हरियाणा विधान सभा

की

कार्यवाही '

20 जनवरी, 1976

खण्ड 1, अंक 7

अधिकृत विवरण

विषय–सूची

मंगलवार, 20 जनवरी, 1976

पृष्ठ संख्या

तारांकित प्रश्न एवं उतर – (7)1

तारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर (7) 7

वर्ष 1976–77 के बजट पर सांमान्य चर्चा (पुनराम्भ) (7)18

औचित्य प्रश्न (7)19

वर्ष 1976–77 के बजट पर सामान्य चर्चा (पुनरारम्भ) (7)20–76

हरियाणा विधान सभा

मंगलवार, 20 जनवरी, 1976

विधान सभा की बैठक, हरियाणा विधान सभा हाल, विधान भवन,

सैक्टर– 1, चंडीगढ़ में 14.00 बजे हुई ।

अध्यक्ष (चौधरी सरूप सिंह) ने अध्यक्षता की ।

तारांकित प्रश्न एवं उत्तर

Mr. Speaker : Question Hour.

तारांकित प्र ० सं० 1410

यह प्रश्न पूछा नहीं गया क्योंकि इस समय माननीय सदस्य, चौधरी राम लाल वधबा, सदन में उपस्थित नहीँ थे ।

तारांकित प्र० सं ० 1438

यह प्रश्न पूछा नहीं गया क्योंकि इस समय माननीय सदस्य, चौधरी दान सिंह, सदन सदन उपस्थित नहीं थे ।

तारांकित प्र० सं० 1468

यह प्रश्न पूछा नहीं गया क्योंकि इस समय माननीय सदस्य, चौधरी देवी लाल, सदन में उपस्थित नहीं थे ।

Repair and Maintenance of Jeeps

***1511. Rao Dalip Singh :** Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) whether any complaint has been received by the Government about the heavy amount spent on the repair and maintenance of the jeeps owned by the Central Co-operative Bank at Mohindergarh; and

(b) if the reply is in the affirmative the action taken thereon?

गृह एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री (श्रीमती शारदा रानी) :

(क) हां जी ।

(ख) परिवाद विभाग में जाँच अधीन है ।

राव दलीप सिंह : क्या मंत्री महोदया बताएंगी कि इस केस की जांच कब तक मुकम्मल हो जाएगी?

श्रीमती शारदा रानी : एक महीने के अन्दर अन्दर हो जाएगी ।

चौधरी शिव राम वर्मा : हरियाणा की और कई जगहों

से ऐसी जो शिकायतें आई हैं । क्या मन्त्री महोदय उनकी भी जाँच करवाएंगे?

श्रीमती शारदा रानी : सवाल तो महेन्द्रगढ़ के बारे में पूछा था, और जगहों के बारे में नहीं पूछा था ।

Mr. Speaker: Order please. I say it is too general a question. It can not be put.

तारांकित प्र० सं ० 1515

यह प्रश्न पूछा नहीं गया क्योंकि इस समय माननीय सदस्य, श्री ओम प्रकाश गर्ग, सदन में उपस्थित नहीं थे ।

तारांकित प्र ० सं ० 1 528

यह प्रश्न पूछा नहीं गया क्योंकि इस समय माननीय सदस्य, चौधरी चांद राम, सदन में उपस्थित नहीं थे ।

Metalled Roads

***1550. Chaudhri Ram Parshad** : Will the Minister for Revenue be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to link the following villages in the Bawal Assembly Constituency with the metalled roads-

1 from Bawal railway to Khori ;

2. from Dharawas to Bhandor ;

3. from Pranpura to Pawati ;

4. from Khori to Harjipur Kundal ;

5. from Bawal to Nangal Babaji ;

6. from Nangali to Khijuri Badoz ;

7. from Raipur to Nangal Babaji ;

8. from Bithwana to Chhuriawas ; and

9. from Asalwas to Kamalpur-lodhana-Pithanwas-Mun- ; danwa and

(b) if so, the time by which the said proposal is likely to be implemented ?

Revenue Minister (Pandit Chiranji Lal Sharma) :

(a) (1) No.

(2) No.

(3) Yes.

(4) No.

(5) Yes.

(6) Yes.

(7) Yes.

(8) Yes.

(9) No.

(b) The completion of roads at Sr. Nos.3 and 5 to 8 depends upon the availability of funds. No. specific date can be given for their completion.

Elections to Gram Panchayats

***1570. Chaudhri Shiv Ram Verma :** Will the Minister for Agriculture be pleased to state whether the elections to the Gram Panchayats are over-due ; if so, since when and the time by which the elections to the Gram Panchayats are likely to be held ?

State Minister for Development and Local Government (Chaudhri Gordhan Dass Chauhan) : The elections to Gram Panchayats are not over-due.

चौधरी शिव राम वर्मा : क्या मन्त्री महोदय बताएंगे कि इलैक्शन की मियाद कब पूरी होने वाली हे?

चोधरी गोवर्धन दास चौहान : दिसम्बर, 1978

तारांकित प्र० सं ० 1411

यह प्रश्न पूछा नहीं गया क्योंकि इस समय माननीय सदस्य चौधरी राम सिह वधवा, सदन में उपस्थित नहीं थे ।

तारांकित प्र० सं ० 1439

यह प्रश्न पूछा नहीं गया क्योंकि इस समय माननीय सदस्य., चौधरी दल सिंह, सदन में उपस्थित नहीं थे ।

Road from Mohindergarh to Village Dulana

***1512. Rao Dalip Singh :** Will the Minister for Revenue be pleased to state—

(a) whether it is in the notice of the Government that the road from Mohindergarh to village Dulana and Bawania has been blocked by the Bundh on the Dohan river ; and

(b) if reply to part (a) above is in the affirmative, the action proposed to be taken by the Government to get the road cleared for traffic ?

Revenue Minister (Pandit Chiranji Lal Sharma):

(a) Yes, Sir.

(b) Action is being taken to open the road.

राव दलीप सिंह : क्या मन्त्री महोदय बताएंगे कि इस सड़क पर बांध की वजह से जो ट्रैफिक रुका हु आ है उसको क्लीयर करने में कितना अर्सा लगेगा?

पंडित चिरंजी लाल शर्मा: स्पीकर साहब, रीसैंट मौनसून में यह बाँध इरीगेशन डिपार्टमैंट ने बनाया और डिस्ट्रिक्ट ग्रिवैंसिज कमेटी में यह मामला 12– 12–75 को डिसकस हुआ था । यह रोड दोहाना रिवर को 250 गज के फासले पर कॉस करती है और म्युनिसिपल रोड को बाईफरकेट करती है । पिछली बारिशों में महकमा नहर ने यह बांध बांधा था ताकि स्पिल ओवर वाटर मेन रोड से महेन्द्रगढ की तरफ न जाये । अब डिप्टी कमिश्नर के साथ हुई मीटिंग में यह फैसला हुआ कि अर्थ–वर्क का जो पोर्शन है वह इरीगेशन वाले कर देंगे और मैटीलंग पी० डबल्यु० डी० वाले कर देगें ।

राव दलीप सिंह : इससे 30–40 गांव खराब होते है । बैलगाड़ी नहीं गुजर सकती, कोई ट्रैफिक किसी किस्म का नहीं जा सकता और सामान भी नहीं जा सकता । इस लिए मन्त्री महोदय इस को कब तक मुकम्मल करवा देगें?

Pandit Chiranji Lal Sharma: As soon as the earth work is done by the Irrigation Department, we will metal it.

राव बंसी सिंह : क्या मन्त्री महोदय बताएंगे कि इस पर अर्थ–वर्क आरम्भ कर दिया है या नहीं अगर नहीं किया तो कब तक आरम्भ कर देगें?

पंडित चिरंजी लाल शर्मा : यह मामला 12– 12– 75 को डिस्ट्रिक्ट ग्रिवैंसिज कमेटी में डिसकस हुआ था कि अर्थ–वर्क शुरू कर दिया जाए इसके बारे मैं नहीं कह सकता कि आरम्भ हुआ या नहीं । मैं अपने डिपार्टमैंट की तरफ से कह सकता हूं कि ज्यों ही अर्थ–वर्क कम्पलीट कर देंगे, हम इस रोड पर मैटीलंग कर देंगे ।

श्री अमर सिंह : स्पीकर साहब, इसी तरह से भिवानी से रोहतक जाने वाली रोड और मेहम से रोहतक जाने वाली रोड बीच से टूटी हुई हैं । क्या मन्त्री महोदय बताएंगे कि इन को कब तक ठीक करबा देंगे?

Pandit Chiranji Lal Sharma: Sir, the work is already in progress and with a very good speed and the department is putting best efforts to complete as early as

possible.

राव बंसी सिंह : क्या मन्त्री महोदय बताने का कष्ट करेंगे कि इस काम को कम्पलीट करवाने के लिए अपना नोट इरीगेशन डिपार्टमैंट को भेजेमें?

Pandit Chiranji Lal Sharma : The matter has already been discussed in the meeting of the Grievances Committee and there is no need of sending any note to this effect.

राव दलीप सिंह : 40 गावों की तकलीफ को ध्यान में रखते हुए क्या मन्त्री महोदय इस काम को जल्दी से जल्दी निपटाने की कोशिश करेंगे?

Pandit Chiranji Lal Sharma: Certainly the Government would consider the desirability of completing it as early as possible.

चौधरी पीर चन्द : स्पीकर साहब, इसी तरह सैलाट सड़क टूटी हुई है, और नरवाना से कैथल के बीच की सड़क भी टूटी हुई है । इस पर काम चालू भी है । क्या मन्त्री महोदय बताएंगे कि यह काम कब तक कम्पलीट करवा देंगे?

पंडित चिरंजी लाल शर्मा: जिन सड्कों पर काम चालू है उन को जल्दी से जल्दी कम्पलीट करवाने की कोशिश करेंगे ।

चौधरी फूल सिंह कटारिया: झझर तहसील में बहुत फ्लड आते हैं और फ्लड की वजह से वहां कई सड़कें खराब हैं ।

क्या मंत्री महोदय उन को जल्दी से जल्दी ठीक करवाएगे?

Pandit Chiranji Lal Sharma: I have already issued instructions for repair of these roads.

श्री के ० एन ० गुलाटी : क्या मन्त्री महोदय बताएंये कि फरीदाबाद और बल्लबगढ़ के गावों को शहर से मिलाने के लिए लिंक रोडज बनाने की तरफ ध्यान देंगे?

Pandit Chiranji Lal Sharma : It all depends upon the availability of funds.

Procurement of Wheat

***1516. Shri Om Parkash Garg :** Will the Minister for Excise and Taxation be pleased to state—

(a) the total quantity of wheat procured by the Government in the State of Haryana during the year 1975; and

(b) the target fixed by the Government for the procurement of wheat during the year 1975?

आबकारी तथा कराधान मंत्री (श्री श्याम चन्द) :

(क) 1— 4—75 से 31— 12— 75 तक 4.33 लाख टनी गेहूं खरीद की गई ।

(ख) भारत सरकार ने 75—76 मात्र के लिए गेहूं खरीद का लक्ष्य सात लाख टनी रखा है ।

तारांकित प्र० सं० 1529

यह प्रश्न पूछा नहीं गया क्योंकि इस समय माननीय सदस्य, चौधरी चांद राम, सदन में उपस्थित नही थे ।

Rooms for Government Girls High School Bawal

***1551. Chaudhri Ram Parshad :** Will the Minister for Education be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to construct more rooms for Government Girls High School Bawal ; if so, the time by which these are likely to be constructed?

शिक्षा एवं परिवहन राज्य मंत्री (श्रीमती प्रसन्नी देवी) :

(क) नहीं ।

(ख) प्रश्न नही उठता ।

Mr. Speaker : Question hour is over.

तारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर

Permanent and Temporay J.B. T. Teachers in the State

***1410. Chaudhri Ram Lal :** Will the Minister for Education be pleased to state—

(a) the total number of permanent and temporary J.B.T. teachers in the State, to date, separately ;

(b) the total number of permanent and temporary B.Ed. teachers in the service of Education

Department/Schools in the State, separately ; and

(c) the total number of posts of the J.B.T. and B.Ed. teachers, if any, lying vacant in the Education Department/Schools in the State?

(b) the number of applications received during the year 1974-75 for the grant of old age pension; and

(c) the number and names of persons togetherwith their addresses to whom pension was granted out of the applications referred to in part (b) above?

शिक्षा मंत्री (श्री माडू सिंह मलिक) :

(ए) जे०बी०टी०टीचर		स्थाई	अस्थाई (तदर्थ तथा स्टाइपैण्डरी सहित)
		16569	12421
(बी) बी० एड० टीचर		4440	5214
(सी) रिक्त स्थान	जे० बी० टी ०	740	
	बी० एड०	50	

Beneficiaries Under the old age Pension Scheme.

***1438. Chaudhri Dal Singh :** Will the Minister for Excise and Taxation be pleased to state—

(a) the total number of beneficiaries under the Old Age Pension, Scheme as on 31,3.1974 and 31.3.1975,

separately ;

(b) the number of applications received during the year 1974-75 for the grant of old age pension; and

(c) the number and names of persons togetherwith their addresses to whom pension was granted out of the applications referred to in part (b) above?

आबकारी तथा कराधान मंत्री (श्री श्याम चन्द) :

(क) 31—3—74 5458

31—3—75 6090

(ख) 1285

(ग) 495, क्योंकि स्वीकृत आवेदकों के नामों व पतों के बारे सूची बनाने में बहुत समय तथा परिश्रम लगने पर भी इससे कोई लाभ होने की आशा नहीं है, इसलिए जिस भी किसी केस के बारे विशेष सूचना चाहिए, वह दे दी जाएगी ।

Fair Price Shops/Ration Depots in the State

***1468. Chaudhri Devi Lai :** Will the Minister for Excise and Taxation be pleased to state--

(a) the district wise total number of Fair Price Shops/Ration Depots in the villages of the State as on 31.12.1974 separately ;

(b) the district wise total number of Fair Price Shops/Ration Depots opened in the year 1975 (to date) in the

villages of the State, separately ; and

(c) the district wise quantity of Sugar and Cloth distributed from the Fair Price Shops/Ration Depots to the villagers in the year 1975 (to date) as referred to in parts (a) & (b) above together with the requirement of each district separately?

आबकारी तथा कराधान मंत्री (श्री श्याम चन्द) :

(ए, बी तथा सी) सूचना सदन की मेज पर रखी जाती है ।

अनुबन्ध 'एं

हरियाणा राज्य के गांव में जिलावार 31– 12– 74 को कार्य कर रहे उचित मूल्य की दुकानें/राशन डिपोज की संख्या का विवरण : –

क्रमांक	जिले का नाम	31– 12– 74 को देहाती क्षेत्र में कुल चल रहे डिपुओं की सख्या ।	वर्ष 1975 में जो डिपो खोले गये ।
1	अम्बाला	315	
2	करनाल	305	
3	सिरसा	200	

4	गुडगावां	401	
5	कुरुक्षेत्र	270	2
6	हिसार	365	
7	जींद	154	69
8	नारनौल	323	8
9	सोनीपत	316	
10	रोहतक	364	50
11	भिवानी	369	51
	कुल जोड़:–	3382	180

अनुबन्ध 'बी'

जिलेवार चीनी तथा कपड़ा जो वर्ष 1975 में देहाती क्षेत्रों में बांटा गया तथा उनकी वार्षिक आवश्यकता ।

क्रमांक	जिले का नाम	राज्य के देहाती क्षेत्र में जितने टन चीनी बाँटी गई ।	राज्य के देहाती क्षेत्र में कपड़े की जितनी गांठें बांटी गई ।	जिले की वार्षिक कपड़े की अनुमानित आवश्यकता	जिलेवार वार्षिक चीनी की अनुमानित आवश्यकता

1	अम्बाला	3573	1063	कन्ट्रोल कपड़ा	14448
2	भिवानी	3194	901	ऐलोकेशन के अनुसार बांटा	11232
3	गुडगांवा	5272	950	जाता है । इसकी	20064
4	हिसार	4499	679	आवश्यकता का अनुमान लगाना	15072
5	जींद	2791.2	350	कठिन है ।	10764
6	करनाल	4239	710	क्योंकि यह कई	13800
7	करुक्षेत्र	3360.2	562	आधारों पर निर्भर होता है ।	11820
8	नारनौल	3110	1095		10620
9	रोहतक	4833	871		16788
10	सोनीपत	2723	375		8604
11	सिरसा	2403.9	345		7908
	कुल जोड़	39998.3	7901		1,41,120

नोट–(1) एक गांठ में लगभग 1500 मीटर कपड़ा होता है ।

(2) जनवरी, 1975 से अप्रैल 1975 तक चीनी 360 ग्राम, तथा मई, 1975 से जून 1975 तक 400 ग्राम तथा जुलाई 1975 से दिसम्बर 1975 तक 420 ग्राम के हिसाब से प्रति व्यक्ति

प्रति मास बांटी गई ।

Procurement of Rice

***1515. Shri Om Parkash Garg :** Will the Minister for Excise and Taxation be pleased to state —

(a) the total quantity of rice procured by the Government in the State of Haryana during the year 1975; and

(b) the target fixed by the Government for the procurement of rice during the year 1975 ?

आबकारी तथा कराधान मंत्री (श्री श्याम चन्द) :

(ए) 2. 59 लाख टनी दिनांक 5— 1— 1978 तक

(बी) 3 लाख टनी ।

Primary, Middle and High or Higher Secondary Schools

***1528. Chaudhri Chand Ram :** Will the Minister for Education be pleased to state—

(a) the total number of Primary, Middle, High or Higher Secondary Schools opened Constituency-wise since May, 1968; and

(b) whether it is a fact that there are villages in Babain Constituency which have no Primary Schools ?

शिक्षा मंत्री (श्री माडू सिंह मलिक) :

(ए) तथा (बी) सूचना एकत्रित करने में जो समय और परिश्रम लगेगा उससे विशेष लाभ नहीं होगा ।

Drinking Water Supply Schemes In Villages

***1411. Chaudhri Ram Lal :** Will the Chief Minister be pleased to state the districtwise number and names of villages in the State in which the drinking water supply schemes have been implemented during the period from January 1974 to-date, separately?

Local Government Minister (Chaudhri Pokar Ram Godara) : A statement is laid on the table of the House.

Statement

Sr. No.	Name of District		Name of villages	Total No. of villages
1	2		3	4
1	Ambala	1.	Bana Bahadur	25
		2.	Islamnagar	
		3.	Mirjapur	
		4.	Tewar	
		5.	Kotla	
		6.	Chan Chuk	
		7.	Kotla (Raipur Rani)	

		8.	Chandi	
		9.	Harijan Majri	
		10.	Mugal Majra	
		11.	Mianpur	
		12.	Ferozepur	
		13.	Jhangu Majra	
		14.	Kath Majra	
		15.	Majri	
		16.	Jaffarpur Jafri	
		17.	Dera	
		18.	Dharampur	
		19.	Bitna	
		20.	Nanheri	
		21.	Sangoli	
		22.	Toddarpur	
		23.	Naya Gaon	
		24.	Kanguwala	
		25.	Tipra	
2	Bhiwani	1.	Sirsa	24

2. Ganga Modi
3. Muna-wali
4. Godisa
5. Ahmadpur
6. Dorewala
7. Jawa
8. Bi jna
9. Badhwana
10. Changroad
11. Bal-road
12. Kalali
13. Balali
14. Palri
15. Kanwari
16. Gunjar
17. Dhayma
18. Dhamana
19. Bhoj Raj
20. Paposa

		21.	Hazampur	
		22.	Jeeta Kheri	
		23.	Orangnagar	
		24.	Jamalpur	
3	Gurgaon	1.	Aterna Shahbad	30
		2.	Feroze-dehar	
		3.	Damdama	
		4.	Karhari	
		5.	Rajika	
		6.	Punhana	
		7.	Nakanpur	
		8.	Mandi	
		9.	Gandhauri	
		10.	Kherla	
		11.	Behlpa	
		12.	Shejawas	
		13.	Rathoj	
		14.	Dehana	
		15.	Ranika	

		16.	Sagarpur	
		17.	Sunpera	
		18.	Malerna	
		19.	Asauti	
		20.	Jataula	
		21.	Devli	
		22.	Seekri	
		23.	Nangal Jogian	
		24.	Bhinakpur	
		25.	Harphala	
		26.	Mohla	
		27.	Kabulpur	
		28.	Deegh	
		29.	Tatarpur	
		30.	Shahpur Khurd	
4	Hissar	1.	Khabra Kalan	9
		2.	Khabra Khurd	
		3.	Kundul	
		4.	Bhattu	

		5.	Ludesar	
		6.	Nathuseri	
		7.	Bawan	
		8.	Bhattu-Kalan,	
		9.	Kharak Punia	
5	Jind	1.	Majeet Singhpura	5
		2.	Dinod Kalan	
		3.	Dinod Khurd	
		4.	Kakrod	
		5.	Uchana Khurd	
6	Karnal	1.	Sataudi	2
		2.	Kashba	
7	Kurukshetra	1.	Dand	4
		2.	Habri	
		3.	Ismalabad	
		4.	Rahera	
8	Mohindergarh	1.	Kanti	12
		2.	Ladhuwas	

		3.	Dehlawas & Gulabpur	
		4.	Bas & Baturi	
		5.	Basdudha	
		6.	Aulant	
		7.	Nangal	
		8.	Aliwas	
		9.	Dhankia	
		10.	Kutabpur Barog	
		11.	Notana	
		12.	Pota	
9	Rohtak	1.	Jhal	11
		2.	Kosli & Kosli Railway Station	
		3.	Loolah Jat	
		4.	Surheti	
		5.	Birhana Milwan & Birhana Gugnan	
		6.	Anwal	
		7.	Azadnagar	

		8.	Bajidpur Barohar	
		9.	Bajidpur Tapahavely	
		10.	Sudharana	
		11.	Judhi	
		12.	Khanpur Khurd	
		13.	Dhariawas	
		14.	Dhana	
10	Sirsa	1.	Rupana	3
		2.	Rupawas	
		3.	Raipur	
11	Sonepat		Nil	
			Total :	128

Irrigation Projects

***1439. Chaudhri Dal Singh :** Will the Chief Minister be pleased to State—

(a) the total amount spent so far on the following canal system :

(i) Indira Gandhi Canal;

(ii) Birendera Narain Chakravarty Canal Project;

(iii) Jawahar Lal Nehru Canal System; and

(iv) Jui Canal Project;

(b) the total cusecs of water flown in the canals as referred to in part (a) above duriug the year 1974-75; and

(c) the total area irrigated by the Canals as referred to in part (a) above during the year 1974-75 ?

मुख्य मंत्री (श्री बनारसी दास गुप्त) :

(क), (ख) ,तथा (ग) आवश्यक सूचना सदन के पटल पर प्रस्तुत की जाती है

सूचना

(क) निम्नलिखित नहर प्रणाली पर 30—9— 1975 तक किया गया खर्चा इस प्रकार :—

1. इन्दिरा गांधी नहर	रुपये 1518.86 लाख
2. बीरेन्द्र नारायण चक्रवर्ती नहर परियोजना	रुपये 1255. 47 लाख
3 जवाहर लाल नेहरु नहर प्रणाली जिसमें 86.08 लाख रुपये झज्जर उठान सिंचाई योजना जो कि जवाहर लाल नेहरु नहरी योजना का भाग है पर खर्च हुए ।	रुपय 584.22 लाख

4. जूई नहर परियोजना रुपये 492.40 लाख

(ख)

1. इन्दिरा गांधी नहर	27024 क्युसिक्स डेज
2 बीरेन्द्र नारायण चकवर्ती नहर परियोजना ।	18132 क्युसिक्स डेज पैटवार डिस्ट्रीव्यूटरी द्वारा बीरेन्द्र नारायण चक्रवर्ती परियोजना स्टेज I, II व III के लिए चला और 1203 क्युसिक्स डेज बीरेन्द्र नारायण चक्रवर्ती परियोजना की स्टेज–4 के निर्माण हेतु निगाना फीडर द्वारा पानी दिया गया ।
3 जवाहर लाल नेहरु नहर प्रणाली	1510 क्युसिक्स डेज
4 जूई नहर परियोजना	43523 क्युसिक्स डेज

(ग)

क्रमांक	योजना का नाम	1974–75 में सिचित किया गया क्षेत्र (एकड / हेक्टेयर)
1	इन्दिरा गांधी नहर	2454 / 9931
2	बीरेन्द्र नारायण चक्रवर्ती नहर	1540 / 6235

3	झज्जर उठान सिंचाई योजना (जवाहर लाल नेहरु उठान सिंचाई योजना का भाग)	1202 / 489
4	जूई नहर परियोजना	14512 / 5873

Fee Concession to Scheduled Castes

***1529. Chaudhri Chand Ran :** Will the Minister for Education be pleased to state—

(a) whether children of all members of Scheduled Castes studying in Schools in the State arc entitled to fee-concession from the primary stage onwards irrespective of income or whether income certificates are required to avail of the fee-concessions and, if so, from which authorities the income certificates are to be obtained;

(b) whether arrangements have been made for disbursement of stipends/scholarships month wise;

(c) the details of any other concessions those are given to members of Scheduled Castes Backward Classes respectively, to promote education amongst them; and

(d) whether Government proposes to take special steps to promote education amongst 'Balmikis' (Bhangis) and families belonging to Scheduled Castes ?

शिक्षा मंत्री (श्री माडु सिंह मलिक) :

(क) जी हां । अतः आय प्रमाण–पत्र देने का प्रश्न नहीं उठता ।

(ख) जी हां ।

(ग) (1) नौवीं दसवीं तथा ग्यारहवीं कक्षाओं में पढ़ने. वाली हरिजन छात्राओं को विशेष मैरिट छात्रवृत्तियां देना ।

(2) स्कूल शिक्षा बोर्ड को दिए गए परीक्षा शुल्क की प्रतिपूर्ति करना ।

(3) जे.बीटी./नर्सरी अध्यापक प्रशिक्षण कक्षाओं में प्रवेश हेतु स्थानों का आरक्षण तथा आयु में ढील देना ।

(4) पुस्तक बैंकों द्वारा पुस्तकों की व्यवस्था ।

(5) चुने हुए क्षेत्रों में अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम ।

(घ) नहीं । बाल्मिकी पहले ही 'अनुसूचित जाति' के अन्तर्गत आते हैं ।

वर्ष 1976–77 के बजट पर सामान्य चर्चा(पुनरारम्भ)

श्री गुलाब सिंह जैन (हिसार) : स्पीकर साहब, कल बजट पर चर्चा करते हुए मैंने कुछ बात कही । आज भी कुछ अर्ज करना चाहता हूं। मैं चौधरी शिव राम वर्मा का ध्यान वित्त मन्त्री साहब के भाषण के पृष्ठ 37 की तरफ दिलाना चाहता हूं । इस में उन्होंने कहा कि जो डैफिसिट बजट है उसको पूरा किया जाएगा

और हमारी जो टैक्स की मशीनरी है उसको स्ट्रमिलाईन करके यह डैफिसिट पूरा करेंगे, न कि टैक्स लगा कर । इसके इलावा स्पीकर साहब, मैं विरोधी भाइयों का ध्यान– पंचवर्षीय योजनाओं की तरफ दिलाना चाहूंगा । इन योजनाओं का 75 परसैटं खर्चा उन टैक्सों से मिलता है जिन का सीधा ताल्लुक किसान भाइयों से है और वह इलैक्ट्रिस्ट्रि, इरीगेशन और एग्रीक्ल्चरल डिवैल्पमैंट पर खर्चा हो रहा है । इसके इलावा स्पीकर साहब, एक बात की तरफ आपकी मारफत सदन का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि हमारी स्टेट में हमारे मन्त्रीगण कितने अच्छे तरीके से टैक्सिज की वसूली पर ध्यान दे रहे हैं । हमें एक्साईज एंड टैक्सैशन से और सेल टैक्स से जो रैवैन्यु मिलता है वह 1967–68 में 9 करोड़ 54 लाख था और 1978–77 के अन्दर 52 करोड़, 62 लाख हो गया है । इसके इलावा डायरैक्टटैक्सिज से जिसका सीधा सम्बन्ध अर्बन पापुलेशन से है, 12 करोड, 18 लाख टैक्स मिलता है जबकि लैंड रैवैन्यु से कुल 4 करोड़ 70 लाख टैक्स मिलता है । मैं इन बातों की तरफ उन माननीय सदस्यों का ध्यान दिलाना चाहता हूं जो सरकार का क्रिटिसीजम करते थे ।

इसके अलावा, स्पीकर महोदय, मैं कुछ बातें अपने हल्के के बारे में कहना चाहूंगा ।

Mr. Speaker : Only for five minutes more please.

श्री गुलाब सिंह जैन : सबसे पहले मैं अपिके द्वारा मुख्य मंत्री जी का ध्यान हिसार टैक्सटाइल मिल के लेबर की तरफ

दिलाना चाहता हूं । वह ण्क बहुत बड़ा यूनिट है हिसार का लेकिन इस एमरजैन्सी का नाजायज फायदा उठाते हुए वहां की मैनेज– मैट लेबर के साथ काफी दु:ख भरा व्यवहार कर रही है । डसके बारे में मैंने पस भी सरकार को लिखा था । लेबर की रिप्रैजैन्टेशन भी भेजी थी लेकिन मुझे आज तक जबाब नहीं मिला कि उस पर क्या कार्यवाही हई । मैं मुख्य मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि वे मुकामी अफसरान को ताकीद करें और श्रम विभाग से कहें कि लेबर के साथ हमदर्दी के साथ पेश आया जाए ।

औचित्य प्रश्न

Chaudhri Partap Singh Daulata : On a point of Procedure, Sir, I would like a Ruling from the Chair. Can another Member discuss the political or social integrity of another Member while speaking in general discussion on the Budget. If not, I have come to know that an hon. Member has talked much on my political and social integrity, that be expunged from the record if it is without Rules. This is least. I do not want to put myself in controversy and lower down the standard of the debate in the House.

Mr. Speaker : I will examine the speech of the hon. Member

Chaudhri Partap Singh Daulata : And with your permission I want to bring to your notice that this is a contempt of the House also because this very House had held in the famous case of Hardwari Lal which is being argued there that if Member's integrity is criticised by someone then

he is guilty of contempt of the House . Can a man, who cannot speak on member's integrity otherwise, speak because he happens to be a Legislator.. ..

Mr. Speaker : The Rules of the House are very clear on this matter. There should be no personal charge against any Member....

Chaudhri Partap Singh Daulata : And if your honour finds that they are without Rules, kindly expunge them, This is what my submission is.

वर्ष 1976–77 के बजट पर सामान्य चर्चा (पुनरारम्भ)

श्री गुलाब सिंह जैन : स्पीकर साहब, मैं आपके द्वारा सरकार का ध्यान अपने हल्के के एक देहात की वाटर सप्लाई स्कीम की तरफ दिलाना चाहता हूं । गंगवा गांव के पास अभी सरकार ने अपना एक सिविर कंप्लैक्स बनाया हे । कुछ सरकारी क्वाटर्ज बनाए हैं, नई होस्टल बिल्डिग भी बनाई है । वहां से गांव की आबादी कोई आधा मील रह जाती है । वे लोग बहुत महसूस करते हैं जब वे देखते है कि इनके पास तो वाटर सप्लाई स्कीम है लेकिन उनको पीने का पानी भी नहीं मिलता । मैं सरकार से प्रार्थना करूंगा कि हिसार वाटर सप्लाई स्कीम से जिस तरह सरकारी क्वाटर्ज को पानी दिया जाता है उसी तरह उससे आस पास के दो चार गांव को भी पानी दे दिया जाए । आज गंगवा गांव में सिर्फ एक कुआं है । बाकी का सब–सवायल वाटर खारी है । तलवंडी राणा की भी यही पोजीशन है । वहां अभी

कंसोलीडेशन नहीं हुई है। इनके पास जमीन भी नहीं है जो वह वाटर वर्कस के लिए दें । इनके कुछ पर भी अगर मोटर लगवा दी जाए तो काफी सहूलियत उन्हें भी हो जाएगी क्योंकि सब–सवायल वाटर वहां भी खारी है । तीसरी बात. स्पीकर सहाब, मैं आपके द्वारा जो अर्ज करना चाहता हूं वह यह है कि दिसम्बर 1973 में हिसार में तुक कान्फ्रैन्स में हमारे ऐक्स चीफ मिनिस्टर चौधरी बंसी लाल जी ने यह एलान किया था कि न्यौली और शाहपुर गांव के लिए जिनका आपस में दो किलोमीटर का फासला है शाहपुर में एक स्कूल खोल दिया जाए और न्यौली के बच्चे वहां चले जाया करें । आज न्यौली के बच्चे वहां जाने में दिक्कत महसूस करते हैं । मैं समझता हू कि अगर बीच के दो किलोमीटर सड़क के कच्चे टुकड़े को पक्का करदिया जाए तो बच्चे साईकल पर आसानी से जा सकते हैं । तो मैं अपने पी० डबल्यू ० डी ० मिनिस्टर साहब से प्रार्थना करूंगा कि उस दो किलोमीटर के छोटे से टुकड़े को जल्दी से जल्दी मुकम्मल करवाने की कृपा करें ।

इसके बाद, स्पीकर साहब, मैं हिसार शहर की तरफ मुख्य मन्त्री जी का ध्यान दिलाना चाहूंगा । वहां पर आज जो बस अड्डा बना हुआ है उसके पास काफी दुकानें लीज पर थीं जिनको गिरवा दिया गया । उनको इस बात के लिए गिरवाया गया कि अड्डे को बड़ा कर दिया जाएगा लेकिन इस बजट में उस बात के लिए कोई प्रोविजन नहीं किया गया है । इसलिए मेरी प्रार्थना है कि कम से कम उन दुकानदारों को बसाने के लिए किसी

आल्टरनेट जगह का जल्दी से इन्तजाम किया जाए इसी तरह से वैस्टर्न जमुना की कुछ जमीन लीज आउट करके दुकानदारों को दी हुई थी लेकिन उनकों भी वहां से उठा दिया गया था । उसके बारे में भी मैं मुख्य मंत्री जी से अर्थ करना चाहता हूं कि वैस्टर्न जमुना को जो लैंड है वह इम्प्रूवमैटं ट्रस्ट को ट्रासफर कर दी जाए या कोई दूसरी योजना बना कर उन दुकान– दारों को दी जाए ताकि वहां पर मार्किट बनाई जौ सके और जिन दुकानदारों को उजाडा गया है उनको जल्दी से रीहैबलीटेट कर दिया जाए । इन कामों पर जल्दी से ध्यान दिया जाए यह आपके द्वारा, स्पीकर साहब, मेरी सरकार से प्रार्थना है । शुक्रिया ।

चौधरी मेहर चन्द (बडोपल) : स्पीकर साहब, कल से अगले साल के बजट के ऊपर बहस हो रही है । मैं तो यह कहूंगा कि समूचे तौर पर बजट जो पेश किया गया है यह एक प्रोग्रेसिव बजट है । अच्छे कामों के लिए इसमें प्रोविजन रखा गया है । मिसाल के तौर पर ऐलोपैथिक डिसपैन्सरीज और बनेंगी उसका प्रोविजन बजट में है । यह हैल्थ प्वांयट आफ व्यू से बहुत अच्छा है । इसके अलावा इरीगेशन एंड पावर डिपार्टमैंट के लिए ज्यादा प्रोविजन किया गया है । इस साल तो 52 करोड़ 69 लाख रुपये का बजट है इन दोनों इरीगेशन एंड पावर के लिए लेकिन अगले साल के लिए 72 करोड़ 53 लाख रुपये का प्रोविजन है । यह कोई कम प्रोविजन नहीं है । कल बजट के ऊपर बहस करते हुए मेंरे एक मोहतरिम दोस्त ने एक बात कही व्यास और रावी के

वाटर के बारे में कि पता नहीं यह ख्वाब कब पूरा होगा । मैं यह मानता हुं कि पिछले साल यह बात क्लीयर नहीं की गई थी लेकिन इस साल यह बात बिल्कुल साफ की गई है बजट स्पीच में और मेरा ख्याल है गवर्नमैटं ने सारी बात दिल खोलकर बताई है । कहा गया है कि–

We hope that the final decision of the Government of India would be intimated in the near future...."

नीयर फ्यूचर यह जाहिर करता है कि हमें ज्यादा पानी जल्दी से जल्दी मिलना है । इसके अलावा एक बात और कही गई है

. .. With that expectation, we have provided Rs. one crore for this scheme in 1976-77...."

इससे साफ है कि खर्चा ज्यादा होगा लेकिन इस बात का शक मिटाने के लिए एक करोड से काम नहीं चले गा गवर्नमैंट ने आगे यह भी कहा है कि

It would be our effort to increase the outlay on the Sutlej Yamuna Link Scheme in 1976-77 so that the works can be completed in the shortest possible time, enabling the farmers of the State to utilize the additional water at the earliest

इससे फालतू गवर्नमैंट क्या कहे? वह तो बड़ी मिसलीडिंग बात थी, जनता को गुमराह करने बाली बात थी कि

इस तरफ गवर्नमैंट का कम ध्यान है । मैं कह सकता हूं इस कि तरफ गवर्नमैंट का बहुत ध्यान है । मैं थौडी देर बाद जो चीफ मिनिस्टर साहब हाल में अनाउसमैंट्स करते रहे उनकी तरफ भी आऊंगा । इसके अलावा, स्पीकर साहब, इस बजट के अन्दर फतेहबाद ब्रांच की लाईनिंग का जिक्र है । यह सबसे बड़ी लाइन्ड चौनल है । मैं तो कहूंगा कि गवर्न मैट का यह सबसे बडा काबिले तारीफ वर्क है । इस की लाईनिग का काम अभी शुरू करना है । स्पीकर साहब इसकी लाईनिग के बाद चार सौ क्युसिक पानी की बचत होगी । चार सौ क्युसिक पानी की बचत कोई थोडी नहीं है । इस नहर की कैपेसिटी मामूली सी यदि और बढ़ जाए तो जूई कैनाल के बराबर ही हो जाए । ऐसा करने से एक लाख एकड़ अडीशनल एरिया की आबपाशी होगी ।

इसके अलावा नागल लिपट इरीगेशन स्कीम का भी जिक्र है । हमारा अम्बाला जिला अभी तक नहर से खाली था । मैं इस बारे में गवर्नमेट की तारीफ किए बगैर नहीं रह सकता । उसको अम्बाला जि ले का भी ध्यान तो आया । यह तो मैं समझता हू कि जिस जगह पर नहर बनेगी उस जगह का स्टेट मिनिस्टर भी है । मैं तो उस मिनिस्टर साहब को भी दाद देता हूं । आखिर ये आदमी उठे तो हैं । अम्बाला जिला कोई गैर बना नहीं है । यह भी हरियाणा का ही है ।

मैं दो लफज फा इनैन्स मिनिस्टर साहब के बारे में भी कहे बगैर नहीं रह सकता । मुझे तो उनके बारे में जरूर कहना

पड़ेगा क्योंकि यह बजट ही इस किस्म का है ।

तेरे बजट में रवानी है

तेरी हर अदा लासानी है ।

इसके अलावा यह भी कहूंगा कि उम्र की बात कोई क्यों करे । उम्र की बात क्यों करे कोई, किसी की पीरी में जवानी है । (तालियां) यह बजट बहुत अच्छा बजट है । हाल ही में हुमारे मु ख्य मन्त्री जी ने बार–बार कहा है कि किसान मजदूर की तरफ खास तौर पर तवज्जुह दी जाएगी, भावों का स्तर ठीक किया जाएगा ताकि किसानों की माली हालत कमजोर न रहे । मैं इस वक्त दावे के साथ कह सकत हूं, इस साल की कह सकता हूं पिछले साल की नहीं, किसानों की माली हालत कमजोर है । उन्होने यहाँ हाउस में कहा है कि सूखी भूमि के लिए सिंचाई का इन्तजाम किया जाएगा । उन्होंने यह भी कहा कि वाटर अलाउन्स भी बढ़ाया जाएगा । काश ये भलाई की बातें मुख्य मन्त्री की जबानी की बजाए अगर बजट में लिख दी जाती तो सारे शकूक ही मिट जाते । इस बजट में यह कमी रही है कि मुख्य मन्त्री जी ने जो बातें कही हों उनका बजट में रिफलैक्शन जरूर होना चाहिए ।

इसके अलावा किसानों की कई बातों को मानता हूं । किसानों के बारे में बार–वार ये कहते हैं कि खेती की उपज बढ़ा है । इसमें कोई दो राय नहीं हैं, उपज बढ़ी है । किसान यह भी कहता है कि सिंचाई के साधन बढे हैं और बढ़ते जा रहे हैं ।

किसान यह भी कहता है कि बिजली की जनरेशन हुई है और ज्यादा हो रही है । खाद आया है लेकिन साथ ही यह भी कहता हूं कि वह मंहगा मिला है । यह उसके दिल की बात है । खाद के मंहगे होने से उसको दिक्कत है । ये सब बातें मैं आगे आंकड़ों से साबित करूंगा । यह आगे बताऊंगा कि खाद के भाव कहां से कहां चले गए । एक बात किसान भी मानता है, मैं भी हरियाणा गवर्नमैंट की तारीफ करता हूं पिछले मुख्य मन्त्री जी की भी करता हूं और मौजूदा कैबेनिट की भी तारीफ करता हूं क्योंकि इसमें कोई खास तबदीली नहीं हुई है, कैबेनिट वही है, मुख्य मन्त्री जी भी अच्छे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, हम बैकवर्ड नहीं जाएंगे, फारवर्ड ही जाएंगे, हरियाणा के अन्दर पांच साल के अन्दर कोई कहत नहीं पड़ा हैं । किसी भी इलाके में कहत नहीं पड़ा है, किसान इस बात को मानता है । कहतसाली दिन पर दिन कम होती जा रही है । यह भी मैं मानता हूं कि कर्जे की सहूलियतें देते हैं लेकिन फिर भी किसान यह क्यों कहता है ।

हजूर हजूर में आसूदगी नहीं मिलती ।

तलाश जिसकी है वह जिन्दगी नहीं मिलती ।

वह कहता है कि इस दुनियां के अन्दर भगवान मुझे हमेशा सुख नहीं मिलता । किसान कहता है कि मैं जिस जिन्दगी की तवक्को करता हूं वह नहीं मिलती है । आखिर कोई वजह तो है । वह वजह क्या है? एक हो वजह है, अगर उसको 'ठीक कर

दिया जाए तो मैं यह कहू सकता हूं कि हरियाणा का किसान मौजूदा गवर्नमैंट को यह कहेगा कि यही गवर्नमैंट रहनी चाहिए, दूसरी गवर्नमैंट नहीं आनी चाहिए और वह बात हो सकती है लेकिन रफ्ता रफ्ता हो सकती है । वह बात क्या हैं? वह है कोस्ट आफ प्रोडक्शन बढ़े । इस बात को कोई इन्कार नहीं कर सकता कि किसान की प्रोडैक्शन के भाव नहीं गिरे हैं । कोई इस बात को चौलेंज तो करे कि नहर का आबयाना ज्यादा हो गया हैं, जमीन का मालिया ज्यादा हो गया, ऐग्रीकल्चर इन–पुट्स की, इक्वीपमैंट्स की कीमतें ज्यादा हो गई और कपड़ा, जूती मंहगे हो गए हैं लेकिन दूसरी तरफ कपास के भाव नीचे चले गए हैं । कपड़े के भाव में दो आने भी कम नहीं किए । किसान कपड़ा किस पैसे से खरीदेगा? आखिर एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन को ही बेच कर किसान अपना गुजारा करता है, पेट पालता है । किसान जूती, कपड़ा कहां से खरीदता है, वह इसी प्रोडक्शन को बेच कर खरीदता है ।

श्री अध्यक्ष : बोलने वाले मैम्बरान ज्यादा हैं । हाउस की सैंस हो तो कोई टाईम लिमिट फिक्स कर दी जाए । दस दस मिनट से कोई ज्यादा मैम्बर न बोले तभी काम चलेगा । (व्यवधान) अब तक बहुत थोड़े मैम्बर बोले हैं और टाईम ज्यादा लग गया ।

चौधरी मेहर चन्द : स्पीकर साहब मुझे कितना टाईम मिलेगा ताकि मैं खत्म करूं । मैंने अपने मन की बातें तो सारी

कहनी है । जितना और टाईम बाकी है उसमें एकाध मिनट की और गुंजाइश कर दें ।

श्री अध्यक्ष : आप वाइंड अप करें ।.

चौधरी मेहर चन्द : स्पीकर साहब अभी से वाइंड अप करूं? स्पीकर साहब आपका आर्डर फाईनल होता है लेकिन मैं दो चार बातें और कहना चाहता हूं । खाद के भाव बढ़े हैं । पइर्ने पचास किलोग्राम का बैग 30 रुपए का आता था लेकिन अब 56 रुपए का है । इस कीमत को वह कहां से पूरी करेगा जबकि जिन्स के भाव वही हैं । इसी तरह से यूरिया का बैग 35 रुपए का आता था अब 65 रुपए का आता है । डी ० ए ० पी ० 65 रुपए का पहले आता था लेकिन अब वह 98 रुपए के करीब आता हए । इस लिए मैं खाद की बात कहने के लिए तैयार हू कि खाद के भाव बढे हैं और करीब–करीब डबल हो गए हैं । इस बात को कोई कह नहीं सकता कि डबल नहीं हुए हैं । जो आदमी यह कहता है कि डबल नहीं हुए हैं उसके बारे में मैं कह सकता हूं कि उसको किसान के साथ कोई हमदर्दी नहीं है ।

इसके अलावा आग देखें ट्रैक्टर की कीमत कहीं से कहीं चली गई है जो मीडियम साईज का ट्रैक्टर है उसकी पहले कीमत 37 हजार रुपए थी लेकिन अब 38 हजार रुपए है । किसान के छोटे औजार हैं जैसे हल है, कस्सी है, फाली है, हैरों है कल्टीवेटर है, इन सब औजारों के भाव बढ़े हैं । अब जिन्स की

कीमतें देखिए, किसी के भाव नहीं बढ़े है । जो पहले 125 रुपए था आज उसका भाव 60 रुपए है, इस साल दो बाते हो गई । एक तो उपज कम है । मैं सारे हरियाणा की बात नही कह रहा हूं । कुछ इलाकों में उपज ठीक है मसलन कुरूक्षेत्र और करनाल में । सोनीपत एरिया में भी ठीक है । मैं यह कह सकता हू कि हिसार, भिवानी और सिरसा में कपास की उपज भी कम हुई है और जिन्स की उपज भी कम ही होगी और भाव आधे हो गए हैं । बाजरा कहां पहले 200–210 था लेकिन आज 75 रुपए क्विटल बिका और उसको कोई पूछता भी नहीं है । गवार कहां 235 रुपए थी और कहां आज भाव 75 रुपए है । इसी तरह से जो देसी कपास है, उसका जो पर–क्विंटल भाव पहले था वह तीन सौ–तीन सौ तीस के लगभग था जो अब 173 और 200 के दरम्यान है । नर्मा का भाव जो 400 को टच कर चुका था आज उसे अढाई सौ में भी कोई नही पूछता । इन चीजों को मद्दे नजर रखते हुए किसान का ख्याल किया जाग्र । शूगर केन की बात यहां आयी, उसके बारे में तो मेरी तसल्ली है लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि 11 रुपए का भाव कम है । पंजाब और हरियाणा में कोई फर्क नहीं होना चाहिए क्योंकि अगर एकचुअली देखा जाए तो हरियाणा तो अब बन गया और एक बाउडरी खिंच गयी वरना पहले तो पंजाब और हरियाणा एक ही थे । वहां के भाव में और यहां के भाव में फर्क क्यों हो? वहां 14.35 रुपए है और हरियाणा में 11 रुपए का भाव क्यों है जबकि हरियाणा भी पंजाब का एक भाग है । (घंटी) स्पीकर साहब, आप कृपा करके थोड़ा–सा टाईम

और देने की मेहरबानी कर दें । मैं जल्दी ही वाइन्ड अप कर रहा हू । मैं यब कुछ छोड़ कर आखिरी बात पर आ जाता हूं । मेरे कुछ सुजैशन्ज हैं । मुजैशन्ज कहने के लिए तो मुझे टाईम देना चाहिए । मैं दों–तीन मिनट में यह कह देता हूं । मैं यह फील करता हू और यहां पर एक्सपैडीचर कम होने का जिक्र भी बजट में आया है, यह एक अच्छी बात है । यहां तक तो मैं इसकी तारीफ करता दर । इन्होंने एक पैरा लिखा है Austerity in Government expenditure लेकिन इस पैरे पर मैं यह कह सकता हू कि जो 20 प्वायंट प्रोग्राम हए, उसमें यह चीज आयी है कि strict economy in Governmnet expendiure स्ट्रिक्ट इकोनोमी करने के लिए मैं यह सुझाव गवर्नमैंट को दूंगा कि एक इकोनोमिक कमेटी सैट–अप की जाए और उस इकोनोमी कमेटी में नान–आफीशीयल्ज हों जिनको कि गवर्नमैंट की वर्किंग का कुछ पता हो ताकि वे बाल की खाल उतार सकें । वह यह भी कहेंगे कि आफिसर यह बात गलत कहते हैं । वे कई दफा मिसलीड कर देते हैं कि हमने यह कर दिया वह कर दिया । आप यह जानते हैं कि आफिसर तो जबाब देने में बड़े चुस्त होते हैं वह तो किसी के पंजे नहीं लगने देते । उस कमेटी में कोई अगर ऐसा आदमी हो जो यह कहे कि हमें भी इसका पता है, हम भी इन्हीं गलियों में घूमे हैं, तो वह उनको जबाब दे सकता है इस वास्ते मेरी यह प्रोपोजल है कि एक इकोनोमी कमेटी सैट–अप होनी चाहिए । कैनाल सरकल्ज जो हैं वे बड़े अनवील्डी हैं । मिसाल के तौर पर हिसार का जो भाखडा कैनाल का सरकल है वह तो बहुत ही

अनवील्डी है । उसका 20 लाख एकड़ सी०सी०ए० है जो कि एक एस ई० के लिए अनमैनेजेबल है । मेरी यह प्रोपोजल है कि एक कैनाल सरकल में 5–6 लाख एकड़ सी०सी०ए० से फालतू नहीं होना चाहिए, डिवीजन डेढ लाख एकड़ के करीब होना चाहिए और एस०डी०ओ० का एरिया 40–50 हजार एकड़ से फालतू नहीं होना चाहिए । मैं यह क्यों कहता हूं? मैं इसलिए कहता हू ताकि किसान को जल्दी इन्साफ मिले और जो सुपरवीजन हो, वह भी ठीक हो सके । पीने के पानी की बात भी मैं कहूगा । पीने का पानी जिन्दगी के लिए एक अहम चीज है । अगर हम पीने का पानो भी जल्दी न दे पाएं तो हम क्या करेंगे जबकि हम डिवैल्पमैंट की बात करते हैं । डिवैल्पमैंट हुई है, कोई भी आदमी इस बात को चौलेंज नहीं कर सकता और अगर कोई खामखाह कहे तो उसका कोई इलाज नहीं । हमने पीने का पानी दिया है लेकिन इस बजट में जो पीने के पानी के लिए प्रोवीजन किया गया है, वह मोस्ट इन्एडीक्वेट है । मैं यह सुझाव दूंगा कि इसमें कुछ और ज्यादा प्रोवीजन होना चाहिए । (घंटी) स्पीकर साहब, एक मिनट और । अपग्रेडिंग आफ स्क्ल्क मेरे ख्याल में मुद्दतों से बन्द है । इस तरफ भी कुछ ध्यान हो जाना चाहिए । देहात के लोग यह कहने लगे हैं कि इस गवर्नमैंट को हो क्या गया जो इतने साल से अपग्रेडिंग बन्द है । चेन्ज इन सिस्टम ऑफ एजुकेशन भी रिक्वायर्ड है । एक नान–अफिशियल रैजोल्यूशन जो अभी हाउस के सामने है और कन्टीन्यू करेगा, उस पर बोलते हुए मैं बोलूंगा कि इसमें क्या कमी है और चेन्ज इन सिस्टम आफ एजुकेशन क्या

होनी चाहिए । इसके अलावा किसान के लिए कैनाल क्लोकर्ज जिन्दगी और मौत का सवाल है जो एट रेन्डम होते हैं । आवकल भी हैं और फतेहाबाद कैनाल में हो रहे हैं । एक हफते से दस दिन तक का तो बर्दाशत हो सकता है लेकिन अगर 15 दिन या 20 दिन का हो जाए तो उससे तो जो कुछ जड़ें खड़ी हैं, वे भी खत्म हो जाएगी । फरवरी और मार्च के महीने में कैनाल क्लोजर्ज बिल्कुल ही नहीं होनी चाहिए वरना तो जो दाने होने है, वे भी नहीं होंगे क्योंकि बारिश का तो कुछ ऐसा ही हाल मालूम देता है । (घंटी) मेरे ख्याल में तो मैं अब बैठ ही जाऊं । क्यों बेइज्जती कराऊं?

श्री जगजीत सिंह टिकका (नारायणगढ) : स्पीकर साहब, आपने मुझे बोलने के लिये टाईम दिया, शुक्रिया । करन भी मैं खड़ा हुआ था । टाईम बहुत थोड़ा मिला है इस वास्ते मैं ज्यादा कुछ तो ऐक्सप्लेन नहीं करूंगा लेकिन जो थोड़ा बहुत हो सक्एगा, वह मैं कहूंगा । मैं यह कहना चाहुंगा कि बजट के मुताल्लिक हाउस में बहस हो रही है और इसके बारे में हमारे माननीय सदस्य चौधरी मेहर चन्द जी ने जो यह कहा कि काफी अच्छा बजट हमारे फाइनैसं मिनिस्टर साहब लाये हैं, यह ठीक है । कहने वाले यह जरूर कहेंगे और कहते भी हैं कि इसमें तो 16 करोड़ 30 लाख नहीं 19.48 करोड़ का घाटा है? यह घाटा अगर देखा जाए तो 16 करोड़ 30 लाख का था लेकिन 3 करोड़ 18 लाख रुपया स्टेट के एम्पलाइज को दिया गया है । इसमें अगर

और गहरा जा कर देखा जाए तो 8.92 करोड़ रुपया पिछले साल का घाटा है और इस साल जो खालिस घाटा है जिसमें वह पैसा भी मिला लिया जाये जो स्टेट के एम्पलाइज को दिया है तो 10. 56 करोड़ का घाटा है । कहने को तो यह बात कही जा सकती है कि इतना घाटा है लेकिन यह कोई खास बात नहीं । इतने बड़े बजट में 10 करोड़ का घाटा पूरा हो सकता है क्योंकि आमदनी और ज्यादा आ सकती है । यह कोई खास बात नहीं है । लेकिन जो ऐक्सपैडीचर प्रोपोज किया गया है, वह देखने के बाद कोई भी आदमी यह नहीं कह सकता कि इसमें कोई गलत चीज कर दी गयी है क्योंकि इसको देखने से मालूम पड़ता है कि जो मेजर ऐक्सपैडीचर है, वह तो बहुत जरूरी चीजों पर ही खत्म हो जाता है । मिसाल के तौर पर इरीगेशन है, पावर है, और इरीगेशन एरण्ड पावर तो बजट का काफी बड़ा हिस्सा ले जाता है, फिर ऐप्रीकल्चर, हैल्थ, पब्लिक हैल्थ एण्ड ऐजुकेशन । अगर इन चीजों के खर्चे को निकाल दें तो फिर बाकी कुछ भी नहीं रहता । इसलिये यह वे चीजें हैं, जिनके ऊपर सरकार खर्च करती जा रही है और उससे किसी को गिला नहीं होना चाहिए । आजकल जैसै कि सब कहते हैं कि ऐमरजैसी है । मैं यह कहता हूं कि यह ऐमरजैन्सी नहीं बल्कि डिस्पिलन का डरा चल रहा है । कम अज कम अब पहले की तरह तो नहीं है कि चाहे कोई बात सच्ची है या झूठी है, जो मर्जी कहते चले जाओ और किसी को बदनाम करते चले जाओ । यह बात अब नहीं है । हमारे जो पहले मुख्य मंत्री थे, जिन्होंने आज हरियाणा का नाम रोशन किया है, वे अब

डिफैन्स मिनिस्टर बनकर सैटर में गये हैं । हमें गर्व है और इस बात का फख्र हासिल है कि हरियाणा के एक ऐसे सपूत को जिन्होंने हरियाणा में तो काम किया ही, अब सारे हिन्दुस्तान के लिये काम करने का मौका मिला है । मुझे तो जरा भी शक नहीं है कि जैसा नाम उन्होंने यहां कमाया है, वह इससे भी ज्यादा अच्छा नाम सारे भारतवर्ष में कमायेंगे । हमारे जो मौजूदा मुख्य मंत्री जी अब आये हैं, ये भी उन्हीं के नक्शे–कदम पर चल रहे हैं । यह बात पहले भी कही जा चुकी है कि कैबिनैट में चेन्ज तो कोई आयी नहीं है, वही पार्टी है, वही मंत्री है सिर्फ मुख्य मंत्री जी जो पहले मंत्री थे, नये बने हैं । उनमें पहले की तरह ही स्पिरिट है और उसी से वह चल रहे हैं और चलेंगे । मुझे आशा है कि उसी तरह से काम करके दिखा कर अपना नाम ज्यादा से ज्यादा ऊँचा करेंगे । सबसे बड़ा काम तो प्राईम मिनिस्टर का है क्योंकि उन्होंने हरियाणा के सिर पर हाथ रखा हुआ है ।

एमरजैन्सी आने के बाद प्राइसिज काफी नीचे आ गयी हैं । इससे लोगों को एक राहत सी महसूस हो रही है । आज कहीं चले जाओ किसी चीज की दिक्कत नहीं है । पहले चीजों की सकेरसिटी की वजह से बहुत दिक्कत होती थी । पहले जिन चीजों की दिक्कत होती थी, आज उनकी दिक्कत नहीं है, वे आसानी से मिल जाती हैं । सीमेन्ट के लिए मारपीट, लड़ाई और इतनी ब्लैक चलती थी लेकिन आज कोई सीमेन्ट को पूछता नहीं है । यह सारा ऐमरजैन्सी की वजह से है । अभी चौधरी मेहर चन्द

ने कहा कि ऐग्रीकल्चर प्रोड्यूस की जितनी प्राइसिज कम हुई हैं उतनी इन–पुट्स की कीमत कम नहीं हुई है बल्कि वह ज्यादा है । इससे किसानों को काफी तकलीफ होती है । बढ़ौतरी की फिगर्ज मैं दुबारा नहीं पढ़ना चाहता क्योंकि कई मेरे साथियों ने पहले ही इन फिगर्ज की बाबत बता दिया है । टाईम बहुत थोड़ा सा है और इस थोड़े से टाईम में सारी बातें नहीं कही जा सकतीं । किसान के काम आने वाली चीजें जैसे फर्टीलाइजर, सीड, ट्रैक्टर, इम्पलीमैंट्स आदि इनकी कीमत कम होनी चाहिए । मेरी यही प्रार्थना है कि सरकार इस तरफ अवश्य ध्यान दे । यह बात ठीक है कि फर्टीलाइजर की जो कीमत बढ़ाई है वह हमारी सरकार ने नहीं बढ़ाई है बल्कि यह सारी दुंनिया में ही बढ़ी हैं लेकिन मैं चाहता हूं कि जिस तरह पहले सरकार सबसिडी देती थी और कम कीमत रखती थी उसी तरह से सबसिडी देकर अब भी कीमतों पर काबू रखे और कम करे । स्पीकर साहब, बजट के अन्दर सरकार ने अच्छे कामों के लिए पैसा दिया है लेकिन मैं दों–तीन बातों का जिक्र करना चाहता हूं । एक तो फैमिली प्लानिंग है । हरियाणा के अन्दर फैमिली प्लानिंग के लिए बहुत अच्छा काम हुआ है और यह खुशी की बात है कि इस काम में हरियाणा देश में फस्ट आया है । फैमिली प्लानिंग देश के लिए बड़े महत्व की चीज है क्योंकि अगर आबादी इसी तरह से बढ़ती चली गई और पैदावार उस हिसाब से न बढ़ी तो काफी नुक्सान होगा । दूसरे फारेस्ट की बाबत कहना चाहता हूं । अगर आप यहां से दिल्ली जाए तो रास्ते में जो पेड़ू लगे हुए हैं वह काफी सुन्दर लगते हैं । मैं कई दफा

इस रोड से गया हूं और कई बार तो मेरे साथ बाहर के सूबों के आदमी थे । वे सड़क के साथ इन पेड़ों को देखकर बड़े खुश होते थे और कहते थे कि आपके यहां फौरेस्ट और सडकों का बहुत अच्छा काम है ।

स्पीकर साहब, मुझे पता लगा है कि एक ऐसी प्रोपोजल है कि जो सड़क अम्बाला से दिल्ली जाती है इसके एक तरफ के फौरेस्ट को काटकर सडक को चौड़ी किया जातु । मेरी प्रार्थना है कि ऐसी बात नहीं होनी चाहिए । इससे बहुत नुक्सान होगा और इस वक्त जो सुन्दरता है यी भी खत्म हो जाएगी । फौरेस्ट को अगर काटा गया तो हो सकता है कि उस रेंज में लोगों के मकान आ जाए और कुछ सरकारी विल्डिगें भी आ जाएं जैसे कि अम्बाला कैन्ट का बस स्टैन्ड है । इनको गिराने से सरकार का तथा पब्लिक का काफी नुक्सान होगा । अगर सड़क को चौड़ा ही करना है तो ऐसा किया जाहू कि जिस प्रकार चडीगढ में सड़कें बनी हुई हैं । आपने 22 सैक्टर से सैक्रेटेरियट को जो सड़क आती है वह देखी होगी । इसके दोनों तरफ सड़क है और बीच में पटरी है । इसी तरह की वह सड़क बना दी जाए । वह फौरेस्ट बिल्कुल ही न काटा जाए ।

अब मैं अपने हल्के में जिन चीजों की आवश्यकता है उनकी बाबत कहना चाहता हूं क्योंकि यही मौका होता है जब कि अपने हल्के की तकलीफों के बारे में कहा जा सकता है । सब से पहले तो मैं अपने पी० डब्ल्यू ० डी० मिनिस्टर साहब से दरखास्त

करूंगा । वे उस इलाके में गए भी थे और उन्होंने वहां देखा भी होगा कि शहजादपुर से अम्बाला रोड है और यह थोड़ा ही फासला है । यह बहुत पुरानी सड़क है । धनाना से लेकर छज्जू माजरा तक का जो फासला है वह बरसात के अन्दर आइलैन्ड बन जाता है और उस वक्त जो भी आने–जाने के कम्युनिकेशन हैं वह कट जाते हैं । पहले जब प्राईवेट बसे चलती थीं उस वक्त तो वे लोग आपस में मिलकर आने–जाने के लिए कुछ इन्तजाम कर लेते थे लेकिन जब से बसों का नेशनेलाइजेशन हुआ है और सरकार ने यह काम अपने हाथ में लिया है तब से कुछ इन्तजाम नहीं है । तीन–चार महीने जब तक बरसात रहती है वहां के लोगों को आने–जाने का कोई साधन नहीं है । उनकी जिन्दगी बिल्कुल बैकवर्ड हो जाती है । जिस प्रकार आज से 50–60 साल पहले तकलीफ होती थी उसी प्रकार की तकलीफ उन दिनों में लोगों को हो जाती है । मैं यह कहना चाहता हूं वहां पर तीन नदियां टांगरी, ओमला और घनाना–चो पड़ती हैं । अगर इन तीनों पर तीन पुल नहीं तो कम से कम घनाना–चो पर फौरन ही पुल बनाना चाहिए । यह ठीक है कि तीनों पर पुल बनाने के बारे में तो कहा जाएगा कि बजट में इतना पैसा नहीं है । अगर घनाना–चो वाला पुल बना दिया जाए तो समस्या काफी हल हो सकती हे और पुल बनने से वह जगह आइलैन्ड बनने से बच जाएगी और बसें भी आ–जा सकेंगी । वरना इस समय तो बरसात के दिनों में डाक–तार का सिलसिला भी बन्द हो जाता है और लोगों को बहुत तकलीफ होती है । इसलिए मेरी प्रार्थना है कि

वह पुल अवश्य ही बनाया जाना चाहिए ।

जो सड़कें बनी हैं और उन पर अभी तक पुलियां नहीं बनी हैं उन पुलियों को बनाने में टाप–प्रायरिटी देनी चाहिए । कोई भी ऐसी सड़क नहीं रहनी चाहिए जिस पर कि पुली न हो ।

स्पीकर साहब, यहां पर ट्यूबवैल्ज के बारे में काफी सवाल पूछे गए हैं । ट्यूबवैल को कनैक्शंज बहुत जल्दी मिलने चाहिए और खासकर उन इलाकों में जहां पर पानी की काफी कमी है जैसा कि हमारा इलाका अम्बाला है और उस अम्बाला में भी तहसील नारायणगढ । हम लोग भी कभी स्वप्न में भी नहीं सोचते थे कि हमारे यहां नहर आएगी । हमारे यहां एम ० आई०टी० सी० ने जो ट्यूब वैल्ज लगाए हैं उनको भी एक–एक साल हो गया है सरकार ने उन पर एक–एक, सवा–सवा लाख रुपया एक ट्यूबवैल पर खर्च किया है लेकिन अभी तक कनैक्शन नहीं मित्रा है और अभी भी बेकार पड़े हैं । मेरी प्रार्थना है कि उनको तो हर जगह से सामान खरीदकर कनैक्शन देना चाहिए जिससे लोगों को फायदा पहुंच सके । अब मैं वाटर सप्लाई अर्थात् पब्लिक हैल्थ की बाबत कुछ कहना चाहता हूं । स्पीकर साहब, मैं तहसील नारायणगढ की बाबत बताना चाहता हूं कि वहां पर अभी भी ऐसी जगह हैं जहां पीने के पानी की बहुत तंगी है और खासकर जो वाड़ का छुरिया कहलाता है । उसमें पानी की बहुत तंगी है । वहां पर कई मील से पानी लाना पड़ता है । कई दफा तो वहां के लोगों को सडा हुआ पानी पीना पड़ता है । यह मैं मानना हूं कि

सरकार ने काफी कुछ किया है लेकिन मेरी प्रार्थना हैकि अभीभी काफी कुछ करने कीजरूरत है । पानी के लिए काफी ऊंचाई पर औरतों को जाना पड़ता है । जैसे हिसार की बाबत कहा जाता है कि पहले वहां पर कोई रिश्ता करने के लिए तैयार नहीं होता था वही हालत इस इलाके की है ।

लाला रुलिया राम (घरौंडा) : स्पीकर साहब, मेरा प्वांयट आफ आर्डर है । जो टाइम जनाब ने बोलने के लिये मुकर्रर किया था, इनको उसी के मुताबिक बोलना चाहिए । मेरे ख्याल में शायद इनकी घड़ी मन्दी चलती है (शोर) ।

Mr. Speaker : Order please. No interruptions. This is not a Point of Order.

श्री जगजीत सिंह टिक्का : स्पीकर साहब, मैं उसी घड़ी क्एरू मुताबिक ही चल रहा हूं । स्पीकर साहब, अब मैं इन्डस्ट्रीज के बारे में कुछ कहना चाहता हूं । नारायणगढ का जो हल्का है वहां पर कोई इंडस्ट्री नहीं है । सरकार ने काफी सहूलियतें इंडस्ट्रीज लगाने के लिये लोगों को दे रखीं हैं । जो लोग इंडस्ट्री लगाना चाहे, सरकार उसको हर प्रकार की सहूलियत देती है लेकिन हमारे हल्के की मजबूरी यह है कि वहां के लोग गरीब हैं, लोगों के पास पैसा नहीं है और जिसको वजह से वे इंडस्ट्री नहीं लगा सकते । सो मेरी सरकार से प्रार्थना है इस हल्के में भी कोई छोटी–मोटी इंडस्ट्री लगा दी जाए जिससे लोगों को उत्साह मिले और लोगों को इम्लायमैंट भी मिल सके । इससे आगे मैं

को–आप्रेटिव सोसाइटीज के बारे में जिक्र करना चाहता हूं । सरकार ने हर पटवार हल्के में मिनि बैन्कस की स्कीम बनाई है । वह बहुत अच्छी है । लोगों को इस से काफी फायदा होगा लेकिन इस बारे में मेरी थोडी सी डिपार्टमैंट से रिक्वैस्ट हैकि वह इतने रिजिड नहों । रिजिडिटी यह है कि एक पटवार सर्कल बहुत बड़ा है, आबादी बहुत ज्यादा है और लोगों को बहुत– दूर दूर पैसे लेने के लिये जाना आना पड़ता है जिससे लोगों को बड़ी परेशानी होती है । अतः सरकार कौ चाहिये कि जहां का एरिया बहुत बड़ा हो, वहां एक से ज्यादा मिनि बैन्कस खोल दे ताकि लोगों को किसी प्रकार की दिक्कत न हो और वे आसानी से अपना काम काज चला सकें । अगर सरकार ऐसा कर दे तो इस से लोगों को और भी उत्साह मिलेगा (घंटी) बस जी मैं वाइंड अप करने ही वाला हूं –

श्री अध्यक्ष : आप ऐसा करें कि पहली घंटी के ऊपर वाइंड–अप करने की तैयारी कर लें और दूसरी घंटी के ऊपर फौरन बैठ जाएं ।

श्री जगजीत सिंह टिक्का : ठीक है जी, इस से आगे स्पीकर साहब, कुछ बातें बिजली के मुताल्लिक भी करना चाहता हू । यह सच है कि बिजली जरूर मिली है लेकिन कुछ हिस्से दिन में भी मिले ताकि लोग उससे फायदा उठा सकें । ऐसा होना चाहिये कि कुछ रात को मिले और कुछ बिजली दिन को मिले । इससे आगे मैं ट्रान्सपोर्ट के बारे में कहूंगा कि अभी सढौरा और

नारायणगढ के बस अड्डे बनने बकाया हैं । वे अड्डे शीघ्र ही बनाए जाएं । इसके लिये जरुर इन्तजाम किया जाए । स्पीकर साहब, अभी कल ही अखबार में पढ़ा है कि भारत सरकार ने पंजाब और हरियाणा वालों को यह आफर की है कि जगाधरी से लुधियाना वाया चण्डीगढ रेल लाइन बिछा दी जाएगी अगर दोनों सरकारें अपने अपने हिस्से की जमीन सरकार को दे देंगी । तो मेरी अपनी हरियाणा सरकार से यह प्रार्थना है कि वह अपने हिस्से की जमीन भारत सरकार को आफर कर दे ताकि यह काम जल्दी ही शुरू हो सके और इससे लोग फायदा उछा सकें । स्पीकर साहब, मैं आपकी तरफ देख रहा हूं कि आप घंटी की तरफ देख रहे हैं । अतः मैं इससे पहले ही बैठ जाता हूं और आपका धन्यवाद करता हूं कि आप ने मुझे बोलने का मौका दिया ।

श्री ओम प्रकाश गर्ग (थानेसर) : आदरणीय स्पीकर साहब, मेरे को भी आपने बजट पर बोलने का समय दिया, मैं आपका धन्यवाद करता हू । बजट की मैं क्या सराहना करूं, बजट तो बहुत ही बढ़िया है । जिसने भी हमारे वित्त मंत्री महोदय की स्पीच सुनी है, वही इस से बड़ा प्रभावित हुआ है, अगर मैं उस की तारीफ में लग जाऊं तो आपकी घण्टी बज जाएगी और मेरा काम खत्म हो जाएगा । (हंसी) स्पीकर साहब, इस बजट के अन्दर जितनी भी बातें आई हैं, वे सभी सराहनीय हैं । सबसे पहले मैं ऐग्रीकल्चर के बारे में कहूंगा । ऐग्रीकल्चर के लिये इस बजट में बहुत अच्छा प्रोवीजन रखा गया है लेकिन इसके बावजूद

ऐग्रीकल्चरिस्ट को जो जो सहूलियतें मिलनी चाहिये थीं, वह नहीं मिल रही हैं । इस में सरकार का गुनाह नहीं है । सरकार ने तो सहूलियते दी हैं, बिजली दे रही है, पानी दे रही है लेकिन किसान को कीमतें इतनी अच्छी नहीं मिलतीं जितनी कि उसको अपने अनाज की मिलनी चाहिये । जमींदार को रोजमर्रा की जो चीजें खरीदनी पड़ती हैं, उनके भाव कई गुना ज्यादा देने पड़ते हैं । जैसे मेरे से पहले बोलने वाले कई भाइयों ने खाद की कीमतों में बढ़ौतरी का जिकर किया कि खाद की कीमतें बहुत बढ़ गई हैं और किसान जो पैदा करता है उसे उस की कम कीमत मिलती है । अतः मेरी सरकार से प्रार्थना है कि जमींदार जो पैदा करता है, उनकी कीमतों का ध्यान रखा जाए । जैसे गन्ने की पैदावार ज्यादा है । आप देखें कि गन्ना पैदा करने वाले किसान को कम खर्चा नहीं करना पड़ता लेकिन गन्ने के काश्तकार की कीमतों को पहले साल की निस्बत सरकार ने घटा दिया बल्कि पड़ोसी प्रदेश की निस्बत भी यहां गन्ने की कीमत कम दी जाती है । फिर भी यह एक सराहनीय बात है कि हमारे – मन्त्री महोदय, मुख्य मन्त्री महोदय और केन कमिश्नर साहब पहले ही इस ओर बड़े ध्यान–पूर्वक सोच रहे हैं कि हमें इस मसले को किस तरह से हल करना चाहिये । मुझे पूरी आशा है कि सरकार इसका कोई न कोई हल जरूर निकाल लेगी क्योंकि इससे किसान को बड़ी परेशानी है । सरकार किसान को उसकी पैदावार का सही दाम नहीं दे पा रही है । दूसरे गन्ने के बारे में, मैं एक बात और करना चाहता हूं कि किसानों को परतों पर बौन्ड भरने के लिये केवल 10 रोज दिये

हुए हैं । कई किसान भाइयों ने किसी कारणवश अपने बौन्ड नहीं भरे । कुछ भाई ऐसे हैं जिन की अभी तक कडि कटाई बची पड़ी है और कुछ कर्मचारियों ने गड़बड़ कर दी है जिसके कारण वे लोग अपने बौन्ड वगैरह नहीं भर सके । किसानों की परते तो मिलों में जमा हैं ऐसे गरीब आदमियों को अवश्य ही कंसिडर कर लेना चाहिये और यह जो 10 रोज की मियाद बौन्ड भरने के लिये रखी गई है, इस मियाद को बढ़ा दिया जाए ताकि किसान भाई सहूलियत से अपना काम काज कर सकें ।

स्पीकर साहब, तृक रोज मैंने एक प्रश्न किया था, उसके बारे में और तो कोई बात नहीं करनी है सिर्फ मिनिस्टर साहब के जवाब का जवाब देना चाहता हू । उन्होंने यह फरमाया था कि कैटल फीड प्लांट जींद से 1,30,000 हजार रुपये का प्रौफिट हुआ है । मैं आपके द्वारा मिनिस्टर साहब और मुख्य मन्त्री महोदय के नोटिस में यह लाना चाहता हूं कि वह प्लांट 1,30,000 रुपये के फायदे में नहीं है बल्कि वह 6 लाख रुपये के लौस में है । इन्होंने राइस–बान 26 रुपये पर लिया और 6 हजार टन 50 और 55 रुपये की ब्लैक में फरोख्त किया जोये नहीं कर सकते थे । अगर यही काम शैलर वाले करते तो उनके लिये डी० आई० आर० थी और इन के लिये कुछ नहीं । इन्हें गवर्नमैंट आफ इंडिया की स्कीम के तहत दो लाख रुपये की मक्की मुफ्त मिली और 6 लाख रुपया इन्होंने. राइस–ब्रान से ब्लैक में कमाया, इस तरह से ये 8 लाख रुपये में से 1, 30,000 रुपया मुनाफा दिखा रहे

हैं । अब आप ही देखिये कि यह क्या है? मेरा मतलब यह है कि इनको किसी चीज से फायदा नहीं हुआ लेकिन मैं इस बहस में नहीं पड़ना चाहता । ऐग्रो इंडस्ट्रीज के बारे में सारे आंकड़े मेरे पास हैं । इनकी कोई चीज प्रौफिट में नहीं है । मैं इतना सोचता हूं कि व्यापार बुद्धि का आदमी इसको चला पाता है लेकिन अब इस गवर्नमैंट की खुशकिस्मती है कि व्यापार बुद्धि ही नहीं बल्कि जिन से व्यापारी बुद्धि लेते हैं, अपना शगुन निकलवाते हैं, मुहूरत निकलवाते हैं, जो व्यापारियों का भी गुरू है । ऐसे आदमी को एम० डी० बना दिया गया है । हो सकता है कि इसका अब कुछ सुधार हो जाए । इसके अलावा इनके क्वालिटी मार्किटिंग इन्सपैक्टर हैं उसका नाम तो मैं यहां लेना उचित नहीं समझता । उसने जो कैटल फीड दिया था वह जगह जगह सैं वापिस आया है । आप हुस चीज की पड़ताल कर सकते हैं कि मैं गलत कह रहा हूं या सही कह रहा हूं । मैं यह बात किसी और कारण से नहीं कह रहा हूं बल्कि मैं तो इसको सुधारने के लिये कह रहा हूं । वहां पर कैटल फीड की भी क्वालिटी ठीक नहीं है और क्वालिटी इन्सपैक्टर्ज की भी क्वालिटी ठीक नहीं है क्योकि वह इन्सपैक्टर गुजरात स्टेट में एक आनन्द जगह है वहां लगा हुआ था । वहां उसको चार्ज शीट मिला हुआ था और डिसमिस होने वाला था लेकिन यहां आने पर उसका भी कुछ बन गया है और इनका भी कुछ बन गया है । मुझे उम्मीद है कि ये हालात अब सुधर जाएंगे क्योकि अब दिमाग से काम लेने वाले आदमी इस जगह पर आ गये हैं । दूसरे अनाज की उपज के बारे में अन्दाजा लगाया जा

रहाहै, बहुत अच्छी बात है क्योंकि अन्दाजे के बगैर कोई काम नहीं चलता है लेकिन अन्दाजा यह भी था कि बारिश बड़ी अच्छी होगी, पिछले साल भी बारिश अच्छी हुई थी और अब यही ख्याल था, अब भी हम 5– 7 रोज पहले सोचते थे कि बारिश अच्छी होगी लेकिन हमारा अन्दाजा गलत हो गया तो अब चड्ढा साहब से सवाल पूछते हैं कि अब क्या होगा । अब 28 तारीख को सैशन खत्म हो जाएगा तो ये सवाल भी खत्म हो जाएंगे और चड्ढा साहब भी इधर उधर की बातें करेंगे । अब जमींदारों ने अपना रुपया जमीन में दबा दिया है और अगर आप उनको बिजली न दे पाये तो वह रुपया वहीं जमीन में दबा रह जाएगा । इसलिये मेरा सुझाव है कि आप ज्यादा से ज्यादा बिजली किसानों को दें ताकि उनका जमीन में दबा हुआ पैसा ऊपर आ सके । उससे किसान का पेट भरेगा, हरियाणा का पेट भरेगा और हरियाणा के बाहर जिनको हम अनाज भेजते हैं उनका भी पेट भरेगा । तो मैं यह अर्ज करुंगा कि इस तरफ आप खास ख्याल रखें । दूसरे फैमिली प्लानिंग की बात है, यह बड़ी अच्छी बात हए । फैमिली प्लानिंग तो चाहिये ही क्योंकि जब तक प्लानिंग फैमिली शुरू से नहीं होगा तब तक कुछ नहीं होगा ।

15. 00 बजे

आबकारी व कर मंत्री (श्री श्याम चन्द) : आपके कितने बच्चे हैं?

श्री ओम प्रकाश गर्ग : चौधरी श्याम चन्द जी मेरे से पूछ रहे हैं कि मेरे कितने बच्चे हैं । तो मैं उनको बता दूं कि तीन तो मेरे हैं और चार मेरी बीबी के हैं । दरअसल इनका पूछने का मतलब तो चौधरी गोवर्धन दास से था । उनके सिर्फ 11वां बच्चा हुआ है और उनसे हम पार्टी खाकर आए हैं ।

एक आवाज : 11 वां नही दसवां है ।

श्री ओम प्रकाश गर्ग : दसवां है तो हो सकता है कि यह जबान मुबारिक हो जाए और 11 वां भी हो जाए । हमारा तो यह अमूल है कि जब किसी के खाना है तो उसका गाना भी है ।

श्री. गिरीश चन्द्र जोशी : स्पीकर साहब, मेरा प्वांयट आफ आर्डर हैकि अभी माननीय सदस्य बोल रहे थे इन्हेंने बताया कि चार बच्चे इनकी बीवी के हैं और तीन उनके हैं तो क्या आनरेबल मैंबर यह बताएंगे कि बीवी वाले चार किसके हैं? (हंसी)

श्री ओम प्रकाश गर्ग : स्पीकर साहब, इनको तो यह बात नहीं पूछनी चाहिये थी क्योंकि मेरी बीवी जमुना नगर की है और ये उनके भाई लगते हैं (हंसी) तो स्पीकर साहब, अब मैं थोड़ा सा ट्रांसपोर्ट के बारे में अर्ज करूंगा । हमारी ट्रांसपोर्ट का काम बहुत सराहनीय काम एं । ट्रांसपोर्ट ने जितनी तरक्की कीहै इसमें कोई शक नहीं है । बसें भी अच्छी हैं लेकिन यह बात दूसरी हैकि हमारे इलाके में छोटे छोटे रूटों पर गन्दी और निकम्मी बसें चलती हैं । दूसरी अर्ज मैं आपसे यह कर दूं कि

कुरुक्षेत्र जिला बनने के बाद कई बसें वहां से चलाई गई, जिला हैड क्वार्टर होने की वजह से लेकिन आपको सुन कर ताज्जुब होगा कि एक बस जो सुबह 6. 30 पर चण्डीगढ से आती थी वह कल बन्द करदी गई है । न मालूम स्टेट मिनिस्टर साहिबा से सवाल पूछ लिये गये थे इसलिये कर दी । तो अगर कोई ऐसी बात है तो उसके लिये मैं माफी चाहूगा लेकिन वह बस जरूर फिर से चला दी जाए बल्कि यह बताएं कि और कौन कौन सी बसें कुरुक्षेत्र से चलेंगी । इसके अलावा लाडवा से दिल्ली और अम्बाला केलिये भी और बसें चलनी चाहियें । इस के बाद मैं लाडवा बस स्टैंड के बारे में कहना चाहता हूं । जब कर्नल साहब ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर होते. थे तो इनको हम मथाना में ले गये थे । ये बड़े अच्छे आदमी हैं । इन्हेंने वायदा किया था कि यह बस स्टैड तीन महीने में बनवा देंगे । मैं समझता था कि इनका वायदा फौजियों वाला वायदा होगा । ये तीन महीने का वायदा करके आये थे लेकिन अब तीन साल ने वाले हैं, वह काम नहीं हुआ । मैं आपके द्वारा ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर साहब से यह दर्खास्त करूंगा कि जगह एक्वायर करने के लिए सैक्शन 4 के तहत कार्यवाही हो गई है और बस स्टैड की वहां बहुत जरूरत है इसलिये उसे जल्दी बनवाने की कृपा करें । इसके बाद स्पीकर साहब, मैं आपके द्वारा सदन में बताना चाहता हूं कि कुरुक्षेत्र के अन्दर 29 अप्रैल को सूर्य ग्रहण का मेलाहोने वाला है लेकिन अभी तक उस संबंध में एडमिनिस्ट्रूएशन में कोई हिल–जुल नहीं हुई है । पहसए तो यह इन्तजाम साल सारन पहले शुरू हो जाता था लेकिन अब की बार

अभी वहां पर ऐडमिनिस्ट्रेटर भी मुकर्रर नहीं हुआ है जोकि अपना काम शुरू कर दे । वहां पर लाखों यात्री इकट्ठे होंगे ।

राजस्व मंत्री (पंडित चिरंजी लाल शर्मा) : ऐडमिनिस्ट्रेटर को कल मुकर्रर कर दिया गया है ।

श्री ओम प्रकाश गर्ग : पंडित जी बता रहे हैं कि कल कर दिया है, बड़ी अच्छी बात है । एक वहां की म्यूनिसिपल कमेटी का जो ऐडमिनिस्ट्रेटर है, वह पार्ट टाइमर है...

पंडित चिरंजी लाल शर्मा : वह भी होल टाइम आ गया है ।

श्री ओम प्रकाश गर्ग : अगर आ गया है तो ठीक है लेकिन स्पीकर साहब, आप पंडित जी की बात पर न जाएं, आप इसका ध्यान रखें । इसके बाद मैं सड्कों के बारे में एक अर्ज करना चाहता हूं ।

श्री ओम प्रकाश गर्गः बस जी वाइंड–अप कर रहा ईदू, जहां सड़क मिली मैं वाइंड अप कर दूंगा । (हंसी) स्पीकर साहब, आपको सुन कर ताज्जुब होगा कि हमें सबसे खुशी की बात तो यह है कि हमें सड़के मिलें या न मिलें लेकिन मिनिस्टर साहब हमारे जिले में हर महीने जाते हैं तो हम तो उनको देख कर ही अपनी तसल्ली कर लेते हैं । तो पंडित जी से मेरी गुजारिश यह है कि कुरुक्षेत्र जब जिला बना था तो कुरुक्षेत्र को देहातों से मिलाने के लिये काफी लिंक बनाए गरा थे, उनको मुकम्मल करो

और इसके अलावा जो कई गैप रहते हैं उनको भी पूरा करो । इसके बाद मैं बीस सूती प्रोग्राम पर आता हूं । बीस सूती प्रोग्राम बहुत अच्छा प्रोग्राम छैं जिसका सारी जनता ने स्वागत किया है । हमारे भाई कहते हैं कि कौन से कर्जे इससे माफ हो गये हैं । यह तो उन लोगों से पूछो जिनके दादा या परदादा किसी जमींदार के हाली थे और आज तक उनकी जान नहीं छूटी है । इस बीस सूत्री प्रोग्राम की मेहरबानी से जगह जगह कोआप्रेटिव सोसाइटियों की तरफ से बैकं खोले जा रहे हैं और पटवार सर्कलों में सोसाइटिया बनाई जा रही हैं जिससे कि किसानों को ज्यादा से ज्यादा सहूलियत मिलेगी । तो ये सारी की सारी बातें बीस सूती प्रोग्राम की हैं । मजदूर की मजदूरी भी बढ़ गई है । हां यह बात दूसरी है कि पंडित जी ने अपने पी० डब्लयू ० डी० के महकमें की मजदूरी नहीं बढ़ाई है और उनकी वही है जो पहले से चली आ रही है । तो मैं अर्ज करता हूं कि इस महकमा की मजदूरी की दर भी बढ़नी चाहिये तभी इस प्रोग्राम पर पूरी तरह से अमल होगा । (घंटी) एक बात मैं पशुपालन के बारे में कहना चाहता हू । इस बारे में सरकार पूरी कोशिश कर रही है और इतनी कोशिश कर रही है कि हिसार से सीमन लेकर हमारे कुरुक्षेत्र में आ गये कि आर्टिफिशल इनसैमीनेशन से गायों की नसल सुधारेंगे और एक नई नसल बनेगी जो ज्यादा से ज्यादा दूध देगी । गांव वाले भी बेचारे अपनी गायों की नसल सुधारने क्एरू लिये भागते भागते फिरते बावले हो गये कि इस तरह से दूध की पैदावार ज्यादा होगी और मुल्क में व्हाइट रैवोल्यूशन आ

जाने की वजह सेजैसे कि उनको सरकार की तरफ से बताया गया उनकी माली हालत सुधर जायेगी और वे अमीर हो जायेंगे लेकिन' उनकी आमदनी बढ़ाने के लिये घी जो पहले 25 रुपये किलो बिकता था. उसका भाव 24 रुपये किलो कर दिया है और दूध का रेट भी कम कर दिया है, गाय का ढूध तो लेना ही बंद कर दिया है, लेते ही नहीं । पता नहीं यह सब कुछ आर्थिक संकट दूर करने के लिये किया है या और कुछ करने के लिये किया है । एक तरफ तो आर्टिफिशल इनसैमीनेशन का बड़ा दौर चला कि नई नसल की गायें बना रहे हैं जो ज्यादा दूध देंगी, इंजैक्शन पर इंजैक्शन लेकर इस महकमा के कर्मचारी गांव गांव में भागते फिरते रहे और लगी गांव में गाय पर गाय चढ़ने, उनकी तादाद बढ़ने, लेकिन अब उनका दूध लेना ही बंद कर दिया । मेरी गुजारिश है कि अगर आपने गाय का दूध नहीं लेना है तो फिर यह सारे का सारा आडम्बर करने की क्या जरूरत थी? इससे कोई फायदा नहीं है यह तो गांव के लोगों को खराब करने वाली बात है । तो मैं अर्ज करता हू कि गाय का दूध भी उसी रेट पर लेना चाहिये और जो दूध की कीमत घटाई गई है उसे बढाना चाहिये.

चौधरी मेहर चंद : आन ए प्वांयट आफ आर्डर सर । मैं यह पूछना चाहता हूं कि क्या ऐसी बातें हाउस में कहने की कोई जरूरत है कि गाय पर गाय चढाई जाती है । (हंसी)

श्री ओम प्रकाश गर्ग : गाय के ऊपर गाय का मतलब आप समझे नहीं । इसका मतलब है शरीफ आदमीके ऊपर शरीफ

आदमी । (हंसी) तो मैं अर्ज करता हूं कि इस बीस सूत्री प्रोग्राम के तहत स्टूडैट्स को सहूलियत देने केलिये बुक वैक्स खोले गये हैं और गवर्नमैंट की तरफ से इन को कालेजों में खोलने के लिये माली इमदाद दी गई है । मैं इस बात को लिये गवर्नमैंट को बधाई देता हूं और इस बात का स्वागत करता हूं । यह बहुत खुशी की बात है इस बारे में मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारे लाडवा में घनौरा गांव के अन्दर इन्दिरा कालेज खोला गयाहै जिस का शिलान्यास चौधरी बंसी लाल जी ने 24 जनवरी 1974 को किया था । 25 जुलाई, 1975 को चौधरी माडू सिंह जी ने वहां क्लासों की इनआगरेशन की है और 30 नवम्बर 1975 को हमारे गवर्नर साहब ने उस कालेज की बिल्डिग की इनआगरेशन की है । इस के अलावा हमारे मु ख्य मती जी श्री बनारसी दास गुप्ता जी, चट्ठा साहब और दूसरे मंत्रीगण उस कालेज को देख चुके हैं कि वह कितना अच्छा कालेज है । फिर हमारी प्रधान मती जी कहती हैं सब से पहले हमारे जो देहाती भाई हैं, बैकवर्ड इलाकों के लोग हैं और रूरल एरियाज के भाई हैं जो पिछड़े हुये हैं उनको सहूलियतें दी जायें । तो मेरे कहने का मनशा यह है कि वहां पर उस कालेज में बुक बैंक खोलने के लिये सहायता देने की कृपा की जाये । (घंटी) अच्छा जी, मैं बैठ जाता हूं अगर और वक्त नहीं है । मेरी बहुत सी बातें रह गई हैं । लेकिन आप से फिर टाईम लेकर कहने की कोशिश करूंगा ।

चौधरी प्रताप सिंह दौलता (बेरी) : स्पीकर साहब,

चूंकि टाईम थोड़ा है इसलिये मैं दस मिनट से ग्यारवां मिनट नहीं लूंगा मेरी आदत ही ऐसी है कि मैं हमेशा अलाटिड टाईम से आगे नहीं जाता । इस लिये मैं जल्दी जल्दी अपने प्वांयट्स रखूंगा । पहले तो मैं यह बात कलीयर कर देना चाहता हूं यह बहुत सारे मैंबर साहिबान को मैं डिस–एपांयट करूंगा जो शायद सोचते होंगे कि मैं कुछ उनको सुनाना चाहूंगा लेकिन मैं ऐसी किसी बात में नहीं पडूगा क्योंकि मेरा ऐसा स्टैडर्ड नहीं है जो कुछ लोगों का है । मैं रैलेवैटं वात ही करूंगा दूसरी कोई बात नहीं करूंगा । पहली बात तो यह है कि मैं इस बजट को बैल्कम करने के लिये खड़ा हुआ हूं । मुझे खुशी है कि गवर्नर साहब का ऐडैरस, हमारे चीफ मिनिस्टर साहब की स्पीच और इस बजट, इन तीनों ने मित्र कर यह साबित कर दिया है कि जो डायनैमिक पालिसी हमारे साबिक चीफ मिनिस्टर चौधरी बंसी लाल जी के वक्त में चली और चलती रही वही. आगे अब चलेगी और वह चीज जो मेरे जैसे आदमी को पसंद नहीं थी, जो हाउस में अननैसेसरी की टैनशन थी, हर वक्त घुटन का ऐटमासफीयर था, हर वक्त कबड्डी चलती थी, वह अब नहीं रही है, बडा पीसफुल ऐटमासफीयर चरना है हाउस में यह खुशी की बात है । तो मैं यह अर्ज करता हूं कि अगर आप इस बजट को पढ़ें तो आपको बंसी लाल गवर्नमैंट के सारे ऐडवांटेजिक्र मिलेंगे माइनस इनटालरैंस । इस के लिये मैं गवर्नमैंट को उसकी इस पालिसी के लिये बधाई देता हूं । स्पीकर साहब, मैं इस गवर्नमैंट को इस बात के लिये भी बधाई देता हूं कि यह जो बजट इस ने रखा है यह रूरल वायस्ड है और सारे हिन्दुस्तान में ऐसा

रूरल वायस्ड बजट कहीं नहीं है जितना हरियाणा में है । किसी और स्टेट में रूरल एरियाज में बजट की इतनी परसेंटेज खर्च नहीं करती है जितनी कि मेरी इस स्टेट के चीफ मिनिस्टर साहब और उनकी यह गवर्नमैंट कर रही है और उसके लिये मैं उनको बधाई देता हूं । अब मैं कुछ सजैशंज देना चाहता हूं । यह मानी हुई बात है कि देहात में सब से गरीब तबका हरिजन हैं । गर्वनमैंट के तीन अंग हैं, ऐग्जैक्टिव, लैजिसलेचर और जुडीशियरी । मैं कहता हूं भला हो महात्मा गांधी जी एन, नेहरू जी का और उन कस्टिच्यूशन बनाने वालों का जिन्होंने इन गरीब हरिजनों को किसी गवर्नमैंट के रहम पर नहीं छोड़ा और उन्होंने इन के लिये कांस्टीच्यूशन में ही रिजर्वेशन कर दी और उनको सर्विसिज में वह रिजर्वेशन मिल भी रही है लेकिन मेरी ख्वाहिश है कि अगर किसी रिजर्वेशन की वेकैसी के लिये कोई हरिजन अवेलेबल न हो तो उसे फित्र–अप न किया जाये जब तक कि उसके लिये कोई हरिजन मिल न जाये यह असूल गर्वनमैंट बना ले । मेरे इन भाइयों को लैजिसलेचर में रिजर्वेशन पूरी मिली हुई है और इनकी रिप्रेजैंटेश्न पूरी है लेकिन मेरे इन भाइयों की रिप्रेजैंटेशन जुडीशिरी में नहीं है । हाई कोर्ट से लेकर सब जजी तक हरिजनों की रिप्रेजैटेशन बहुत ही– कम है । यह कोई जात पात की बात नहीं । मै तोएक क्लास ऐजे होल की बात कर रहा हूं कि उनका नम्बर भी आना चाहिये और उन लोगों का नम्बर कम होना चाहिये जो डेढ सौ साल से सारी जुडीशियरी पर कब्जा किये हुये हैं । यह इनसाफ की बात है और यह कोई जात पात की बात नहीं है

। किसी और भाई की ऐसी जहनियत हो तो हो और जैसे चाहे और जैसी उसकी जहनियत हो वैसे. सोच ले लेकिन मैं इन्साफ की बात करता हूं और उस तबके के लिये इन्साफ की बात करता हूं जो बहुत गरीब है और पिछड़ा हुआ है । देहात में एक और गरीब क्लास है और तीन साल पहले भी मैंने उसकी बात हाउस में की थी और वह है रूरल शाप कीपर, देहात का बनिया, जिसकी बड़ी बड़ी पुरानी हवेलियां बनीं हैं गांव में और उसका गांव में बहुत बड़ा पार्ट रहा है और आज भी है । आज वह बहुत खसता हालत में है । उसकी आज बहुत ही डिसऐडवाटेजिस पोजीशिन है । उसके लिये कोई रोजगार का साधन नहीं रहा है उसका कारोबार ठप्प हो चुका है । देहात में जो शहर का मोवाइल हौकर जाता है वह गांव के बनिये से बहुत ऐफीशेंट हैट्रेड में और बड़ा चालाक है इसलिये उस ने इस क्लास का गाँव में काम, बिजनैस खत्म कर दिया है और वह आज सोशली और इकनामिकली बहुत कमजोर हो चुका है । किसी किसान के लडके पर गरीबी आ जाये तो वह सड़क पर जा कर रोडी कूट लेगा लेकिन एक महाजन का लडका जो किसी और तहजीब में पला है, जिसकी अपनी पुरानी ट्रेडीशन है वह चाहे भूखा मर जायेगा या आसाम की तरफ लोटा ले कर चला जायेगा लेकिन सड़क पर जा कर टोकरी नहीं उठा सकेगा । अगर उसका कहीं सट्टे का दाव लग जाये तो करोड़पति बन सकता है लेकिन मजदूरी नहीं कर सकता क्योंकि उसका पास्ट उसे हाट करता है और मेरा तजरुबा है कि इन बनियों की मैजोरिटी हरियाणा से जा कलकत्ता और आसाम में जाकर बस गई

है । तो मैं यह अर्ज करता हूं कि यह जो आपने मिनी बैंक्स चलाये हैं इन से जैसे इन्डस्ट्री वालों को कम रेट पर पैसा देते हैं उसी तरह से इन रूरल शाप कीपर्ज को कम रेट पर कर्ज दे कर उनको अपना कारोबार चलाने में मदद दें । एक बात और करें कि यह जो बाहर से शहर से गांव में हौकर जाता है उस पर विलेज पंचायत पाबंदी लगा दे । गाँव का जो बनिया है वह गाँव का पार्ट है वह गाँव की हर बहु बेटी को अपनी बहू बेटी समझता है लेकिन यी जो बाहर से बेचने आता हए इसे किसी से कोई लिहाज नहीं होता । इस लिये मैं अर्ज करता हूं कि पाबंदी लगा दी जाये कि गांव में जो चीज बिकेगी उसके बेचने का लाइसैसं गांव की पंचायत देगी और जिसे वह लाइसैंस देगी उसकी ही चीज गांव में बिकेगी दूसरे की नहीं बिकेगी । तीसरी क्लास जो गांवों में रहती है रूरल आर्टीजन की, जिन को बैकवर्ड. कहते हैं, उन बेचारों की रिजर्वेशन सर्विसिज में तो हैं लेकिन लैजिस्लेचर में नहीं है । मैंने इस बात को कई बार दोहराया कि जो खाती हैं, लोहार हैं इनका लैजिस्लेचर में एक भी रिप्रैजैटेटिव नहीं है, एक भी आर्टीजन मैम्बर बनकर नहीं आता क्योंकि उनकी तादाद थोड़ी है । हरिजन जिनके पास पैसा है उनके 15 भी आ सकते हैं, बैकवर्ड भी आ सकते हैं जिनको पूलिटिकल पार्टी चाहे कामयाब करवा सकती है लेकिन हुन आर्टीजन का कोई मैम्बर नहीं है । कम से कम 10— 15 मैम्बर इनके भी लैजिस्लेचर में होने चाहिए । इससे अगली क्लास है प्रैजैटै प्रोप्राइटर्ज की । इस पर मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा क्योंकि इन पर मेरे चीफ मिनिस्टर बोल लिए हैं, गर्ग साहब भी बोले हैं । जब

ये बातें करते हैंतो इनकी बातें सोशलिजम की बातें हो जाती हैं और जब मैं बात करता हूं तो जातपात की बाते हो जाती हैं । ऐसी बात नहीं होनी चाहिए । 28 साल हो गए हैं स्पीकर साहब, जब से यह मजदूर, धरती का बेटा गुलाम है । मैं यह बात बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहना हूं । 28 साल से यह क्लास मर रहीहै । Peasant proprietary class जहां तक लैजिस्लेचर का ताल्लुक है, पीजैट प्रोप्राइटर क्लास का लैजिस्लेचर मेंकोई रिजर्वेशन नहीं है लेकिन फिर भी अपनी स्टैरन्थ से, किसी पार्टी का टिकट मिले या न मिले, यहां तक धक्के खाकर ये आ जाते हैं लेकिन पीजैट प्रोप्राइटरज की रिजर्वेशन नहीं है, ऐग्जैक्टिव में भी नहीं है इस बात से ऐडवोकेट जनरल मिस्टर कौशल मुझसे ऐग्री करते हैं । जब तक इन के लिए ऐग्जैक्टिव मैं आधा या चौथाई हिस्सा रिजर्वेशन नहीं होगी तब तक इनके साथ बड़ी भारी बेइन्माफी होगीं । आप इसको इकोनोमिक क्लास बना दीजिए कि जो पीजैट प्रोप्राइटर 5 एकड़ से कम जमीन का मालिक हो, चाहे वह खतरी हो, चाहे अरोडा हो, चाहे महाजन हो, कास्ट का इस में कोई सवाल नहीं, this present proprietary class is a dying class. उसकी रिजर्वेशन होनी चाहिए । Present proprietor's son should get reservation in service. वरना जो यह गंगा तबका है यह इसी तरह पिसता रहेगा । आप सैक्रेटेरिएट की लिस्ट उठाकर देख लें, सर्विसिज में कोई पीजैटं प्रोप्राइटर नही मिलेगा, चपडासियों में मिलेंगे, सिपाहियों में मिलेंगे, इसके बीच की सर्विसिज में नहीं मिलेंगे, जुडीशियरी में भी कमी है । पीजेंटरी के बारे में सिवाये

इसके, और मैं कुछ नहीं कहूंगा । पिछले तीस साल से जन्म की बिना पर शड्यूल्ड कास्ट्स के, हरिजनों के राइट्स रिजर्व हो सकते हैं तो लैंड ऐलीनेशन ऐक्ट के मुताबिक जन्म की बिना पर स्टैचुटरी एग्रीकल्चरिस्ट्स की रिजर्वेशन क्यों नहीं करते? या तो आप सारा इकोनोमी पर बेस रखें या जन्म पर रखें । जन्म से कुछ हरिजन हैं और कुछ बैकवर्ड हैं । मेरा कहने का मतलब है कि आप लैड एलिनेशन ऐक्ट के मुताबिक रखें और इस क्लास के लिए भी सर्विसिज मैं रिजर्वेशन करें ।

इसके इलावा मैंने प्लाट्स के बारे में यह नहीं कहा कि हरिजनों को प्लाट्स नही मिलने चाहिए, ऐसी एबसर्ड बात कभी नहीं कही । क्या हरिजन दरख्तों की छतों पर रहेंगे अगर प्लाट नहीं देने? दे दीजिए प्लाट्स लेकिन हरिजन भाइयों को बता दें कि गवर्नमैंट ने दिए हैं या हुमने दिए हैं । कामन लैड एक्ट, पंचायत ऐक्ट वगैरा के तहत जो जमीन लेकर देनी है वह दे दें। हमें कोई गिला नहीं लेकिन उन को यह तो बता दें कि वह जमीन हमने (जमींदारों ने) दी है ताकि हम से वे प्यार करना सीखे । इसके साथ ही साथ यह भी कर दें कि जिस हरिजन भाई को जमीन मिले उसको कम से कम 5 हजार रुपया गवर्नमैंट दे वरना वह मकान नहीं बना सकेगा, वह उस प्लाट को बेच लेगा जमींदार को और your prupose to provide a house will be failure उसको 5 हजार रुपया देना जरूरी है । अगर नहीं देते तो सिवाये इसके कि वह जन्मना प्लाट जमींदार को बेच दे, और कोई चारा नही ।

50 परसेंट प्लाट्स जमींदारों को बिकते हैं । स्पीकर साहब, मैं टाईम का लिहाज रखते हुए अब रूरल से अर्बन की तरफ आता हूं । अर्बन प्रौपर्टी के बारे में मेरा एक सुझाव है । यह बात रैवेन्यु मिनिस्टर से सरोकार रखती है । बहुत सारे शहरी मकानात दफतरों के लिए और दूसरी चीजों के लिए हैं । मेरा अपना मकान किराये पर था लेकिन मैंने बा–रसूख होने की वजह से किराया बढ़ा लिया । यह मेहरबानी गुप्ता साहब की हुई कि मैंने किराया बढवा लिया । लेकिन बहुत से ऐसे केसिज हैं जिनके किराये नहीं बढ़ते । मेरे पास ऐसे केसिज आए है । पं० चिरंजी लाल जी के पास भी ऐसे केसिज आए होंगे । मेरे पास एक विडो आई, वह जाए जाए रो रही थी । वह बेचारी क्या करे? वह मुकद्दमा लड़ नहीं सकती थी । रैटं रिवाईज करवाने के लिए गवर्नमैंट के पास मुक्त के वकील हैं लेकिन जो आम सीटिजन की प्रौपर्टी गवर्नमैंट के पास है, पी० डबल्यु ०डी० उसकी असैसमैंट यू ० टी० की तरह हर सात्र किया करे ताकि ये झगड़े पैदा न हों । रैवेन्यु मिनिस्टर साहब, डिपार्टमैंटल इक्टूक्शन्क दें कि हर साल, हर साल नहीं तो पांच साल के बाद रैटं रिवाईक कर दें । दूसरी सुजैशन, जिसके बारे में कई बार मैं कह चुका हूं कि प्रौपर्टी टैक्स और हाउस टैक्स को मर्ज कर दें । इससे लोगों को बड़ी भारी तकलीफ है, पेमेंट करने में बड़ी दिक्कत होती है । स्पीकर साहब, मैं आपका ज्यादा वक्त न लेता हुआ दो मिनट का वक्त मांगूंगा । देश में कास्ट और रिलिजन न हों । इस चीज ने देश का बेड़ा गर्क किया है । गवर्नमैंट कास्ट और रिलिजन से परे रहे । कास्ट वाले कामों

को पैटरोनाईज नहीं करना चाहिए । व्यापार मण्डल एक ऐसा वर्ग है जिस में कास्टीजम नहीं है, उसको बेशक गवर्नमैंट अटैंड कर ले, भट्टो में किसान कान्फ्रेंस हुई उसको भी अटैन्ड कर ले लेकिन अगर जाटों का जलसा हो, गौड़ों का जलसा हो, अग्रवालों का जलसा हो तो उस में गवर्नमैंट को पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए, स्टेट को ऐसी लानत परपैचुएट नहीं करनी चाहिए । फासिजम के लिए तीन चीजें चाहिए– A god like leader than a cheap slogan and than religion यह जो रिलिजन की एनकरेजमैंट है, इससे दूर रहना बेहतर है । यह जो कुम्भ का मेला भरता है, इस में गवर्नमैंट की तरफ से कोई अटैम्पट नहीं होता लेकिन अगर आर्य–समाज की शताब्दी हो, गुरू का जलूस निकले और उस पर गवर्नमैंट पैसा खर्च करे, इन चीजो में, इन पाखंडियों में गवर्नमैंट को पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए । ये चीजें कम्पलीकेसी पैदा करती हैं अगर इसको गवर्नमैंट पैट्रोनाईज करती है । स्पीकर साहब, मेरा लास्ट प्वांयट है, यह बड़ा इम्पौर्टेट प्वांयट हैं । मैं लखनऊ से बड़े पैशन लेकर आया । हमारे प्रधान जी भी साथ थे और चौधरी मेहर चन्द जी भी साथ थे । हम जव वहां दाखिल हुए तो हमने उनसे पूछा कि कितने एम० एल० ए ० डिटैन्शन में हैं? जितनी तादाद उनकी है, उसके मुताबिक हम हैरान रह गए यह जान कर कि यू ० पी० में बहुत थोड़े एम० एल० ए० डिटैन्शन में हैं । फिर हमने पूछा कि एम० प्ल० ए ० को अलाऊंस क्या मिलता है? उन्होंने कहा कि जो इलैक्ट हो कर आता है उसको 1,000 रुपया तन्खाह पूरी की पूरी मिलती है । हम यह जानकर भी

हैरान रह गए । इसलिए हरियाणा में जो पकड़े हैं उन को छोड़ दिया जाए । वे तो बगैर सींग की अपोजीशन है । यह अपोजीशन क्या सींग मारेगी? अगर ये सारे एम ० एल० एज ० छोड़ दिए जाएं तो एक हैल्दी ट्रैडिशन होगी, गुप्ता लायक ट्रैडिशन होगी । मैं गुप्ता जी से फिर रिक्वैस्ट करूंगा कि सभी एम० एल० एज० को छोड़ दिया जाए । वे सब यहां मौजूद होने चाहिए । कितना अच्छा हो यदि अपोजीशन यहां बैठी हो! बगैर अपोजीशन के हाउस को रन करना तो ऐसा है जैसे एक ही टीम कबड्डी खेले, हो हो करके अपनी साईड में वापिस आ जाए और दूसरी तरफ उनको रोकने वाला कोई न हो ।

श्री के० एन० गुलाटी : ऑन ए प्वांयट आफ आर्डर, सर । दौलता साहब बगैर अपोजीशन के कैसे कह सकते हैं । ये यहां बैठे भी हैं और बोले भी हैं ।

Mr. Speaker : This is no point of order.

चौधरी प्रताप सिंह दौलता : स्पीकर साहब, कम से कम एक आधे को तो सजा दे दो ताकि इन्हें प्वांयट आफ आर्डर क्या होता है इसका पता लग जाए और हाउस रन करना आ जाए ।

तो मैं अर्ज कर रहा था कि कम– से कम डिटैन्शन होना चाहिए और उन लोगों को अलाउन्स जरूर मिलना चाहिए जो डिटैन्शन में हैं । (घंटी) मैं तो रेडी हो गया है और जल्दी ही वाइन्ड–अप कर रहा हूं । स्पीकर साहब, मैं गुप्ता जी की

नेकनीयत को डाउट नहीं करता लेकिन मेरे रोंगटे खड़े हो गए जब उन्होंने फूलचन्द जी को जवाब दिया । उन्होंने कहा कि जो लोग मीटिंगें करते हैं उन लोगों को तो डिटेन करना ही पड़ता है । मेरी प्राईम मिनिस्टर कई बार यह बात बता चुकी हैं । मैं बड़ा हामी हूं ऐमरजैसी का लेकिन अगर यह ऐमरजैन्सी फेल होगी तो यह होगी इसके रौंग यूज से । होना यह चाहिए कि जो पार्टीज बंद हैं या जिनका अमेरिका से सम्बन्ध है या जो इंटैलिजैन्स एजैन्ट हैं, उनको छोड़ कर बाकी सब को मीटिंगें करने का हक हो । उनको बिना किसी खास वजह से नहीं पकड़ना चादिए वरना फासिज्म कायम हो जाएगा । बचे कौन रह जाएंगे, आर० एस० एस० के वर्कर्ज जो अन्डर ग्राउन्ड होना जानते हैं, सी० पी० आई० (एम ०) वाले जो इस काम में माहिर हैं । डैमोक्रेटिक फोर्सिज को, डैमोक्रेटिक पार्टीज को आपको फंक्शन करने की इजाजत देनी चाहिए वरना मुल्क सीधा सिविल वार की तरफ जाएगा । एक तरफ आपकी आर्मी होगी और दूसरी तरफ अन्डरग्राउन्ड वर्कर्ज होंगे । Democracy will be a big failure by misuse fo emergency बी० एल० डी० आदि पार्टीज को आप खुला बोलने दें, इनको जलसे करने दें क्योंकि हम भी ख्यालों में या ताकत में किसी से कमजोर नहीं । इन पर यह पाबन्दी बेकार है । इन पार्टीज को फंक्शन करने की इजाजत दे दी जाए । स्पीकर साहब, जो आर्थिक चोर हैं, जो इकनौमिक चोर हैं उन के लिए शुरू में मिजा बना था । प्राईम मिनिस्टर इन्दिरा गांधी ने मोरार जी देसाई को एक पत्र भी लिखा था कि I will use it only against smugglers. उन

पररियायत नहीं होनी चाहिए । इस हाउस के नोटिस में भी एक बात लाई गई थी कि हिसार की एक फर्म ने हरिजनों के नाम से 22 ट्रैक्टर्ज लिए और ब्लैक मार्किट में बेचे और हरिजनों को एक नहीं मिला । इस बात को हाउस के नोटिस में लाने वाले इसी हाउस के एक आनरेबल मैम्बर, चौधरी पीर चन्द थे जो आज भी यहां मौजूद हैं । मिजा उनके खिलाफ इस्तेमाल करें या करें उन वकीलों के खिलाफ, चौधरी प्रताप सिंह दौलता जैसे वकीलों के खिलाफ, जो इन्कम टैक्स की चोरी कराने में लोगों की मदद करते हैं, जिनके खिलाफ फाइलों में और आफिशियल रिकार्ड में ऐविडैसं मौजूद है । ऐसे लोगों के खिलाफ मिजा का प्रयोग न करना, स्पीकर साहब, मिजा की तौहीन है ।

श्री के० एन ० गुलाटी (फरीदाबाद) : स्पीकर साहब, मैं अपने चीफ मिनिस्टर, फाईनैन्स मिनिस्टर और कंसर्न्ड आफिशियल्ज को मुबारिकबाद देता हूं कि उन्होंने बजट बहुत अच्छा बनाया । घाटा तो है मगर टैक्स कोई नहीं, इसके लिए मैं इन्हें हार्दिक मुबारिक– बाद देता हूं । स्पीकर साहब, कुछेक सात्न से बजट बहुत अच्छा और शानदार आ रहा है । जिन्होंने इसे क्रिटिसाइज किया हए उनसे मैं रिक्वैस्ट करूंगा कि वे ख्वामखाह गलत क्रिटिसिज्म न किया करें, सच्चाई की तारीफ किया करें और जो सुझाव देने हों उन्हें दिया करें ताकि हरियाणा तेजी से आगे बड़े । मैं इतना कहना चाहता हूं कि work is workship के निशाने से ही हम आगे बढ़ सकते हैए वरना बिल्कुल आगे नहीं बढ़ेंगे

पीछे ही आएंगे । मैं तो यह कहना चाहता हूं कि ––

खुदी को कर बुलन्द इतना कि हर तकदीर से पहले

खुदा बंदे से यूँ पूछे बता तेरी रजा क्या है ।

यहीं बस नहीं :––

मिटा दे अपनी हस्ती को गर तू मरतबा चाहे ।

कि दाना खाक में मिल कर गुले गुलजार होता है ।

हम कामों से आगे बढेगे । केवल बातों से कोई आगे नहीं बढ़ सकता।

स्पीकर साहब, मैं टाईम के मुताबिक ही कुछ चन्द बीतें अपने हल्के की जल्दी–जल्दी कहता हूं और हाउस तथा मिनिस्ट्री, का ध्यान उनकी तरफ दिलाता हूं । सबसे पहले मैं चाहूंगा कि फरीदाबाद, बल्लभगढू, होडल और पलवल आदि को मिलाकर हरियाणा का बारहवां जिला बना दिया जाए । 26 जनवरी नजदीक आ रही है । उस दिन इसकी अनांउसमैंट कर दी जाए ।

स्पीकर साहब, मेरे हल्के में बहुत सारी झुग्गी झोंपडियां हैं । उनको एक सैक्टर दे दिया जाए । बहुत सारे सैक्टर गैर–आबाद पड़े है । अगर एकु सैक्टर उनको अलौट कर दिया जाए तो झुग्गी झोपड़ी वाले अपने मकान वहां बना लेंगे । मेरी सरकार से प्रार्थना है कि बीस सूली कार्यक्रम के अन्तर्गत पच्चीस

पच्चीस या पचास पचास गुज के प्लेट उन्हें जल्दी से जल्दी दे दिए जाएं ताकि वे भी आराम से रह सकें ।

स्पीकर साहब, फरीदाबाद एक इंडस्ट्रियल एरिया है । वहां बी० एड, एम० एस० सीय एम० कौम और एल० एल० बी० की हायर क्लासिज का भी इन्तजाम किया जाए ।

स्पीकर साहब, फरीदाबाद बल्लभगढ में लोकल बसों की लोगों को बड़ी तकलीफ हैं । अगर फरीदाबाद कंप्लैक्स को मिनी बसें चलाने की इजाजत दे दी जाए तो लोकल बसों कीं तकलीफ खत्म हो जाएगी ।

स्पीकर साहब, कुछेक लिंक रोडज भी वहां बड़े जरूरी हैं । उनके नाम हैं रू––

1. ताजूपुरा–खेडी–ओल्ड फरीदाबाद ।

2. मथुरा रोड़ टू एतमादपुर विलेज ।

3. एक पाली रोड़ भी हे, जो कि बहुत पुरानी है और जिसका जिक्र मैं हमेशा करता हूं । पाली रोड़ के बारे में हमारे पुराने मुख्य मती और मौजूदा भारत के रक्षा मैली चौधरी बंसी लाल जी ने 1972 के सैशन में अश्योरैन्स दी थी । मै पी० डबल्यु० डी० मिनिस्टर साहब से और नए मुख्य मली जी से प्रार्थना करूंगा कि उनकी दी हुई अश्योरैन्स को जल्दी से जल्दी पूरा कर दिया जाए ।

स्पीकर साहब, प्रौविडैन्ट फंड की एक स्कीम बन रही है जिसके तहत एक अलग दफ्तर फरीदाबाद में होगा । उसको भी जल्दी से जल्दी इम्पलीमैंट करा दिया जाए यह मेरी सरकार से प्रार्थना है ।

(इस समय सभापतियों की सूची में से एक सदस्य चौधरी ईश्वर सिंह पदासीन हुए)

चेयरमैन साहब, मैं अपने चीफ मिनिस्टर साहब और फाईनैन्स मिनिस्टर साहब से यह' भी प्रार्थना कर देना चाहता हुं कि प्रोफैशनल टैक्स को खत्म कर दिया जाए । इसकी थोड़ी आमदन है और खर्चा स्टाफ पर ज्यादा हो जाता है । जो ताकत सरकार इस पैसे को इकट्ठा करने में लगाती है उसे टैक्स के दूसरे एरीयर्ज को इकट्ठा करने में लगाया जाए । पूरे टैक्स वसूल करने में लगाया जाए । अगर ऐसा करना संभव न हो तो जिस तरह बीस सूती कार्यक्रम के अन्तर्गत इन्कम टैक्स की लिमिट को 6 हजार से उठाकर 8 हजार कर ' दिया गया है उसी तरह से से यी भी 8 हजार की बजाय दस हजार रुपए की आमदनी दर चार्ज हो क्योंकि यह भी बीस सूली कार्यक्रम से ही सम्बन्धित है । इससे प्राईवेट सैक्टर और पब्लिक सैक्टर के बहुत से मुलाजिमों को फायदा होगा । मजदूरों को फायदा होगा ।

चेयरमैन साहब, मेरे फरीदाबाद में बड़ी तरक्की हुई है लेकिन सैनीटेशन का प्रबन्ध अभी थोड़ा खराब है । इसे जल्दी से

ठीक कराया जाए । वाटर सप्लाई के बारे में भी मैं. कहना चाहता हूं कि इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड का दस लाख क्युबिक फीट वाटर रोजाना जमीन में फैक दिया जाताहै । कह यूं ही जाया जाता है । कंप्लैक्स उस पानी को मांग रहा है लेकिन अफसरान का कोआर्डिनेशन न होने की वजह से वह नहीं मिल रहा है । अगर पब्लिक हैल्थ वाले

कंप्लैक्स वाले और दूसरे अफसरान बैठकर कोआर्डिनेशन कर लें और दस लाख क्यूबिक फ्लेट वाटर को, जिसेवे फजूल में फैकते हैं, कंप्लैक्स को दे दें तो पीने के पानी का सिलसिला भी वहां ठीक हो सकता है ।

चेयरमैन साहब, फरीदाबाद बल्लभगढ की सड़क से लेकर रेलवे स्टेशन तक कोई लिंक रोड नहीं है । बड़ी दूर से जाना पड़ता है । बीच में फाटक है । काफी देर तक वहां रुकना पड़ता है । इससे बड़ा समय खराब होता है । अगर यहां छोटी–सी डायरैक्ट पक्की सड़क बना दी जाए तो मुसाफिरों को काफी सहूलियत मिलेगी ।

चेयरमैन साहब, मेरी यह भी प्रार्थना है कि तीन सौ रुपये माहवार से कम आय वाले जितने भी परिवार हैं उनको कोई टैक्स नहीं लगना चादिए । उनको की ऐजुकेशन और फी इलाज दिया जाए ।

चेयरमैन साहब, होम डिपार्टमैंट से आपकी मारफत मैं

अर्ज करूंगा कि फरीदाबाद और बल्लभगढ में पुलिस की जो चौकियां हैं उनमें स्टाफ कम है । वहां प्रैजैन्ट शड्यूल के मुताबिक स्टाफ नहीं है । इसे पूरा किया जाए । पांच नम्बर और पन्द्रह नम्बर सैक्टर के थानों की मथुरा रोड को बाउंडरी मानकर रीऐलोकेमन की जाए ताकि नजदीक का इलाका' नजदीक के पुलिस स्टेशन में जाकर अपनी फरियाद सुना सके । मेरी यह भी प्रार्थना है कि फरीदाबाद को बजाय चौकी के रेलवे जी० आर ० पी ० का थाना बनाया जाए । मेरे हल्के में चार नम्बर चौकी, पांच नम्बर चौकी, मुजसर चौकी और सी० आई० पुलिस चौकी है वहां पर कोई भी टेलीफोन की सुबिधा नहीं है । अगर कोई हादसा हो जाता है तो वहाँ एम० एल० ए० वगैरह को जाना पड़ता है तो जिसके साथ हादसा होता है वह उसको टेलीफोन भी नहीं कर सकता है । इसलिए मेरी सरकार से गुजारिश है कि वहां पर टेलीफोन का प्रबन्ध किया जाये । चेयरमैन साहब, मेरे हल्के में लेबर कोर्ट की बड़ी भारी तकलीफ है । लेबर कोर्टको फैसला करने में बड़ा टाईम लगता है । इसलिए वहां पर दूसरी लेबर कोर्ट भी बनायी जाये । दूसरे वहां पर लेबर कोर्ट के फैसले इम्पलीमैंट नहीं होते हैं । लेबर कोर्ट को इंडिपैन्डैन्ट पावर दी जाये । कई केसिज में बड़ी देर हो जाती है क्योंकि उनके फैसले इम्पलीमैंट नहीं होते हैं। उनको सिविल कोर्ट में जाना पड़ता है । फरीदाबाद में लाल जी फैक्टरी के पांच वर्करज के केसिज हैं जिनके नाम हैं रमेश, मूलचन्द, बदलू होर भाटिया और रधुबीर तथा इनका अमाउन्ट है, 3100, 900, 1629, 1060 और 232 रुपये

। इन केसिज का फैमला सन् 1974 मे हुआ था लेकिन अभी तक इम्पलीमैंट नहीं हुआ । उनको सिविल कोर्ट में जाना पड़ता है । तो ऐसी पावर्ज लेबर कोर्ट को दी जाये जैसे सेल्ज टैक्स वालों को दी गई हैं कि वहीं पर कैश ले लेते हैं । तो मैं यह कहूंगा कि लेबर के फैसले होने के बाद पेमैन्ट एकदम हो जानी चाहिए ।

फरीदाबाद और बल्लभगढ में एल० ओ०–कम–सी० ओ० का आफिस भी होना चाहिए ।

अब मैं जनरल ऐडमिनिस्ट्रेशन के बारे में कहना चाहता हूं । टीचर्ज की ट्रांसफर केवल अप्रैल के महीने में होनी चाहिए, 11 महीने बन्द होनी चाहिए । उनके लिए क्वार्टर का प्रबन्ध 'किया जाये । जहां पर क्वार्टरज नहीं हैं, वहां ऐम्पलाइज नहीं जातेहैं । ट्रांसफरज जो किये जातेहैं, उसमें बच्चो की पढ़ाई का ख्याल रखा जाना चाहिए ।

दूसरे, दफ्तरों में टाईम का भी ख्याल रखा जाना चाहिए । किसी अफसर को मिलने का टाईम फिक्स होना चाहिए लन्च से पहले या लन्च के बाद । टाईम और पंकच्युलिटी का खास ख्याल रखा जाना चाहिए ।

तीसरी बात ऐम्पलाइज के बारे में कहना चाहता हूं । खास तौर से ऐजुकेशन डिपार्टमैंट के जो ऐम्पलाइज हैं उनका प्रोविडेन्ड फन्ड में जो पैसा कटता है उसका सही हिसाब किताब नही रखा जाता है । इसके लिए पास–बुक्स इशू की जानी चाहिए

। कभी कोई गलती बिल मेंहो जाती है तो सात सात महीने तक उनको अलाउत्स वगैरह भी नहीं मिलते हैं । दूसरे मैं यह भी कहना चाहता हूं कि हर ऐम्पलाइज को मैडिकल फैसिलिटीज, हाउस रैन्ट, डी० ए ० सब बराबर मिलना चाहिए चाहे कोई देहात में पढ़ाता है चाहे कोई शहर में न!।करी करता है । ये बातें जनरल होनी चाहिए ।

ऐजुकेशन डिपार्टमैंट में तीन महीने से ज्यादा छुट्टी नहीं होनी चाहिए । 12 महीने में पांच महीने छुट्टियां रहती है । सन्डे और दूसरी गजटिड छुट्टियां मिला कर तीन महीने से ज्यादा नहीं होनी चाहिए । इतना कह कर मैं अपनी जगह लेता हूं और आपका शुक्रिया अदा करता हूं । बजट अच्छा है और प्रदेश की भलाई के लिए है ।

डाक्टर ओम प्रकाश शर्मा (जगाधरी) : आदरणीय चेयरमैन साहब पिछले दो दिनों से सदन में बजट पर चर्चा चल रही है । विपक्षी दल के नेता और ट्रेजरी बैचिज के मेम्बरान दोनों अपना अपना नजरिया पेश कर रहे हैं । सब से पहले मैं अपने वित्त मती साहब को बधाई देता हूं कि मौजूदा बजट को मौजूदा हालात का बेहतरीन बजट करार दिया जा सकता है । चेयरमैन साहब, मैं इस सदन का चार साल से मैम्बर हूं । मैं यह महसूस करता हूं कि हमारा बजट हर साल ज्यादा से ज्यादा बढ़ रहा है, उसका बोझा हमारे ऊपर बढ़ रहा है । उसका एक कारण है जिसके बारे मैं अर्ज करना चाहता हूं । हमारी जितनी भी प्लानिंग

हैं जिनके बारे में सदन में बार बार चर्चा होती है उनमें से एक फैमिली प्लांनिग भी है । जो बढती हुई आबादी है उसको किस प्रकार से रोका जा सकता है । काफी समय पहले स्वामी रामतीर्थ ने एक बात कही थी कि जिस देश की आबादी बढती है वह देश बड़ा बदकिस्मत है, उससे बदकिस्मत कोई देश हो नहीं सकता । तो जो हालात हैं उनके अनुसार बढ़ती हुई आबादी हमारी इकोनौमी के लिए बडा भारी खतरा बनी हुई है, हालात नाजुक हैं । चेयरमैन साहब समय थोड़ा है इसलिए मैं यह सारी बात एक शेर में अर्ज कर देता हूं ।

ना कुछ–खा के मरा हूं न किसी रोग से मरा ।

ये कसरते औलाद से तंग आ के मरा है ।

चेयरमैन साहब, हालात ऐसे होने जा रहे हैं कि आजकल परसुएशन से मकसद हल नहीं हो सकता । सरकार को चाहिए और मैं मुख्य मैली जी से भी अपील करूंगा कि वह इसके बारे में सख्त कानून बनाये, लीगलाइजेशन के बगैर यह मसला हल नहीं होगा । हमारी इकोनौमी खतरे में है और यह खरतरा रोज–ब–रोज बढ्ता जा रहा है । यह खतरा ऐसा है जिसका और कोई इलाज नहीं है । चेयरमैन साहब, कहने को बातें तो बहुत सी हैं लेकिन समय बहुत थोड़ा है इसलिए सब बातें नहीं कह पाऊंगा ।

चेयरमैन साहब, सब से पहले तो मैं यह खुशी महसूस

करता हूं कि हम सब मिल जुलकर अपनी स्टेट, अपने मुल्क से गरीबी को दूर करने की कोशिश में जुटे हुए हैं । अब मैं महसूस 'करता हूं कि हमारे लिए नई रोशनी की राहें नजर आने लगी हैं । जो नई 'राहें दिख रही हैं वे हमारी प्रधान मंत्री ने बताई हैं । ऐमरजैन्सी के हालात के अन्दर जो रोशनी हमारे सामंने हैं वह हमारी प्रधान मैली जी का बीस सूली प्रोग्राम है । वक्त थोड़ा . है और इस थोड़े वक्त में हमें इस बीस सूती प्रोग्राम को लागू करना है । यह प्रोग्राम ऐसे समाज का निर्माण करेगा जिसको हम समाजवादी समाज कह सकेंगे, जिसको हम जनतंत्र का समाज कह सकेंगे ।

अब मैं अपने जाने वाले मुख्य मंत्री और मौजूदा चीफ मिनिस्टर साहब के बारे में अर्ज करना चाहता हूं । हमारे जाने वाले चीफ मिनिस्टर की हरियाणा पर एक अमिट छाप 'है । उन्होंने जो हरियाणा के लिए किया है उसको कोई भी हरियाणावासी भूल नहीं सकता । सन्, 1967 में भी मुझे सदन का मैम्बर रहने का मौका मिला है । उस वक्त स्टेट की क्या हालत थी और आज स्टेट की क्या हालत है । यह किसी से छुपी नहीं है । उस वक्त हमारी स्टेट बैकवर्ड और डेफिसेट स्टेट कहलाती थी । हर लिहाज से बैकवर्ड और डेफिसेट स्टेट थी । यहां पर न पानी था, न इन्डस्ट्री थी, न कोई साधन थे और न ही कोई चीज थी । थोड़े से ही अर्से के अन्दर मुख्य मंत्री चौधरी बंसी लाल जी ने इस स्टेट को इतना ऊंचा उठाया' कि सारे भारतवर्ष के अन्दर आज यह सूर्य

की तरह से चमक रही है । अब हमारे नये मुख्य मत्री श्री गुप्ता जी बहुत आलापाया दिमाग के मालिक हैं, बुद्धिमान हैं, बड़े दूरअन्देश हैं । अगर हम सब लोग उनको इकट्ठे हो कर स्पोर्ट करें तो हमारी जितनी भी समस्यायें हैं चाहे वे इकोनोमिकल हैं, चाहे वे सोशल समस्यायें हैं वे हल हो सकती 'हैं । हमारे नये मुख्य मत्री इतने काबिल हैं कि तमाम मुश्किलात पर काबू पा करइसं हरियाणा को ऐसी जगह पहुंचा देंगे जिसका मुकाबला कोई भी प्रान्त नहीं केर सकेगा । जिन बातों को चौधरी बसी लालु ने पूरा करने की कोशिश की थी और जो अधूरी रह गई हैं उनको पूरा करने में हमारे मुख्य' मती, श्री गुप्ता जी पूरी तरह से कामयाब होंगे । चौधरी बंसीलाल जी का हरियाणा के निर्माण में जो हिस्सा है, उसमें कुछ हिस्सा हमारे मौजूदा मुख्य मंत्री गुप्ता जी का भी है ।

आदरणीय चेयरमैन साहब, टाईम थोडा है इसलिये मैं– कोई लम्बी–चौड़ी बात नहीं अपने हल्के के बारे में एक दो बात आपके 'द्वारा 'सरकार से जरूर कहूंगा ।

जहां हमारा हरियाणा मुल्क के आसमान पर चमक रहा है वहां इसमें एक छोटा सा ग्रहण लगा हुआ है और वह ग्रहण सामने से नजर नहीं आता । चेयरमैन साहब, जगाधरी शहर वैसे भी हरियाणा की बैक पर है । वहां पर अगर कोई आदमी हरियाणा से बाहर से नींद की हालत में कार में बैठकर आ जाये और उसकी आंख सिविल हास्पिटल जगाधरी में खुले तो मैं समझता हूं

कि वह उस हास्पिटल को देखकर यह कहेगा कि यह जो हरियाणा की प्रगति या डिवैल्पमैंट के बारे मे इतना कुछ ढोल पीटा जा रहा है, यह सब कुछ एक ढोंग है । हमारे जिले के फार्मर सिवल सर्जन और मौजूदा हैल्थ के सबसे बड़े और आला आफिसर तशरीफ फरमां हैं । उन्होंने उसका मुआयना बहुत बार किया है । हमारे विल मती जी भी एक दो बार उस हास्पिटल में हो आये हैं । विल मती साहब ने पिछले दिनों चीफ मिनिस्टर साहब को एकनोट लिखा था और उसमें उन्होंने उस हास्पिटल की एक सही पिक्चर लिखकर भेजी । मुझे यह कहते हुए शर्म आती है कि उस सिविल हास्पिटल के अन्दर सिर्फ एक लेटरीन है जोकि मेल और फीमेल दोनों के लिये है । इसके अलावा, जहां एक लेटरीन है वहां उसके साथ ही कोई गुसलखाना नहीं है । पीने के पानी का वहां कोई इन्तजाम नहीं है और अस्पताल की बिल्डिंग आज से सौ साल पहले अंग्रेजों के जमाने की बनी हुई है । पहले वहां सिविल रैस्ट हाउस. होता था । उसकी छतें टूटी हुई हैं और उसको हम सही ढंग से बिल्डिंग नहीं कह सकते, वह बिल्डिग खतरनाक पोजीशन में हैं मैं यह अर्ज करूंगा कि आप गुप्ता साहब से यह कहें कि वह अपनी तरफ से किसी आफिसर को नियुक्त करें जो वहां पर सरप्राइज विजिट करे और यह देखे कि आपके डाक्टर और अमला उस हास्पिटल के अन्दर कैसे काम कर रहे हैं । न वहां सर्दी का आराम, न गर्मी का आराम और न बरसात का आराम । डाक्टर के दिमाग को एक बहुत अच्छे माहौल में रहना चाहिए ताकि वह अपने पेशैन्ट्स के लिये सही ढंग से एडवाइस दे सके ।

मरीज की जिन्दगी का मसला डाक्टर के सामने दरपेश होता है । उसे ऐसा वातावरण ऐसा माहौल चाहिए कि वह अच्छे ढंग से, ठण्डे दिल से प्रैसक्रीपशन पेशैन्ट्स के लिये दे सके । अगर वहां माहौल ही ऐसा है तो अच्छे से अच्छे डाक्टर का दिमाग भी खराब हो जायेगा । चेयरमैन साहब, यह सिविल हास्पिटल तो दरअसल नाम का ही हास्पिटल है । पहले यह सरकार का नहीं था, यह म्युनिसिपल हास्पिटल था । पिछले अन्दाजन 7–8 साल से शायद 1988 से हरियाणा सरकार ने टेक–ओवर कियाहै । 7–8 साल का अर्सा होचुका है लेकिन उसके बावजूद भी इन कमियों को दूर नहीं किया गया । (इस समय अध्यक्ष महोदय पदासीन हुए) म्युनिस्पिल कमेटी का जो अस्पताल था, वह 1966–67 में जहां होता था वह बिल्डिंग अब गिर चुकी है । वहां से उठाकर इसको सिविल रैस्ट हाउस, जगाधरी में ले जाया गया जिसकी बिल्डिग आज से सौ साल पहले की बनी हुई है । पहले जहां होता था, वहां पर इसकी हालत अच्छी थी । मुझे इसका यूं पता है कि 1963, 64, 65, और 88 में मुझे म्युनिस्पिल कमेटी का प्रैजीडैन्ट रहने कामोका मिला था और इस अस्पताल की देख–रेख कमेटी के पास होती थी । उस समय इसकी हालत आज से कहीं बेहतर थी । जब से यह सिविल हास्पिटल सरकार के पास आया है, यह हास्पिटल नहीं रहा । आज जो वहां वैटर्नरी हास्पिटल है, वह उससे कहीं ऊपर दर्जे पर है । यह कोई अच्छी बात नहीं लगती । मैं आपके द्वारा मुख्य मैली साहब से रिक्वैस्ट करूंगा कि वे जगाधरी के लोगों का ख्याल रखते हुए, जगाधरी तहसील के

निवासियों और जगाधरी के 4 हल्कों का ख्याल रखते हुए किसी वक्त उस हस्पताल को विजिट करें और यह देखें कि 'क्य हास्पिटल की हालत क्या है । स्पीकर साहब, एक और बात, है तो छोटी सी, लेकिन 'मैं अपने इलाके के काश्तकार के बारे में कहना चाहता हूं और बहु बात गन्ने से मुताल्लिक है। मेरे जिले में एक ही गन्ना मिल है । साथ वाले जिला कुरुक्षेत्र के लिये भी एक यही मिल है । इस मिल का नाम सरस्वती शुगर मिल है । आप बखूबी जानते हैं कि जो उस सरस्वती मिल का असाइन्ड एरिया है, जिस एरिया का गन्ना उस मिल में जाता है, उसमें बड़ा हिस्सा तहसील जगाधरी का है । तहसील जगाधरी का काश्तकार जो गन्ना पैदा –करता–है, उसकी कई समस्याएं हैं, कई मुश्किलात हैं और वह मुश्किलात मैं आपके नोटिस में लाना चाहता हूं । मैं आशा रखता हूं कि मेरी यह बात सरकार द्वारा सुनी जायेगी । कभी हालत ऐसी होती है कि गन्ना सरप्लस हो जाता है और कभी हालत ऐसी होती है कि गन्ना किल्लत में चला जाता है । जब मौसम साथ देता है, वक्त पर पानी मिल जाताहै 'बिजली बगैरा की हालत भी ठीक होती है तो गन्ना सरप्लस हो जाता है और जब मौसम ठीक नहीं होता तो गन्ना स्केयरसिटी में चला जाता है । इस साल जो गन्ने की प्रोडक्शन सरस्वती मिल के असाइन्ड एरिया में है, उसकी पैदावार का अन्दाजा एक करोड़ 34 लाख स्विंटल का है । पिछले साल सरस्वती शृगर मिल यमुनानगर ने 84 लाख क्विटल गन्ना क्रश किया था और इस साल जो गन्ना क्रश करने की हद केन कमिश्नर, हरियाणा के द्वारा अलाटकी गयी है वह 85 लाख क्विंटल

हैजबकि पिछले साल मिल 84 लाख क्विटल गन्ना क्रश कर सकी । इस बार मिल वालों को यह सहूलियत दी गयी है कि वह पहले सेभी कम गन्ना क्रश करें जबकि गन्ना सरप्लस है । आपको पता है गन्ने से चीनी बनती है और चीनी हमारे देश को फारेन ऐक्सचेंज देने वाली है । चीनी से हमारे देश को फारेन ऐक्सचेंज मिलता है बजाय इसके कि हमारे केन कमिश्नर साहब या हमारे सैक्रेटरी ऐग्रीकल्चर मिल को यह हिदायत करते कि वह बजाय 84 लाख क्विटल के, इस साल 90 लाख क्विटल गन्ना क्रश करें, उन्हेंने और कम गन्ना क्रश करने की अलाटमैंट की । जहां तक मुझे मालूमहैवहशूगर मिल 90 लाख क्विंटल से भी अधिक गन्ना क्रश करने की अहलीयत रखती है । स्पीकर साहब, इतना ही नहीं हुआ (घंटी). स्पीकर साहब, मुझे पांच मिनट और दे दें । मैं तो काश्तकार नहीं हूं लेकिन आप तो काश्तकार के बेटे हैं । कम सेकम मुझे आपके राइटके लिये तो बोलने दीजिये । मुझे 4— 5 मिनट और दे दीजिए । स्पीकर साहब, उस पर भी काश्तकार के साथ एक जुल्म हुआ । स्पीकर साहब, जब गन्ना सरप्लस हो जाता हैतो सरकार एक फारमूला बनाती है कि काश्तकार ने जों पिछले तीन वर्ष में गन्ना सप्लाई किया है उसका तीन साल का पडता फिक्स कर देती है यानी तीन साल की सप्लाई के आधार पर एक फारमूले के तहत एक पड़ता फिक्स करतीहै । स्पीकर साहब, यह एक ऐसी बात है जिसको खुलकर कहना चाहिए । मिल मालिक —जो हैं वे. सरकार और उसके कर्मचारियों को गुमराह करतेहैं । जहां तक केन कमिश्नर का सम्मन्ध है उनके बारे में ऐसा नहीं

सोचा जा सकता । सैक्रेटरी साहब कोमैं –जाति तौर परजानता हूं । केन कमिश्नर साहब हमारे यहां एस०.डी ०एम० रहे हैलेकिन इनके नीचे के जो अफसर हैंवे 'मिल मौलिकों से ऐसी फिगर लेतेहैं जिससे–सरकार गुमराह होती है और गन्ना काश्तकार को काफी नुक्सान होता है । इन्होंने पहले एलान कर दिया कि हम पिछले तीन साल के पडसे पर काश्तकार का गन्ना लेंगे लेकिन फिर 15 प्रतिशत का कट लगा दिया । स्पीकर साहब, जिन्होंने दो साल से गन्ना बोया, उनका क्या होगा, जिन्होनै एक साल से गन्ना बोया, उनके गन्ने लेने का कोई इन्तजाम सरकार की ओर से नहीं था । स्पीकर साहब, 24 जनवरी, 1975 को जनरल मैनेजर, सरस्वती मिल को एक लैटर इशू हुआ और उसमें यह कहा गया कि इस बार आप अपने जराय से तमाम काश्तकारों को यह इतलाह दें कि सरकार तीन साल. के पड़ते पर गन्ना लेगी । लेकिन स्पीकर साहब, उस लैटर की स्याही भी सूखी नहीं थीरू कि इन्होंने तीन साल के पड़ते पर 15 प्रतिशत की कट लगा दी । यह काश्तकार के साथ अन्याय है । आप काश्तकार को देखें कि पिछले साल चीनी का भाव 435 रुपए था और इस साल भी 435 रुपए है । आप देखें कि पिछले साल की गन्ने पर जो लागत आती थी वह आज बढ़ी है । ट्रैक्टर पहले से ज्यादा कीमत पर आता है, फर्टीलाइजर तेज है, बीज तेज है इम्पलीमैंट्स महंगे हैं, बिजली और पानी का रेट बढ़ा है, मजदूरी बढ़ी है । स्पीकर साहब कोई ऐसी चीज नहीं जिसकी कीमत न बढ़ी हो । पिछले साल यही गन्ना था, हमारी सरकार ने पौने चौदह रुपया क्विटल का

भाव दिया था और इस साल सरकार ने ग्यारह रुपए का रेट दिया मिल के दरवाजे पर और साढ़े दस रुपया का रेट दिया तुलाई के सेन्टर पर और इस पर भी मिल मालिक इतनी ज्यादती कर रहे हैं कि सरकार ने साढ़े दस रुपया फिक्स किया है उसके बजाए वे सवा दस रुपया प्रति क्विटल दे रही है । स्पीकर साहब, मेरे पास उस सवा दस की रसीद भी है । (घंटी)

श्री अध्यक्ष : आपने काफी समय ले लिया है आप फिर किसी टाइम पर बोल लेना ।

डाक्टर ओम प्रकाश शर्मा: स्पीकर साहब, जगाधरी एक बहुत ही पुराना इंडस्ट्रियल टाउन है । हमारे हरियाणा के एक्सचेकर को टैक्स की शक्ल में जगाधरी टाउन से बहुत पैसा मिलता है । जगाधरी हरियाणा के अन्दर दूसरे नम्बर पर है । लेकिन इतना रैवेन्यू देने के बावजूद, इतना टैक्स देने के बाद भी, हमारी बदकिस्मती है कि हमारे साथ सौतेली मां जैसा सलूक किया जाता है । जगाधरी की मंडी तमाम हिन्दुस्तान के अन्दर बर्तनों के लिए मशहूर है लेकिन इस सरकार ने इस इंडस्ट्री की तरफ कोई तवज्जुह नहीं दी मैं मुख्य मंत्री महोदय से रिक्वैस्ट करूगा कि हमारी तरफ भी कुछ नजरे–करम करें । हमारी उनसे स्पैशल रिक्वैस्ट है कि आप जगाधरी को एक हैवी प्लांट दे दें । बहुत मजदूर वहां बेकार हो रहे हैं क्योंकि मैटल इंडस्ट्री स्टेबल नहीं है । स्पीकर साहब, अगर आपकी मारफत हमको एक प्लान्ट मिल जाता है तो जहां हम मुख्य मनी साहब के आभारी होंगे वहां

आपको भी दुवाएं देंगे ।

मुख्य मंत्री (श्री बनारसी दास गुप्त) : अध्यक्ष महोदय, बजट पर कल से जो बहस चल रही है वैसे तो इसका जवाब वित्त मन्त्री जी ने देना है और कोई जरूरी नहीं था कि मैं बीच में हस्तक्षेप करता परन्तु अध्यक्ष महोदय मेरे सामने बैठने वाले मेरे कुछ दोस्तों ने कल कुछ ऐसे प्रश्न उठाये हैं कि उन पर बोलना मेरे लिये जरूरी हो गया है । चौधरी रिजक राम बोले और उन्होंने अनेक बातों की चर्चा. की । आप और हम सब जानते हैं कि बह एक सन्जीदा व्यक्ति हैं, पुराने पालिटीशियन हैं, पुराने पार्लियामेन्टेरियन हैं । उन्होंने अनेक प्रकार के महत्वपूर्ण विषय कल अपनी चर्चा में उठाए । मैं उनके सम्बन्ध में –कुछ बातें प्रस्तुत करना चाहता हूं । अध्यक्ष महोदय, जहां तक वर्मा जी का सम्बन्ध है, उन्होंने भी कुछ बातें कहीं लेकिन उनकी बातों का या उन्होंने जो आंकड़े पेश किए उनको मैं कोई विशेष महत्व नहीं देता । व्यक्तिगत रूप में वर्मा जी बहुत अच्छे आदमी हैं । लेकिन जिस पार्टी से, जिस राजनैतिक दल से उनका सम्बन्ध है उनका सारा मामला झूठ और धोखे पर आधारित है । इसलिये जो बातें तोड़ मरोड़ कर

चौधरी शिव राम वर्मा : आन ए प्वांयट आफ आर्डर, स्पीकर साहब, मुख्य मैली को ऐसी बातें कहना शोभा नहीं देती

परिवहन मंत्री (श्री के० एल० पोसवाल) : आपके लिए

तो कुछ नहीं कहा गया है ।

श्री बनारसी दास गुप्त : अध्यक्ष महोदय, मैंने पहले ही निवेदन किया है कि व्यक्तिगत रूप में वर्मा जी बड़े भले आदमी हैं, बड़े अच्छे आदमी हैं परन्तु दुर्भाग्य से उनका सम्बन्ध एक ऐसे दस से है और मैं समझता हू कि बहुत गहरा है भी नहीं (हंसी) क्योंकि अगर सम्बन्ध गहरा होता तो आज वह यहां नहीं बैठते । स्पीकर साहब, मैं यह अर्ज कर रहा था कि जिस पार्टी का आधार फासिज्म है, जिस पार्टी का आधार और तरीका यह हो कि हजार बार एक झूठ को दुहरा दिया जाए तो वह सच हो जाता है तो मैं उन बातों का जवाब क्या दूं? आजकल अध्यक्ष महोदय, आपात स्थिति में कई केसिज कई मामले व्यक्तिगत रूप से मेरे नालिज में हैं, मेरी जानकारी में हैं कि इन के दल के कुछ नौजवान साथी और बड़े उत्साही बर्कर जब जेल की सीखचों में बन्द किये गये तो उन्होंने माफी नामों पर अपने अंगूठे ही नहीं टेके मगर कागज के ऊपर चूतड़ के चूतड़ टेक दिये। उनके लिखित विश्वास दिलाने पर उन्हें बाहर निकाल दिया गया परन्तु उन्होंने बाहर निकलने पर उत्पात करना शुरू कर दिया । तो आप बताएं कि उनकी लिखित पर, जवान पर, बात पर, किस पर विश्वास किया जाए? अध्यक्ष महोदय, आन्दोलन तो हम भी किया करते थे, साम्राज्यवाद के साथ हमारी टक्कर थी और वह भी विदेशी साम्राज्यवाद के साथ । मैं सच्चाई के साथ कहता हूं कि हमारे दल का कोई व्यक्ति अगर जवानी तौर पर भी माफी मांग लेता था तो सभी उसे नफरत की

दृष्टि से देखा करते थे । उस से कोई बात नहीं करता था लेकिन आज इन के माफी नामों में, इनकी प्रतिज्ञाओं में और गंगा जल उठाने में भी कोई महत्व नहीं है । अध्यक्ष महोदय, इन्होंने जो बातें कल यहां पर कहीं, मैं समझता हूं कि उन में कोई आधार नहीं है ।

चौधरी शिवराम वर्माः स्पीकर साहब, मैंने तो इनकी किताबों से आंकड़े पेश किये हैं । अगर ये उन आंकड़ों को गल्त कहें तो मैं समझूंगा ।

श्री बनारसी द्रास गुप्त : अध्यक्ष महोदय, मैं आंकड़ों पर भी आऊंगा । वह सबर से बैठें । मैं तो थोड़ी सी भूमिका उस दल की बता रहाहूं जिस दल से मेरे दोस्त का सम्बन्ध है । जहां तक चौधरी रिजक राम जी का सम्बन्ध है उन्होंने 20 सूत्रीय कार्यक्रम का अपने भाषण में जिक्र किया और यह बात कही कि इस में कोई नई बात नहीं है । यह बात तो. अध्यक्ष महोदय मैं भी मानता हूं । बातें नई नहीं हुआ करती । आज के जमाने में बडी से बडी चीजों का जब आविष्कार किया जाता है तो हम सुनते हैं, मैंने वेद तो नहीं पढे लेकिन कहते हैकि वेदों के अन्दर भी इन सब बातों का जिकर है कि उस वक्त हवाई जहाज बनते थे. एटम ' बम्ब बनते थे, अस्त्र शस्त्र और कई चीजें इजाद हुई जिनको देखकर सुनकर हैरानी होती है लेकिन वेदों में कहते हैं उन सब की चर्चा हुई है । आज प्रधान मन्त्री ने आरने 20 सूत्रीय कार्यक्रम में जो कुछ कहा है, वह सब पुरानी बातें हैं लेकिन इस कार्यक्रम

का महत्व यह है कि हमारी प्रधान मन्त्री जी ने एक आदेश दिया है और हम दृढ़ प्रतिज्ञ हैं कि इसको इम्पलीमैंट करेंगे (तालियां) । अध्यक्ष महोदय, इस में नई बात यह है कि हम इस 20 सूत्रीय कार्यक्रम को बडे जोर के साथ, मजबूती के साथ इम्पलीमैंट कर रहे हैं । चौधरी रिजक राम जी ने अपने भाषण में नशाबन्दी की बात कही है । मैं समझता हूं कि सभी हमारे भाई इस बात से सहमत होंगे कि शराबखोरी एक लानत है इसको जितनी जल्दी दबाया जाए, खत्म किया जाए उतना ही अच्छा है । लेकिन मैं इस बात को मानता हू और शायद वह भी इस को मानते होंगे कि केवल कानून के द्वारा ही इस बुराई को समाप्त करना असम्भव है । जब तक सामांजिक तौर पर शराब के विरूद्ध घृणा उत्पन्न न करें और यह प्रण न करें कि हम इसे नहीं छुएंगे तब तक इस बुराई को खत्म नहीं किया जा सकता (तालियां) महाराष्ट्र तथा तमिल नाडू में नशाबन्दी का अनुभव अच्छा नहीं हुआ । हमारे प्रदेश में भी एक दो जिलों में नशाबन्दी लागू की गई थी । इसका परिणाम क्या हुआ कि लोग खूब पीते थे नाजायज शराब निकलती थी, ला एण्ड आर्डर की समस्या क्रियेट हुई! सरकार का रैवेन्यु कम हुआ । तो इस प्रकार नशाबन्दी लागू करने का क्या फायदा हुआ? क्या सरकार को धन की आवश्य– कता नही है? अगर सरकार को किसी साधन से धन आता है तो कोई बुरी बात नहीं है । सरकार कें खजाने में जौ पैसा आता है वह जनहित के लिये खर्च किया जाता है । अध्यक्ष महोदय, इस के साथ ही चौधरी साहब ने रिहायशी प्लाटों का जिकर शी अपने भाषण में

किया और यह कह दिया कि सरकार ने इस पर क्या खर्च किया, ग्रामों में शामनात जमीन थी उनमें से प्लाट काटकर दे दिये। ठीक बात है लेकिन सरकार के कोष में जो सम्पत्ति है! वह भी जोरना की है? सरकार जो जनता की– सरकार है, उसके पास जितना धन है, साधन हैं, यह–सब जनता के लिये है । अध्यक्ष महोदय, अभी पिछले दिनों प्लानिंग कमीशन कें साथ हमारी डिस्कशन हुई, हम ने अपने बड़े लम्बे चौड़े प्लान उनके सामने रखे तो उन्होंने हमें क्योकि आप भी अपने रिसोर्सिज से धन जुटाओ । अगर हम रिसोर्सिज उटाते हैं तो, किस के लिए योजनाबद्ध, विकास के लिए । तो इम लिये रेवैन्यु बढाने की तरफ जो हमारी ध्यान हैरू वह कोई बुरी बात नही है । आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह बात कहने को तैयार हूं कि इस सदन का कोई भी सदस्य अगर यह गारन्टी लेने के लिये तैयार है किं एक बार–प्रोहिबीशन का कानून बनने के बाद कोई इसके मुंह नहीं लगाएगा तो हम यह घाटा सहन करने के लिये भी तैयार हैं । लेकिन मुझे विश्वास है कि कोई भी सदस्य इे बातकी गारन्टी नहीं दे सकता । इस के बावजूद भी इस सदन को विश्वास दिलाता हू कि हमारें प्रधान मन्त्री का ध्यान प्रोहिबीशन की ओर है, नशाबन्दी की ओर उन्होंने कदम उठाया है. और जो 12 सूत्रीय कार्यक्रम इस उद्देश्य कैं लिये, उन्होंने बनाया है, हम हरियाणा प्रदेशमें उसका इम्पलीमैट करेंगे, हम किसी से पीछे नही रहेंगे (तालियां) । अध्यक्ष महोदय, इसके बाद चौधरी रिजक राम जो ने बांडिड लेबर की बात कही । मैं जिम्मवारी के साथ कहता हूं कि हरियाणा प्रदेश में बांडिड लेबर

की कोई समस्या नहीं । 20 सूत्रीय कार्यक्रम की बात, जिसका चौधरी साहब ने मजाक उडाया था, आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हू । चौधरी साहब कह रहे थे कि यह सब लोगों को झांसा देने की बातें कुंए, इस पर अमल नहीं हो सकता, ये सरकार सालों से ऐसी बातें कहती आ रही है । उन्होंने कोई सन् 53 की बात कह दी कि 53 में कांग्रेस ने कुछ कहा था और 55 की भी बात कह दी कि उस वक्त दस सूत्रीय अथवा पांच सूत्रीय प्रोग्राम पेश किये गये थे और भुवनेश्वर में हुए कांग्रेस के सैशन का भी जिक्र कर दिया । 55 में या 53 में जो बातें हुई उसके 17 साल बाद तक चौधरी साहब भी काग्रेस में रहे । अगर वह फैसला निरर्थक था तो उस वक्त उसका विरोध करते, साल भर, दो साल तक इन्तजार करते लगातार 20 साल तक उस पार्टी में रहे जिस पार्टी ने वह प्रोगाम बनाया था । लेकिन अब उनको होश आयौ 'कि यह प्रोग्राम थोथा है, अमली जागा पहनाने के लिये नहीं, केवल कोरी बातें करने का है । औपके द्वारा मैं यहां इस सदन को यह बताना चाहता हूं कि अब सरकार ने इम 20 सूत्रीय प्रोग्राम को लागू करने का लक्ष्य निर्धारित कर दिया है । उन्हेंने तो टाईम बाउंड प्रोग्राम बनाया है और यह टाईम बाउंड प्रोग्राम जून, 76 तक लागू हो जाना चाहिये मैं आपको दावे के साथ यह तो नहीं कहता कि इस काय' मैं हम शत प्रतिशत सफल होंगे लेकिन मैं यकीन दिलाता हूं कि इस प्रोग्राम को इम्पलीमैन्ट करने मैं हम और प्रदेशों से पीछे नहीं रहेंगे, उन से आगे ही रहेंगे । (तालियां) इन्होंने यह भी कहा कि कर्जों की वसूली में हमने कौन सा तीर मार दिया? एक

साल के लिये हमने वसूली मुलतबी कर दी तो इससे क्या फर्क पडता हए? लेकिन मैं आपके द्वारा इस सदन को यह विश्वास दिलाता हूं कि सिर्फ एकु साल के लिये हमने कर्जे' की वसूली मुलतबी नहीं की हम इसी सदन के, इसी सत में कादून भी बनाने जा रहे हैं जिससे ऐसे गरीब लोगों, देहाती भाइयों के कर्जे हम कानून के द्वारा माफ कर देंगे । (तालियां) उस माफी के अन्दर वर्मा साहब ने एक बात कह दी कि सरकारी कर्जे तो माफ नहीं किये गये, बैंकों के कर्जे भी माफ नहीं किये गये तो अध्यक्ष महोदय, आप स्वयं इस बात का अनुमान लगा सकते हैं कि यह कहां तक सम्भव है । बैंकों की ओर से हम कर्जा देते हैं, वह रिजर्व बैंक आफ इंडिया की तरफ से हमारे पास धन आता है और वह हमारे किसान भाइयों में खेती की उपज बढाने के लिये और अन्य धंधे चलाने के लिये कर्जा दिया जाता हद । उसके बाद कर्जे की वसूली करके रिजर्व बैंक आफ इंडिया को धन वापिस दिया जाता है । तो अगर इन कर्जों को माफ कर दिया जाए तो न हम रिजर्ब बैके को रकम वापिस कर पाएगे और न दोबारा हमें वहां से धन मिलेगा । जब तक यह सकुलेशन हम जारी नहीं रखेंगे तब तक हम किसान की सेवा नहीं कर पाएंगे । तो इसलिये बैक का कर्जा किसी भी प्रकार सरकार के लिए माफ करना सभव नहीं है । चौधरी साहब ने तुक बात कही, और वर्मा साहब ने उसका समर्थन किया कि वसूली के लिये जब गांव में जीप जाती हैं, तो लोग जलती हुई भट्ठी में भाग कर छुप जाते हैं । यानी गुड़ बन रहा है, भट्ठी जल रही है और लोग डरते हुए भट्ठी में घुस जाते हैं तो यह

बात तो चौधरी साहब ने ही देखी होगी कि जलती हुई भट्ठी में से भी लोग कैसे बच जाते हैं । यह ठीक बात है कि अधिकारीगण वसूली करते हैं और वसूली में कभी कभी सख्ती भी करते हैं क्योंकि बिना सख्ती से वसूली होती नहीं । मुझे यह कहते हुए गर्व है कि जहां तक लैड डिवैल्पमैंट बैक का प्रश्न है उसके द्वारा हम लौंग टर्न लोन देते हैं, अपने भाइयों को । मैं किसानो की इस बात में सराहना करता हूं कि उसमें हमारी शत–प्रतिशत वसूली होती है । अभी पिछले दिनों वर्ल्ड बैकं की एक टीम आई थी, उन्होंने तमाम. हिन्दुस्तान के बैकों का निरीक्षण किया था । उसके पश्चात् जो उन्होंने रिपोर्ट दी उस रिपोर्ट को जान कर हमें बड़ी खुशी होती है । उन्होंने बतलाया कि तमाम दुनिया में एक इजराइल को छोड़ कर हरियाणा की तुलना में भूमि विकास बैंक और कहीं नहीं हैं (तालियां) । आगे चौधरी साहब ने कहा कि आपने कर्जे क्या मुलतबी कर दिये लोगों के लिए मुश्किल पैदा कर दी, पहले गरीब आदमी किसी से कुछ कर्ज लेकर अपना काम निकाल लिया करता था लेकिन अब उसकी बात कोई नहीं सुनता । मैं उनकी यह बात मानता हूं कि काम तो वे जरूर निकाल लिया करते थे लेकिन वे कई तरह के फिजूल खर्चे के लिये भी कर्जा ले लेते थे जैसे विवाह शादियों के लिये । मुझे यह सब मालूम है क्यौंकि मैं तो ऐसे घर में पैदा हुआ हूं जहां ब्याह उटवाया करते थे । तो उसमें खर्च कितना होता था, और साहूकार कितना लिखता था इसका कोई हिसाब नहीं था । बनिया जमींदार का अंगूठा टिकवा लेता था । मैं यह बात कहने के लिये तैयार हूं कि

एक बार जिस का अंगूठा साहूकार की बही में टिक जाता था उसकी पीढियां भी उन्के चक्कर से नहीं निकल सकती थीं । तो साहूकार के चुंगल से निकालने के लिये, यह कर्जा माफ करने के लिये, इम सदन के द्वारा कानून बनाया जा रहा है और प्रधान मंत्री जी के आदेश से उनके बीस–सूत्री कार्यक्रम में यह बात शामिल है । लेकिन इसका आल्ट्रनेटिव प्रबन्ध क्याहो? यह बात उन्होंने ठीक कही कि कहां से वह गरीब जरूरत के वक्त कर्जा ले । अध्यक्ष महोदय, जो देहाती, जो हमारे भाई सीमान्त किसान हैं, मार्जिनल फार्मर हैं अथवा स्माल फार्मर हैं, उनको पिछले चार सालों में 18 करोड़ 31 लाख रुपया कर्जा दिया है सिर्फ स्माल फार्मर और मार्जनल फार्मर को, उसके अलावा हम दो तरह का कर्जा किसान कोदेते हैं एक लौंग टर्म लोन होता है और एक शार्ट टर्म लोन होता है । तो मैं लौंग टर्म लोन की बात करता हूं । जहां 1968–6 7 में हरियाणा में 59 19 लाख रुपये कर्जा दिया जाता था वहां 19 74– 75 में 1 129 72 लाख रुपये कर्जा दिया गया है यानी कहां 59. 19 लाख और कहां 1 129 72 लाख । इतना कर्जा हमने लौंग टर्म लोन का किसानों को दिया ट्रैक्टर खरीदने के लिये, ट्यूबवैल खरीदने के लिये तथा अन्य इम्पलीमैंट्स तथा कृषि के साधन उपलब्ध कराने के लिये । इसके अलावा हम काप लोन भी देते हैं । फसलों की पैदावार बढाने के लिये, किसानों की सहायता करने के लिये जो हम कर्जा देते हैं वह 1967–68 मैं जब चौधरी बंसी लाल जी की सरकार बनी 76798 लाख रुपये था और अब कितना दिया जाताहै? 371864 लाख । आप अन्दाजा लगा

सकते हैं कि कहां 787. 98 लाख और कहां 3718.64 लाख । तो इस प्रकार किसानों को कर्जा देने के लिये सरकार की तरफ से पूरा प्रबन्ध किया गया है। अध्यक्ष महोदय, यह भी आपको मालूम है कि पिछले दिनों भिवानी के अन्दर एक देहाती बैक खोला गया । प्रेजीडैटं आफ इंडिया ने एक स्पैशल आर्डिनैसं जारी किया कि किस प्रकार देहात के लोगों को कर्जों की सहूलियात दी जाएं । उस आर्डिनैसं के अन्तर्गत तमाम हिन्दुस्तान में चार बैक खुले । उनमें से एक बैंक हरियाणा में खुला और उस बैक की शाखाएं अब दूसरे जिलों में और दूसरे इलाकों में खोली जां रही हैं । अध्यक्ष महोदय, अभी अभी पिछले दिनों मैंने अनेक जगह इस प्रकार की स्टेटमेंट्स 'दी हैं कि हम सारे प्रदेश में 2000 मिनी बैक खोलने जा रहे हैं । आज जो हमारी क्रेडिट कोआप्रेटिव सोसाइटीज हैं उनकी संख्या 6000 के लगभग है । लेकिन उनमें बहुत ' सारी जैनुयन हैं और कुछ नहीं हैं यानी कुछ में काम होता है और कुछ में नहीं होता है और कुछ डिफालटर हैं । उनके सैक्रेटरी पार्ट टाइमर हैं, उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है, सारा 'हिसाब किताब सैक्रेटरी की जेब में होता है । तो इन सारी त्रुटियों को दूर करने के लिये हम ऐसे दो हजार बैंक खोल रहे हैं । जो वाएबल यूनिट हो । हर पटवार सर्कल में एक बैंक होगा । मल्टी पर्पज उसका काम होगा, होल टाइमर उसका सैक्रेटरी होगा और सुबह 9 बजे से सायं 5 बजे तक खुला रहेगा और वहाँ से हर देहाती भाई कर्जे की सहूलियत हासिल कर सकता है । इसके अलावा हमारें कुछ देहाती भाई, हरिजन भाई या बैकवर्ड क्लासिज

के हैं जिनके पास हुनर है लेकिन पूंजी नहीं है और साधन नहीं हैं । उन सबको साधन जुटाने के लिये तथा कर्जे देने के लिये, कच्चा माल देने के लिये और उनके तैयार 'माल को देश और विदेश में बेचने के लिए हम हैंडी क्राफ्ट और हैंड लूम कारपोरेशन बनाने जा रहे हैं जो देहात में रहने वाले दस्तकारों को हर प्रकार की सुविधाओं का प्रबन्ध करेगा । हमारे प्रदेश में अन–स्किल्ड लेबर भी हैं, जिनके पास न हुनर है और न जमीन, हम उनको भी रोजगार देने का प्रबन्ध कर रहे हैं ।

कल चौधरी साहब ने एक बात ठीक कही थी और मैं भी मानता हूं कि जमीन पर बोझा बढ्ता जा रहा है । तो उस बोझे को हल्का करना चाहिए, कहां तक जमीन इतना ' बोझा उठा पाएगी । यह भी मैं मानता हूं कि जमीन के टुकड़े होते जा रहे हैं। चौधरी साहब ने सक्सेशन बिलकी बात की कि यह बिल ऐसा है कि जब किसी भाई की मौत हो जाती है तो उसकी जमीन 18– 17 जगह बंट जाती है और कुछ आबादी भी बढ़ी है । कल वर्मा साहब– परिवार नियोजन पर नुक्ता चीनी कर रहे थे कि कुंवारी. लड़कियों को केस ' लाने के लिए कहा जाता है लेकिन मैं एक बात आपके द्वारा पूछना चाहता हूं कि या तो सारे भाई मिल कर कह दें कि बढ्ती हुई आबादी की कोई समस्या नहीं है, तब तो हम भी चुप करके बैठ जाते हैं । परन्तु यह बडी गम्भीर समस्या है कोई मामूली समस्या नहीं है । जब यह हरियाणा प्रदेश बना था उस वक्त इसकी आबादी 76 लाख थी लेकिन आज एक

करोड 13 लाख है । तो यह जो खाने वालों की रहने वालों की और इस्तेमाल करने वालों की आबादी बढ़ रही है उसके लिये क्या आपके पास कोई ऐसी योजना है जिसको अमली रूप दे कर इस बढ़ती हुई आबादी की, सारी ये जरूरतें पूरी कर सकें? अगर नहीं है तो मैं आपके द्वारा अध्यक्ष महोदय वर्मा साहब से यह पूछना चाहता हूं कि इन्होंने आज तक कभी अपनी किसी सभा में, मीटिंग में एक शब्द भी परिवार नियोजन के लिये कहा है? मैं चेलैजं . केसाथ बात करता हूं कि इस बारे मैं ये लोग कोई बात नहीं करते हैं । मैं कहता हूं संयम से करो, कृत्रिम उपायों से करो किसी तरह करो, लेकिन क्या कभी उन्होंने इसबारे में जनता में कभी प्रचार किया है? नहीं किया है । सिर्फ नुकताचीनी ही करना जानते हैं कि पैटवारियों को तंग किया जाता है, अफसरों को तंग किया जाता है । मैं मानता हूं कि कहीं कहीं कोई ..सख्ती की बात. भीरू हो –जाती होगी लेकिन. यह राष्ट्र हित की बात है और यह इस देश को सर्वनाश से बचाने की बात है । यह देश बचेगा नहीं अगर इसी तरह से यह आबादी बढ्ती गई । मैं यह बात बडे गर्व के साथ कहता हूं कि जहां हरियाणा ने चौधरी बंसी लाल. के नेतृत्व में देश में कई और रिकार्ड कायम किये हैँ वहां परिवार नियोजन का रिकार्ड भी हिन्दुस्तान में कायम किया है । हरियाणा देश में इस मामले में भी प्रथम रहा है और इस बारे में पहला इनाम जीता है । यह हमारे लिये फख्र की बात है । मैं इन भाइयों से प्रार्थना करूंगा कि वे इस बात में हमारा पूरा सहयोग दें ताकि हम यह समस्या हल कर पायें । कैसे करना है इस बारे

में तरीका ये भाई सोच लें । हम अफसरों के द्वारा नहीं करेंगे यदि ये भाई इसकी जिम्मेवारी अपने ऊपर ले लें । लोगों को समझायें, परसुएशन से करें या जैसे चाहें कर ले हमें कोई एतराज नहीं है, लेकिन कुछ करें तो सही, खाली नुकताचीनी से कोई बात बनने वाली नहीं है । अध्यक्ष–महोदय, इस बीस सूत्रीय प्रोग्राम के तहत हम ने राक और बात कीं–है । हम ने बहुत सारे रोजगारों मैं मिनिमम वेजिक देने का फैसला किया है । जहां पहले 80 से 115 रुपये तक उजरत मिलती थी अब 140 से 175 रुपये तक देने का हमने फैसला किया है । इससे कम वेजिज नहीं दिये जायेंगे । हाथ कर्जा उद्योग बढाने के लिये कई सैटर खोले गये हैं जिन में लोगों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है और इस प्रकार से लोगों को काम देने की कोशिश कर रहे हैं । इस के साथ साथ हुस बीस सूत्रीय प्रोग्राम में एक बात यह भी है कि कृषि की पैदावार बढाई जाये । करन चौधरी साहब ने इस बारे में एक बात यह कह दी कि यह जो खेती की पैदावार बढ़ी है इसका सब से बडा कारण, कारण तो उन्होंने और भी बताये और वे ठीक भी हैं, यह बताया कि हरियाणा में 15 लाख हैक्टेयर नई जमीन तोड़ी है। लेकिन आप जानते हैं कि हरियाणा प्रदेश बनने के बाद यहां पर नई तोड नहीं हुई है । यह नई तोड़ सरदार प्रताप सिंह कैरों के वक्त में ज्वांयट पंजाब के वक्त में हुई थी जब लैंड यूटिलाइजेशन ऐक्ट बना था । पता नहीं उन को कहां से यह पता लगा कि हरियाणा में नई जमीन तोड़ी गई है । मैं निवेदन करता हूं कि हरियाणा में 1966–87 में कल्टीवेबल एरिया 36 लाख 82 हजार हैक्टेयर था

और आज यह 37 लाख 23 हजार हैक्टेयर है । तो आप ही अंदाजा लगायें कि कितनी भूमि नई खेती के अधीन आई है । मैं समझता हूं कि शायद एक फीसदी भी नहीं बनती है जो बढ़ी है । हां एक बात जरूर हुई है कि हमारा क्राप एरिया बढ़ा है हरियाणा बननेके बाद । पहले यह 45 लाख 89 हजार हैक्टेयर था और. अबयह है 51 लाख 50 हजार हैक्टेयर फिर खेती में हमारी इनटैन्सिटी भी बढी है । 1967–6 8 में हमारी खेती की पैदावार की इनटैन्सिटी 125 थी लेकिन अब 138 है । हमारा ग्रास इरीगेटिड एरिया भीं बढा है । कल वर्मा साहब कह रहे थे कि हरियाणा में लम्बाई तो नहरों की बढ़ गई और नई नहरें भी बन गईं लेकिन सिंचित भूमि में वृद्धि नहीं हुई लेकिन मैं इस बारे में आंकड़े देता हूं और जिम्मेदारी के साथ बताना चाहता हूं कि उनकी यह बात निराधार है । 1966– 67 में जहां हमारी 17 लाख 38 हजार

हैक्टेयर जमींन इरीगेट होती थी वहां आज 25 लाख 84 हजार हैक्टेयर जमीन इरीगेट होती है । (तालियां) तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उनकी बात कहा तक सच है । चौधरी साहब ने एकं बात और कह दी और वर्मा साहब भी कुछ आंकड़े दे रहें थे पता नहीं कौन सी किताब से पढ़ कर वे आंकड़े दे रहे थे । चौधरी साहब ने भी यह कहा कि यह पैदावार इसलिये बडी है क्योंकि 15 लाख हैक्टेयर नई भूमि काश्त के अन्दर आ गई और इस बारे में मैंने आपको सारी बात बता दी कि उनकी यह

बात निराधार है । जहां तक खेती की पैदावार बढने की बात है इस बारे में मैं आपके सामने सारे आंकड़े हरियाणा के भी और देश के दूसरे राज्यों के भी पेश करता हूं जिनसे आपको पता चल जायेगा कि दूसरे राज्यों के मुकाबले में हमारे यहां कितनी पैदावार बढ़ी है । आंध्र प्रदेश मैं 22 प्रतिशत खेती की पैदावार बढी है, बिहार में 13 प्रतिशत कम हुई है, हरियाणा में 38 प्रतिशत बढ़ी है (तालियां) केरल में 4 प्रतिशत कम हुई है, मध्य प्रदेश में 10 प्रतिशत बढी हउ, तामिल नाडु में 34 प्रतिशत बढ़ी हए जब कि हमारे यहां 38 प्रतिशत बढ़ी है, महाराष्ट्र में एक प्रतिशत बड़ी है, कर्नाटक में 22 प्रतिशत, उड़ीसा में दो प्रतिशत और पंजाब मैं 23 प्रतिशत बढी है, उत्तर प्रदेश में 4 प्रतिशत कम हुई है, वैस्ट बंगाल में 4 प्रतिशत कम हुई है और खेती की पैदावार बढ़ने के आल इन्डिया के जो आंकडे हैं 12 प्रतिशत वृद्धि के हैं जब कि हमारे हरियाणा में 38 प्रतिशत वृद्धि के आंकड़े हैं । तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पैदावार बडी है या घटी है

चौधरी शिवराम वर्मा:फिर भी अनाज की कमी रह गई?

श्री बनारसी दास गुप्त : कहां रह गई कमी? यह बात भी मैं साफ करदेना चाहता हूं जो वर्मा साहब कह रहे हैं । जिस समय हरियाणा बना था उस वक्त यह प्रदेश खाद्य की दृष्टि से घाटे का प्रदेश था और आज हमें फख्र होता है कि हम सैंट्रल पूल में आये साल पंजाब के बाद तमाम हिन्दुस्तान में सब से ज्यादा अनाज देते हैं । कहां पर है यहां अनाज की कमी? इस

साल भी हजारों टन हमारा चावल पड़ा है और हम गवर्नमैंट आफ इन्डिया से कहते हैं इसे उठा लो और हमारी पेमैंट कर दो लेकिन वे उठा नहीं रहे हैं । तो फिर यह कमी की बात कहां से आई? फिर वर्मा साहब पर–कैपिटा इनकम के बारे में कुछ आंकड़े पढ रहे थे । वह जो 1960–61 की प्राईसिज के आधार पर टेबल दिया हुआ था

वह पढ़ कर उन्होंने सुना दिया क्योंकि वह इनको सूट करता था लेकिन अगला जो टेबल था उस पेज पर वह नहीं पढ़ा । मैं इस बारे में भी बताना चाहता हूं कि उन्होंने जो बात कही वह निराधार है और इस बारे में मैं सारे देश के आंकड़े आपको बताता हूं । सारे हिन्दुस्तान में पर–कैपिटा इनकम 104 प्रतिशत बढी है लेकिन हरियाणा में इसके मुकाबले में 25. 6 प्रतिशत बढी है । दूसरे राज्यों की भी सुन लो । वैस्ट बंगाल की 8. 4 प्रतिशत, कर्नाटक की 18 प्रतिशत, मध्य प्रदेश की 14.5 प्रतिशत और हिमाचल प्रदेश की 166 प्रतिशत यह इनकम बढ़ी है, गुजरात की कम हुई है 94 प्रतिशत, पंजाब की 17 प्रतिशत बढ़ी है, राजस्थान की 138 प्रतिशत और यू ० पी० की 13 प्रतिशत बढ़ी है लेकिन हमारे हरियाणा की 25.6 प्रतिशत बढी है जो कि हर प्रदेश से ज्यादा है और उन सब से ज्यादा वृद्धि पर–कैपिटा इनकम में हमारे यहां हुई है । एक बात और चौधरी साहब ने कही कि लैड सीलिंग का चर्चा यहां बहुत होता है लेकिन हुआ कुछ नहीं । मैं चौधरी साहब से कहना चाहता हूं कि उनके वक्त में भी दो कानून

बने थे, एक 1953 में पंजाब में बना था और आप भी अध्यक्ष महोदय यज जानते हैं, आप भी उस समय मैंबर होते थे, और एकं कानून 1955 में पैप्सू का एक ऐक्ट बना था । तो कल चौधरी साहब ने चुनौती देते हुए एक बात. कही थी कि आज तक कितनों जमीन मु जारों को मिली । उन्होंने यह भी कहा कि हजारों मुजारे बेदखल हो गए । पहले तो मैं वही बात दोहराता हूं कि चौधरी साहब के दिल में अगर इतना दर्द था मुजारों के लिए, किसानों के लिए, तो वे 1 7 साल तक क्यों खामोश बैठे देखते रहे और मुजारे उजाडते रहे । लेकिन चलो, आज अगर आपके दिल में उनके प्रति दर्द है तो मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि पंजाब ऐक्ट और पैप्सू एक्ट के परिणाम– स्बरूप 31 मार्च 1975 तक 58 हजार 922 स्टैडर्ड एकड़ जमीन हमने 3 1, 737 भूमिहीन मु जारों को दी है। आप कल बड़े चेलैजै के साथ कह रहे थे कि मुख्य मन्त्री बतलाए कि एक. इंच भी जमीन किसी को देंगे या नहीं । मैं आपके सामने यह फैक्ट्स दे रहा हू कि 31,737. मुजारों को बांटी है और आगे जो हमारा ऐक्ट आ रहा है...

चौधरी शिवराम वर्मा : आप पहले ही ये सारी बातें किताबों में क्यों नहीं छाप देते ।

राजस्व मंत्री (पंडित चिरंजी लाल शमी):जो ओवर रूल रूलिंग हो जाए और फिर उसे कोट किया जाए तो वह कंटैम्पट आफ कोर्ट होती है । इन्होंने 60– 61 की फिगर कोट की है । That is contempt fo the House (व्यवधान)

श्री बनारसी दास गुप्त : अध्यक्ष महोदय, आपको मालूम है, लेड सीलिंग बिल 1972 में पास किया गया था लेकिन हाई कोर्ट में चौलेंज हो गया । इसके परिणामस्वरुप उसमें संशोधन करना पड़ा और बह संशोधन सभा के इस सत में आ रहा है और हम जल्दी ही इसको पास करने जा रहे हैं । उस बिल को पास करने के अदि हमारा अन्दाजा है कि 92,486 एकड़ जमीन सरप्लस मिलेगी लेकिन इस में कुछ जमीन हमारे धार्मिक स्थानों की है जो 15,922 एकड़ बैठती है, गऊशालाओं की 9481 एकड़ है । 25,773 एकड़ जमीन इस सरप्लस में सैं निकल जाएगी और जो बाकी जमीन होगी वह हरिजनों में, गरीबों में तकसीम की जायेगी । चौधरी साहब ने चेलैजं के साथ कहा था कि मुख्य मन्त्री बतलाए कि एक इंची जमीन भी किसी को दे पाएंगे । जो मैंने फिगर दी है, इतनी जमीन हम दे पाएंगे, लेकिन एक बात हम मानते हैं कि सब को जमीन नही दे सकते । यह बहुत बड़ी बात है, बड़ी मुश्किल है, सब को जमीन दी नहीं जा सकती । मैं इस बात से सहमत हूं कि जमीन के टुकड़े होते जा रहे हैं, इसका पैदावार पर असर होता है, लेकिन इसका चारा कोई नहीं है । उत्तराधिकार ऐक्ट अथवा सक्सैशन ऐक्ट के बारे में, अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन यह है कि यह सैन्ट्रल ऐक्ट है और इस ऐक्ट के बारे में हमने एक बार पहले भी गवर्नमैंट आफ इण्डिया को लिखा था । इसके बावजूद भी मैं चौधरी साहब को और इस सदन के सदस्यों को विश्वास दिलाता हूं कि हम इस पर अपने दल की बैठक में पूरी तरह से विचार करेंगे और अगर आवश्यक हुआ तो संशोधन

लाने के लिए मामला केन्द्रीय सरकार के साथ उठाएंगे । इसके साथ अध्यक्ष महोदय, मैं अधिक समय न लेता हुआ एक खास बात की ओर इशारा करना चाहता हूं जैसे कि चौधरी साहब ने जिक्र किया कि नंहरों में पानी नहीं है। नहरों में पानी की बात चौधरी साहब ने बिल्कुल ठीक कही । जितना पानी हमें चाहिए उतना मिल नही रहा, यह बात बिल्कुल ठीक है । हमने नई नहरें भी बनाई हैं, उन कई नहरों मैं बरसात के दिनोंमें बाढ़ का पानी देते हैं । जब यमुना नदी के अन्दर बाड का पानी आता है । जुई कैनाल तो पैरिनियल बन गई है, बाकी जितनी नहरें बन रही हैं वे बाढ के पानी पर बन रही है । बाढ का पानी चलाने पर अध्यक्ष महोदय, जहां चौधरी रिजक राम जी के इलाके का कल्याण किया वह दूसरे सूखाग्रस्त लोगों को भी राहत पहुंचाई है । अध्यक्ष महोदय जिला सोनीपत में एक मुडलाना गांव है । जब सें हमने होश सम्भाला है तबसे देख रहे हैं कि वह. गांव चारों ओर से पानी में डूबा रहल था, लोग घर से बाहर नहीं निकल सकतेथे । इस प्रकार के अनेकों गांव थे लेकिन आज आप देखते हैं कि वह बात नहीं है । बाढ़ की समस्या हल हुई, उन लोगों को तबाही से बचाया और जो एक एक बूंद पानी के लिए लोग तरसते थे उन को पानी पहुंचाया, कम से कम वे एक फसल तो पैदा कर लेते हैं । अगर कहत ए जाए और भगवान रूठ जाए तो वे कम से कम पशुओं के लिए चारा पैदा कर लेते हैं और गुजारे के लिए अनाज पैदा कर लेते हैं । चौधरी साहब कह रहे थे कि नहरें तो बना ली जाये लेकिन पानी देते वक्त ध्यान रखना । मैं चौधरी साहब कौ

और इस सदन को विश्वास दिलाता हूं कि जो नहरें बन रही हैं, उनमें हम किसी अन्य इलाके का पानी काट कर के नहीं डालेगे, एक बूंद भी किसी का.. पानी नहीं काटेंगे । उन्होनें कहा कि मैंने 3 हजार क्यूसिक पानी बढ जाने की बात कही है । यह बात ठीक है इतना ही बढा है । पानी कई साधनों से बढाया गया है । यह भूमिगत जल तथा वाटर कोसिंज राव माईनर पक्का करने लें बढा है । इसके बारे में चौधरी साहब कह रहे थे कि माइनर और वाटर कोर्सिज को अगर पक्का कर दिया गया तो सीपेज से जौ सब–सायल वाटर मीठा होता है वह बन्द हो जायेगा और पीने के पानी की समस्या खड़ी हो जाएगी । यह बात उन्होंने कल कही है । चौधरी' रिजकराम बडे स्याने आदमी हैं, रहने वाले भी स्यानपत के हैं । स्यानपत में जो बसते हैं वे बहुत सियानै आदमी हैं । हम अध्यक्ष महोदय, सोनीपत को स्यानपत कहते है ।

Pandit Chiranji Lal Sharma : Thank you for the compliments.

श्री बनारसी दास गुप्त:अध्यक्ष महोदय, वे इस. बात को क्यों भुल गए कि कच्चे खालों में जो पानी चलता है वह उसके बैड में जजब होता है । जजब तो जमीन में ही होता है, फिर खेत्रों में फैल कर जजब होगा हम माइनर्ज को, नहरो को खालों को पक्का बनाकर पानी टेल तक पहुंचा देंगे ताकि किसान उसको इस्तेमाल कर सकें । इसलिए सब– गयल वाटर को इससे' कोई असर नहीं पड़ेगा, चाहे आप किसी टैक्नीशियन से जांच करवा

लें, यह एक मोटी अकल का आदमी भी जान. सकता है कि जो पानी थोडी जमीन में जजंव होता था अब वह ज्यादा जमीन में फैल कर जजब होगा । चौधरी साहब ने एक बात और कही कि डायरैक्ट ट्यूबबैल लगा दिए, आगमेंटेशन ट्यूबवैल लगा दिए जिससे जो दूसरे प्राइवेट ट्यूबवैल थे उन पर बुरा असर पड़ा, इन्होंने कई गांवों के नाम लिए कि फलां गांव में पानी मीठा था, फिर खारी हो गया । हमने इस बात की इन्वैस्टीगेशन करवाई और हमार पास इसकी पूरी रिपोर्ट है, अगर आप देखना चाहें तो किसी समय देख सकतेहैं । हां, यह ठीक है, जहां आगमेंटेशन का ट्यूबवैल लगतों है उसके कुछ रेडियस में वह असर करता है लेकिन दूर तक नहीं करता । यह जो पानी का लैवल नीचे गया, पानी ब्रैकिश हुआ, सब–सायल वाटर पर असर पड़ा, इसका कारण यह है कि पिछले कई सालों सेड्राइ–साइकल चल रही है । मैं ऐसे गांव बता सकता हूं जिनके 100 मील तक भी ट्यूबवैल नहीं लगा लेकिन वहां का पानी बैकिश हो गया । मरा अपना गांव है, उसके चारों तरफ के कुओं में मीठा पानी होता था, आज वहां एक कुएं में भी मीठा पानी नहीं रहा और मेरे इलाके में 60– 70 मील की दूरी तक कोई गहरा ट्यूबवैल नहीं लगा । यह सब ड्राई–साइकल का असर है । इस साल बारिश काफी अच्छी हुई है और अगर इसी तरह पानी बरसता रहा तो सब–सायल वाटर ठीक हो जायेगा, इसके बाद सब सायल वाटर की समस्या नहीं होगी । इसके इलावा एक महत्वपूर्ण बात और है, और उस बात पर हरियाणा प्रदेश का भविष्य निर्भर करता है । वह बात है,

रावी–व्यास के फालतू पानी के बंटवारे की । यह बात बड़ी अहम है, महत्वपूर्ण है, इसमें कोई संदेह नहीं है । लेकिन अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा सारे सदन को विश्वास दिलाता हूं कि हमने आज तक इस मामले को उठाने में या केन्द्रीय सरकार से बात करने में किसी प्रकार कीं कोताही नहीं की । हमने तगड़ा स्टैड लिया है । आज तक आप जानते हैं चौधरी बंसी लाल जी यहां थे । वे कमजोरी की बात करना तो जानते ही नहीं थे । मेरी मौजूदगी में कई मीटिग्ज दिल्ली के अन्दर हुई । मैंने हमेशा देखा कि हर मामले में तगड़ा स्टैड उन्होंने लिया और बड़ी मजबूती के साथ वे लड़े । अब मामला केन्द्रीय सरकार के विचाराधीन है और मुझे इस बात का पूरा विश्वास है कि बहुत शीध्र ही यह फैसला होने वाला है । मैं समझता हूं शायद महीना भी न लगे । मुझे इस बात की पूरी आशा है कि इस पानी में जो हमारा हिस्सा बनता है, जो इन्साफ की दृष्टि से हमारा हिस्सा बनता है, वह हमें अवश्य मिलेगा । फिर चौधरी साहब ने कहा कि उस पानी को हरियाणा तक लाने के लिये कैरीयर कैसे बनना है, लिंक कैनाल कैसे बननी है । पहले कहते थे कि दस करोड़ का ऐस्टिमेट है । लेकिन मैं चौधरी साहब को बता दूं कि दस करोड़ का ऐस्टिमेट तो इसका कभी बना ही नहीं । सन् 1968 में पहली बार दह मसला पैदा हुआ । इस पानी के बटवारे का हमने क्लेम किया और उसी वक्त इस कैरीयर के बनाने का अनुमान भी लगाया गया । उस वक्त 27 करोड़ रुपये इसका ऐस्टिमेट था जो अब बढ़ कर 57 करोड़ रुपये हो गया है । यह मैं समझता हूं कि आज जब वह लिंक कैनाल

बनेगी तो उस पर 57 करोड़ रुपये खर्च होंगे लेकिन आप जानते हैं कि हर चीज के भाव आज बढ़े हैं, मजदूरी भी बढ़ी है । अब तक काम शुरू इसलिए नहीं किया क्योंकि वह आधी कैनाल पंजाब के क्षेत्र में बननी है और आधी हरियाणा में बननी है । हमने पंजाब के भाइयों से यह बात की भी हे लेकिन उन्होंने कहा कि जब तक पानी का बंटवारा नहीं हो जाता तब तक हम इजाजत नहीं देंगे अपने एरिया में कैनाल बनाने की । मुझे इस बात का विश्वास है कि जब पानी का बंटवारा हो जाएगा तो पंजाब के भाई, पंजाब के मुख्य मन्त्री और पंजाब की सरकार इस सम्बन्ध में हम से पूरा सहयोग करेगी और अपने क्षेत्र में जल्दी से जल्दी नहर बनाने के हमारे काम के रास्ते में कोई रोडा नहीं अटकाएगी । चौधरी साहब ने यह भी कहा कि इसको बनते बनते 6 साल लग जाएंगे लेकिन चौधरी साहब को मैं यकीन दिलाना चाहता हू कि जिस रोज पानी का फैसला हो जाएगा उसके पश्चात? अढाई साल के अन्दर अन्दर इस नहर को पूरा करने की कोशिश करेंगे । वैसे तो हम दो साल में ही इसे पूरा करने की कोशिश करेंगे क्योंकि हरियाणा की परम्परा रही है कि वह रिकार्ड टाईम में काम पूरा करता है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा गुंजायश रख कर मैं यह बात कहता हू कि अढाई साल में अपना कैरीयर हम जरूर बना लेंगे ।

स्पीकर साहब, एक बात और चौधरी साहब ने कही थी कि जब तक कैरीयर नही बनेगा तब तक हम पानी का फायदा नहीं उठा पाएंगे । मैं चौधरी. साहब को आपके द्वारा बतलाना चाहता हूं

कि ऐसी बात भी नहीं है । जब तक यह कैनाल नहीं बताएगी तब तक आठ सौ क्यूसिक्स से लेकर तीन हजार क्यूसिक्स तक पानी हम ऐगजिस्टिग चौनल्ज में से ले आएंगे । अभी भी हमें ऐडहोक शेयर इस पानी का मिलता है । सात सौ क्यूसिक्स से चौदह सौ क्यूसिक्स तक के राबी और व्यास के सरप्लस पानी को आज भी हम इस्तेमाल करते हैं । इसलिए मैं अध्यक्ष महोदय यह यकीन दिलाना चाहता हू कि इस बारे न तो हमारी सरकार की तरफ से पहले कमजोरी रही है और न आज है । हम बड़ी मजबूती के साथ इस प्रश्न को हल करने में लगे हुए हैं और म्उझे आशा है कि यह बहुत जल्दी हल होगा और हरियाणा को इससे बहुत ज्यादा फायदा होगा ।

किसाऊ डैम की बात भी चौधरी साहब ने की और कहा कि यह गलती हो गई कि उसके बनाने का काम उत्तर प्रदेश पर छोड़ दिया गया । स्पीकर साहब, वह गलती तो चौधरी साहब ने की होगी या किसी और ने की होगी क्योंकि हम तो उस बत कहीं थे नहीं । 1963 में पहली बार किसाऊ डैम बनाने का फैसला हुआ था! उत्तर प्रदेश पर यह छोड़ों भी इसलिए गया होगा क्योंकि काफी सारी टैरीटरी जहां यह डैम बनना है उनकी है । कुछ हिस्सा तो उसका उत्तर प्रदेश में पड़ता है और कुछ हिमाचल प्रदेश में पडता है । इसलिए उन पर इसकी कंस्ट्रक्शन की बात छोडनो जरूरी थी! लेकिन उत्तर प्रदेश ने इस प्रोजैक्ट को लोअर प्रायरिटी पर रखा हुआ है । पिछले दिनों चौधरी बंसी लाल जी

खुद वहां गार थे । त्रिपाठी जी से जो उस समय उत्तरप्रदेश के मुख्य मली थे, वे मिले थे, उनको –रोकर वे साईट पर गए थे, काफी बातचीत चली थी लेकिन अभी तक उन्होंने सी० पी० डव्ल्यू ० डी० को सैक्शन के लिए भी यह प्रोजैक्ट भेजा नहीं है । हम इसके लिए फिर कोशिश करेंगे । स्पीकर साहब, मैं चौधरी साहब को यह भी बताना चाहता हू कि यही नहीं हमने तो गंगा का बाढ़ का पानी हासिल करने के लिए भी कोशिश की है । हुनने सैन्ट्रल गवर्नमैंट को लिखा था, एक स्कीम उनके सामने पेश की थी कि यदि 10 हजार क्यूसिक्स पानी गंगा से बाढ़ का हमें हरिद्वार के स्थान पर दे दिया जाए तो हम अपने काफी सूखाग्रस्त इलाके को पानी दे सकते हैं । वह पानी उत्तर प्रदेश वालों के कोई काम नहीं आता । लाखों क्यूसिक्स पानी बरसात के दिनों में उनका बहकर समुद्र मं चला जाता है और उनके इलाकों की तबाही करके जाता है । मैंने बाबू जगजीवल राम जी से निवेदन किया था कि आने बारने दस साल में या बीस साल में भी यदि इस बरसात के पानी को इस्तेमाल करने की उत्तर प्रदेश की कोई योजना हो तो एक बूंद भी पानी हमें न दें लेकिन उनके पास कोई योजना इसको इस्तेमाल करने की है नहीं । वे इसे इस्तेमाल कर नहीं सकते । इसलिए इसमें से कुछ पानी हमें दे दो । हमने कोशिश तो की है लेकिन दूसरे प्रदेश का मामला है, पड़ोसी प्रदेश का मामला है, हम उन्हें मजबूर नहीं कर सकते? पहले ही आगमैन्टेशन कैनाल के बारे में हमारी काफी जवाब– तलबी होती रहती है क्योंकि इस सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश वाले कहते हैं कि हरियाणा वाले उनकी जमीन के

नीचे के पानी को खींच कर ले गए । हमें बार बार जवाब देना पड़ता है कि हमने उनका बूंद भी पानी नहीं लिया है, यह हमारा अपना पानी है ।

जहां तक थीन डैम का सवाल है, आपने स्पीकर साहब अखबारों में पढ़ा होगा कि पंजाब के मुख्य मंत्री और जम्मू तथा काश्मीर के मुख्य मली का इस बारे में समझौता हो गया है । ठीक है, बहुत अच्छी बात है कि फैसला हो गया । हमें इस बात की खुशी है लेकिन भारत सरकार से हमने पहले ही क्लेम किया हुआ है कि रावी और व्यास के सरप्लस पानी पर जो भी प्रोजैक्ट बनेगा, पानी के लिए या बिजली के लिए, उसमें हरियाणा प्रदेश का शेयर होगा । इस क्लेम पर हम स्टैंड करेंगे और बड़ी मजबूती के साथ, बड़ी दृढ़ता के साथ इस प्रश्न को हम केन्द्रीय सरकार के साथ उठायेगे ।

ये सब बातें कहने का, अध्यक्ष महोदय, मेरा अभिप्राय यह है कि हमारी सरकार ने इस प्रदेश को विकसित बनाने में, इसमें हरित क्रांति लाने में, उद्योग धन्धे आदि स्थापित करने में किसी प्रकार की कोताही नहीं की है । सारे हिन्दुस्तान में आज हमारी रैपुटेशन है कि हरियाणा प्रदेश में विकास के काम बड़े तेजी के साथ कार्यन्वित होते हैं । चौधरी बंसी लाल जी की डायनेमिक लीडरशिप की आज तमाम हिन्दुस्तान में प्रशंसा है । मैं भी यकीन दिलाता हूं कि उन्होंने जो परम्परा कायम की थी उसको हम कायम रखेंगे । (तालियां) इसके लिए मुझे अपने दल के

भाईयों के साथ साथ विपक्षी दल के भाईयों का सहयोग भी चाहिए । यह बात प्रदेश के हित में है और प्रधान मैली जी का जो बीस सूत्रीय कार्यक्रम है वह केवल कागजों मे ही नहीं रहेगा बल्कि पूरी तरह से कार्यन्वित किया जाएगा । चौधरी रिजक राम जी ने एक बात और कही कि प्रधान मली जी ने अपने बीस सूत्रीय कार्यक्रम में कहा कि हम राष्ट्रीयकरण नहीं करेंगे । मैंने तो 20 सूत्रो में यह प्वांयट कहीं नहीं पढ़ा, पता नहीं इन्होंने कहां से पढ़ त्रिया । स्पीकर साहब, नेशनेलाइजेशन के जो विरोधी थे उनके हिमायती तो चौधरी साहब हैं । जब बैंकों का राष्ट्रीयकरण होने लगा तो जो आदमी उसके विरोधी थे उन लोगों के नलों में बाहें डालकर तो चौधरी साहब अपनी राजनीति का काम चलाते हैं । मैं पिछले दिनों पानीपत में वीवर्ज कालोनी का फाउंडेशन स्टोन ले करने गया । वहां स्टेट बैंक आफ इंडिया के मैनेजर बैठे हुए थे । मेरे से डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि ये देहाती भाईयों को कर्जा अपने हाथों से देंगे । लेकिन मैंने अपने भाषण में बतलाया कि स्टेट बैक आफ इंडिया के मैनेजर आज अपनी मर्जी से यहां नहीं आए हैं । बैकों के दरवाजे तो पहले जब ये नेशोलाइज नहीं हुए थे बिरला, डालमिया और टाटा के लिए खुले थे । बिरला को जब जरूरत होती तो 10 करोड़ 20 करोड़, 50 करोड़ का कर्जा उसे मिल सकता था लेकिन किसान को जब किसी. चीज के लिये कर्जे की जरूरत होती तो बैंक के दरवाजे उसके लिए बंद होते थे । आज स्टेट बैंक आफ इंडिया के मैनेजर देहातों में जाकर के जो चौक बांटते हैं वह प्रधान मंत्री के डंडे से बांटते हैं । अगर ये

बैकंस नेशनेलाइज्ड न होते, चौधरी रिजक राम जी जिनको नेता मानते हैं, उनकी बात अगर मान ली जाती तो न ये बैकंस नेशनेलाइज होते और न ही गरीब देहात वालों को या किसान मजदूरों को उन से कर्ज मिलता । आज इस बात का काफी प्रबन्ध किया जा रहा है । प्रधान मली जी ने कभी राष्ट्रीयकरण के विरोध में कोई बात नहीं कहीं, लेकिन हां उन्होंने एक बात जरूर कही कि हिन्दुस्तान में मिक्सड इकौनोमी, मिश्रित अर्थव्यवस्था चलेगी, कम्पलीट नेशनेलाइजेशन की पालिसी की बात देश में नहीं चल सकती । मैं भी इस बात का कायल हूं, हामी हूं कि मिक्सड इकोनोमी से देश का ज्यादा विकास होगा, ज्यादा डिवैल्पमेंट होगी, देश फले फूलेगा । तो अन्त में अध्यक्ष महोदय, मैं आपका धन्यवाद करते हुए इस सदन को विश्वास दिलाता हूं कि प्रदेश के हित में जो भी बात होग उन सब को पूरा करने की कोशिश की जायेगी, उनमें कोई कोताही नहीं होगी । आपका बड़ा धन्यवाद । (तालियां) (इस समय उपाध्यक्षा पदासीन हुई)

लाला रुलिया राम (घरौंडा) : डिप्टी स्पीकर साहिबा, कल से बजट पर चर्चा चल रही है । हमारे फाइनैन्स मिनिस्टर साहब ने जो बजट रखा है यह बहुत अच्छा बजट है । यह हरियाणा की खुशकिस्मती है कि इतना अच्छा बजट बनाया गया है । यह ठीक है कि कुछ मैम्बरों ने इसको क्रिटिसाइज भी किया है । जो भी हरियाणा स्टेट में हुआ है वह हमारे सामने हैं । यह किसी से छिपा हुआ नहीं है कि किस तरह से हरियाणा ने थोड़े

टाईम में तरक्की की । हमारे सामने यह स्टेट बनी थी । हरियाणा बनने से पहले की भी हालत हमने देखी थी और आज की हालत भी हम अपनी आंखों के सामने देख रहे हैं । आज हरियाणा कितनी तरक्की पर जा रहा है । हमारे पहले चीफ मिनिस्टर साहब की यहां सदन में काफी तारीफ हुई है । अब जो बागडोर आयी है वह भी एक मजबूत चीफ मिनिस्टर के हाथ में आयी है । मैं आशा करता हूं कि हमारे मौजूदा चीफ मिनिस्टर साहब सूबे के विकास में पूरा–पूरा ध्यान करेंगे ।

अब मैं एक दो बातें अपने इलाके के बारे में अर्ज करना चाहता हूं । हमारी कुछ डिमान्डज हैं जिनके बारे में मैं उम्मीद करता हूं कि सरकार उनको पूरा करेगी । मैं सबसे पहले ऐग्रीकल्चर के मुताल्लिक अर्ज करना चाहता हूं । मेरे बहुत से भाइयों ने जमीदारों के बारे में चर्चा किया है । जमींदारों के सामने बहुत मुसीबतें हैं । जमीदारों को उपज की कीमत कम मिलती है और जमींदारों को दूसरी चीजें मंहगी लेनी पड़ती हैं । मैं यह भी समझता हूं कि गवर्नमेंट ने उनको सहूलियात देने में किसी किस्म की कमी नहीं रखी है । सरकार ने जमींदारों के लिए बिजली का, पानी का, नहरों का सब चीजों का प्रबन्ध किया है लेकिन फिर भी मैं दरखास्त करूंगा कि जितनी भी इमदाद इन लोगों की हो सके, सरकार को करनी चाहिए । यहां पर हाउस में फर्टिलाइजर का मामला मैम्बर साहिबान ने उठाया । फर्टिलाइजर का मामला बिल्कुल दुरुस्त है । मैं यह कहते हुए बिल्कुल झिझक

नहीं करूंगा कि लास्ट ईयर खाद के रेट्स दुगने हुए थे ।

जमींदारों को इल्म नहीं था कि इस तरह सेरेट्स दुगने ही जायेंगे । इस की आवाज सुनते थे कि रेट्स बढ़ेंगे क्योंकि मार्किटिंग फैडरेशन थाका ने शोर मचाया हुआ था । फैडरेशन वालों को तो सारे मामले का पता था कि भाव बढ़ेंगे । इसमें कोई शक नहीं कि यह स्टेट गवर्नमैंट का फैसला है कि सैन्ट्रल गवर्नमेंट रेट्स बढ़ाये लेकिन इसका जो फायदा है वह फैडरेशन वालों को हुआ । एक महीना पहले फैडरेशन वालों ने चिट्ठी इशू कर दी कि सेल बन्द कर दो । सोसायटी वालों ने सेल बन्द कर दी । जबरेट्स बढ़ गये तो एक दिन पहले अपने आदमियों को फायदा पहुंचाने के लिए एक एक आदमी से एक एक हजार और पांच पांच सौ कट्टे उठवा दिये । उन आदमियों को पचास पचास हजार रुपये कमवाये । उस वक्त हमारे यहां विधान सभा का सैशन लगा हुआ था । यह बात यहां हाउस में भी आयी और हमारे चीफ मिनिस्टर साहब ने भी आर्डर दिया कि इन्कवायरी करायी जाये । आर्डर देने के बाद कई केसिज भिवानी, नीलोखेडी, घरौंडा के पकडे । बाद में यह पता लगा कि जितने भी ये केसिज पकड़े गये थे वे सब के सब फेल हो गये । सिर्फ हमारी फैडरेशन की कमजोरी की वजह से फेल हुए हैं । इस तरह से एकएक आदमीमुनाफा खा गया ।

यहां हाउस में मेरे भाई एक एम० एल० ए ० ने फोर्डर के बारे में जिक्र किया । हमारे यहां घरौन्डा में एक बी० डी० ओ0

लगा हुआ था आजकल तो वह जीन्द ट्रांसफर हो गया है । डेरी डिवैल्पमैंट डिपार्टमैंट में लगा हुआ है । उसने सारा फोडर अपने आदमियों को दिया । उन्होंने सारे फोडर को ब्लैक के अन्दर बेचा । उस आदमीं ने अच्छी पोस्ट पर होने के कारण उसका नाजायज तौर पर फायदा उठाया । मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि जितना चारा उन्होंने बेचा है उसके बारे में इन्कवायरी करायी जाये । जो चीज पशुओं के लिए बनायी गई है, वह पशुओं तक पहुंचनी चाहिए थी । बीच में जिन आदमियों ने उसकी चोरी की है उनको पकड़ना चाहिये और सजा मिलनी चाहिये ।

तीसरी चीज मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि हमारी ट्रांसपोर्ट ने कमाल कर दिया है । बहुत ही ज्यादा मुनाफा कमाया है, किसी भी सरकार ने इतना मुनाफा नहीं कमाया है । हम पंजाब से भी आगे बढ़ते जा रहे हैं । छोटी छोटी चीजें जिनकी तरफ हमें ध्यान देने की आवश्यकता है वे हैं, जितनी हमारी पुरानी गाड़ियां हैं वे रास्ते में खराब हो कर खड़ी हो जाती हैं । मुसाफिर तंग होते हैं । कल जब मैं आ रहा था तो घरौंडा से चन्डीगढ तक मुझे तीन चार गाड़ियां खड़ी मिलीं जो खराब थीं । खराब होने से लोगों को काफी दिक्कत होती है । मैं आपके जरिए मिनिस्टर महोदय से अर्ज करूंगा कि इस बात को जरूर चौक करें । उनके साथ कोई मिस्त्री वगैरह भेजा जाये ताकि किसी मुसाफिर को दिक्कत न हो ।

ऐक्प्रैस गाड़ियां जब चलती हैं तो वे अन्धाधुन्ध चलती

हैं । अगर कार सामने से आ जाये तो उसका पास करना बड़ा मुश्किल होता है । ऐक्सप्रैस गाड़ियों को आधा घन्टा और दे दिया जाये ताकि वे आराम से चल सके । दूसरे तेज गाड़ी चलने से ऐक्सीडैन्ट होने का डर रहता है । जिस मुसाफिर ने किसी ऐक्सप्रैस गाड़ी में जाना है वह घर से आधा घन्टा पहले भी चल सकता है ।

डिप्टी स्पीकर साहिबा मैं सड़कों के मुताल्लिक भी जिक्र करना चाहता हूं । पी० डब्ल्यू ० डी० का महकमा बहुत बड़ा महकमा है । उसके अन्दर बहुत ज्यादा कर्मचारी हैं मैं फाइनैन्स मिनिस्टर साहब से यह अर्ज करना चाहता हू कि इस महकमें को रुपया दिया जाना चाहिए । मेरा इलाका पानीपत और करनाल के पास लगता है । मैं देखता हूं कि बिना पैसे के एस० डी० ओ० से ले कर एक्स० ई० एन० तक सब लोग खाली बैठे रहते हैं । जब तक सरकार उनको पैसा नहीं देगी तब तक वे काम कहां से करेंगे । पी० डव्ल्यू ० डी० महकमे का हरियाणा पर बड़ा भारी बोझ है । इस बोझ को कम करने के लिए उन्हें पैसा दिया जाना चाहिए । अगर थोड़ी बहुत सड़के बन जायें तो हरियाणा प्रान्त का भी भला होगा और वह स्टाफ भी काम में लग जायेगा । मैं तो यहां तक कहूंगा कि मेरे यहां एक सड़क घरौंडा से चावला विलेज को जाती है । मैंने यह चीज अपने चीफ मिनिस्टर साहब को भी नोट करायी थ्री कि वह सड़क कई साल से बनी हुई है और अब उसकी जो रोडी है, वह नीचे से निकलनी शुरू हो गयी है । अगर उसके

ऊपर थोड़ी सी रोडी फिंकवा दी जाये तो अच्छा होगा लेकिन नीचे वाले ये कहते हैं कि हमारे पास कोई पैसा नहीं । मुझे जहाँ तक पता है चीफ मिनिस्टर साहब ने तो लिखकर भी भेज दिया था लेकिन एक्स० ई० एन० साहब कहते हैं कि कोई पैसा नहीं है । तो मैं यह अर्ज करूंगा कि इस तरह की जो छोटी–छोटी सडकें पहले ही बनी हुई हैं, उनकी प्रौपर मेंटेनैसं की जाये । आगे सवाल आता है को आप्रेटिव काम कोआप्रेटिव के महकमें के मुताल्लिक यह ठीक कहा गया है कि अब उसमें बहुत कुछ सुधार हो गया है । पहले इस महकमे के अन्दर इतनी गड़बड़ थी कि जिसका कोई हिसाब नहीं । गुप्ता जी ने जैसे कि यहां बताया है कि हम कई कोआप्रेटिव सोसाइटियों को पटवार के सरकल के मुताबिक बना रहे हैं । लोग 8– 10 साल पुरानी वसूली रोके बैठे हैं । इतनी पुरानी वसूली है लेकिन वह नहीं देते । आखिरकार गवर्नमैंट के आर्डर जाते हैं तो लोग क्या करते हैं, वे डरते फिरते हैं ।

अब मैं अपने चीफ मिनिस्टर का ध्यान फैमिली प्लानिंग के मुताल्लिक भी दिलाना चाहता हूं । फैमिली प्लानिंग हरेक आदमी के लिये चाहिए और जब तक हरियाणा में ही नहीं बल्कि सारे देश में आबादी पर रोक नहीं लगती हम आगे नहीं बढ़ सकते क्योंकि आबादी बढ्ती जा रही है । इसके अलावा मैं सरकार से यह भी अर्ज करूंगा कि वह थोड़ा सा नोट कर लें और अपने आफिसर साहिबान को इतनी हिदायत जरूर कर दें कि जो इधर

उधर से लोगों को लाकर आपरेशन करके दिखा देते हैं, वह न करें, मैं यह देखता हूं और मेरे पास सही मिसाल है कि दिल्ली से और इधर उधर से लोगों को लाकर आपरेशन किये जाते हैं, यह अच्छा नहीं है । वह उन्हें दिखाते हरियाणा के हैं । अगर इस चीज का सबूत लेना चाहें तो मेरे घरौंडे के अस्पताल की इन्कवारी करा लो, मैं साबित कर दूंगा । मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि सही मायनों में यह काम होना चाहिए और. इस ओर जितनी ज्यादा तवुज्जह दी जाए, उतनी ही कम है, मैं तो गुप्ता साहब से यह अर्ज करूंगा कि इसके लिये कोई कानून ही बना दें तो बहुत अच्छा होगा । इससे तो पब्लिक भी दु:खी है और आफिसर भी दु:खी है । अगर कोई मुलाजमत के लिये जाता है. तो उसको यह कहा जाता है कि दो केस लाओ ।

इसके अलावा मेरे इलाके की एक और डिमान्ड या तकलीफ है । मैं अपने फाइनैस मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर साहब के सामने यह जरूर रखूंगा कि हरियाणा का इस स– फ्लड आने की वजह से बहुत ज्यादा नुक्सान हुआ है खासकर डिस्ट्रिक्ट करनाल बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है । मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि इस साल जमुना के पुल जितनी भूमि घिरी है, उसका कोई हिसाब नहीं । मैंने खुद देखा है । मैं फ्लड के दिनो में वहां गया और मैंने वहा देखा है कि यू ० पी० वालों ने तो बड़ी–बडी ठोकरे लगा रखी हैं । पता नहीं अंग्रेजी में उनको क्या कहते हैं लेकिन जो उन्होंने इतनी बडी–बड़ी कीमती ठोकरें लगा रखी हैं, उनकी

वजह से जमुना का पानी हमारी तरफ आया और हमारी सारी की सारी छोटी– छोटी ठोकरें पानी में बह गयीं और बहुत नुकसान हुआ । आप वहां जाकर खुद देख लें । इस बारे में मैं अपना सुझाव रखना चाहता मेरा सुझाव यह है और फाइनैसं मिनिस्टर साहब से यह अर्ज करना चाहता हूं कि हम हर साल 10– 15 लाख रुपया फ्लड के लिये देते हैं । वह रुपया टाईम के टाईम कर हाँ दिया जाता है । मतलब यह कि फ्लड आने के वक्त ही रुपया दिया जाता है । जहां पर ठोकरें लगी हुई हैं, वहां पर माल ट्रकों से नहीं जा सकता । वहां पर माल बधियों से जाता है । मैं फांइनैस मिनिस्टर साहब से यह अर्ज करना चाहता हूं कि यह रकन कम दी जाती है जब फ्लड आ चुका होता है । मेरा सुझाव यह है कि बजट में ही थोड़ी सी रकम इस मतलब के लिये रखनी चाहिये । मैंने चीफ मिनिस्टर साहब के सामने भी यह प्रस्ताव रखा था । उन्होंने चीफ इंजीनियर को बुलाकर मीटिंग की । मीटिग करने के बाद इसके लिये पहले 5 करोड़, फिर 3 करोड़ और फिर एक करोड़ रुपया फ्लड कन्ट्रोल और ड्रैनेज के लिये रवा । मेरा कहने का मतलब यह है कि अगर शुरू में ही इसके लिये पैसे मिले तो हरियाणा का काम चल सकता है और यह भूमि बच सकती है वरना तो मैं यह बता देना चाहता हूं कि अगर इन्तजाम नहीं हुआ तो कितने ही गांव यू०पी० के अन्दर शामिल हो जायेंगे । हमारे इलाके के अन्दर तो इतनी तबाही हुई है कि अब एक तीसरी जमुना तैयार हो गयी है और वहां सिर्फ 8 एकड़ जमीन बच रही है । अगर 8 एकड़ जमीन में भी पानी आ गया तो तीसरी जमुना

बड़ी जमुना में पड़ जायेगी और सारा इलाका यू ० पी० में चला जायेगा । इसलिये मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि मैंने यह बात सी० एम० साहब से कही थी और उन्होंने कैपरिहन साहब से यह कहा था कि आप खजाने वालों से बात. करो । कल जब मैंने मित्तल साहब से अर्ज की तो मित्तल साहब ने मेरे ख्याल से फाइनैसं से डिप्टी सैक्रेटरी या सैक्रेटरी को बुलाया । वहां पर कैपरिहन साहब भी खड़े थे । तो उन्होंने भी यह कहा कि रुपये का इन्तजाम करो । तो मेरे इलाके की यह जरूरत है । (घंटी) मैं कोई ऐसी बात नहीं कह रहा हूं । मुझे कम से कम दों–चार मिनट तो और मिलने चाहिएं । तो यह जो दिक्कत है दह जिले करनाल की ही नहीं है बल्कि सारे हरियाणा के लिये एक बहुत बड़ा मसला है । इसलिये मैं आशा रखता हूं और अपने फाइनैसं मिनिस्टर साहब से यह कहूंगा कि इस रुपये के देने के लिये कोई हिचकिचाहट न की जाये और अगर इसके लिये रुपया किसी काम से भी बचाकर देना पड़े हमें देना चाहिए ताकि जो हरियाणा की भूमि है, वह बचायी जा सके क्योंकि वहां पर इतना ज्यादा नुकसान हुआ है कि जिसका कोई हिसाब नहीं है । इसलिये मैं फाइनैसं मिनिस्टर साहब से यह रिक्वैस्ट करूंगा कि इसके लिये रुपया इन्हीं दिनों में जल्दी से जल्दी रख दिया जाये वरना यह काम अधूरा रह जायेगा और इसी तरह से हरियाणा का नुक्सान अगले सालों में भी होता रहेगा ।

अब मैं 20 सूत्रीय प्रोग्राम के बारे में कुछ अर्ज करना

चाहता हूं । यह जो इस वक्त 20 सूत्रीय प्रोग्राम चल रहा है, यी एक बहुत अच्छी चीज है और मुझे आशा है कि हरियाणा इसमें भी सबसे आगे रहेगा । इसके अलावा एक चीज मैं जरा सी और रखना चाहता हूं । अब मैंने सुना है कि कालेजों की अपग्रेडेशन पर भी कुछ और पाबन्दी लगा दी है और स्कूलों की अपग्रेडेशन भी कई साल से बन्द पड़ी है । देहातों में कई साल से बिल्डिगें बनी पड़ी हैं लेकिन स्कूलों की अपग्रेडेशन नहीं हुई है । मेरी अर्ज यह है कि अपग्रेडेशन होनी चाहिए । डिप्टी स्पीकर साहिबा, मेरे हल्के में भी स्कूलो की अपग्रेडेशन होनी चाहिए । कालिजों को अपग्रेड करने के लिए पहले सरकार 75 हजार को सिक्योरिटी मांगती थी लेकिन अब उसे दो लाख कर दिया है उसको घटाया जाना चाहिए ।

डिप्टी स्पीकर साहिबा, मैं आपकी मारफत सरकार का ध्यान अपने कस्बे घरौंडा की ओर दिलाना चाहता हूं । वहां पर दो मंडियां है । तीस मील का वह एरिया है और वहां पर पुलिस का पहरा होता है लेकिन वहां पर पुलिस थोड़ी है । पांच–चार आदमी तो बाहर दौरे पर ही रहते हैं । इसलिये मेरी प्रार्थना है कि वहां पर पुलिस की तादाद बढ़नी चाहिए । मैं इतना ही कहकर समाप्त करता हू ।

श्री धजा राम (सफीदों): डिप्टी स्पीकर महोदया, इससे पहले कि मैं कुछ कहूं, सब से पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हू कि आपने मु झे बोलने का टाइम दिया । मित्तल

साहब ने जो हाउस के अन्दर बजट पेश किया है वह बहुत ही अच्छे ढंग से पेश किया है और उसमें हर डिपार्टमैंट के लिए प्रोविजन रखा गया है, चाहे वह ऐजुकेशन का हो, चाहे इंडस्ट्री का हो और चाहे ऐग्रीकल्चर का हो । मित्तल साहब ने ऐग्रीकल्चर और सिंचाई के लिए ज्यादा से ज्यादा रुपया दिया है । ऐग्रीकल्चर या दूसरी बातों के बारे में कहने से पहले मैं हरिजनों को जो प्लाट्स दिए गए हैं उसके बारे में कहना चाहता हू । यह ठीक है कि सरकार ने 1 लाख 48 हजार, 859 प्लाट्स गांवों के अन्दर दिए हैं लेकिन मैं आपकी मारफत सरकार के नोटिस में लाना चाहता हू कि ये प्लाट्स या तो कन्सौलिडेशन के टाईम से आज तक दिए गए हैं या अभी दिए गए हैं और मैं साफ तौर पर बताना चाहता हूं कि मौके पर कब्जा मेरे ख्याल में तीस प्रतिशत को ही मिला है । जो 1 लाख 48 हजार 859 की फिगर दी है, मैं समझता हूं कि यह बातें सिर्फ कागजात में ही हैं । मेरी आपसे प्रार्थना है कि सरकार उसको अमली जामा पहनाए । मौके पर जाकर सही कब्जा दिलाए । कुछ गांवों की बात मेरे नोटिस में है कि जो प्लाट्स दिए गए हैं वे तालाबों के अन्दर, जोहडों के अन्दर या उस जगह पर जहां कि हरिजनों की आबादी तो वैस्ट की तरफ है लेकिन उनको ईस्ट की तरफ प्लाट दिए गए हैं । मैं कहना चाहता हूं कि हरिजनों की आबादी चाहे वह ईस्ट, वैस्ट, नार्थ या साउथ में है उसी तरफ प्लाट दिए जाएं ताकि वह गरीब आदमी अपनी झोपड़ी डाल सकें । मेरी यह भी गुजारिश है कि सरकार उनको कुछ पैसा सबसिडी की शक्ल मेदे ताकि वह गरीब हरिजन

अपने मकान या झोंपडियां बना सकें ।

दूसरी बात मैं फैमिली प्लानिंग के बारे में कहना चाहता हूं । इसमें मित्तल साहब ने बड़ा पैसा रखा है । मैंने यह बात पिछले सैशन में भी कही थी और अब भी कहना चाहता हूं, मेरा सुझाव भी है और मैं सरकार के नोटिस में लाना चाहता हू कि आज हम देख रहे हैं कि चाहे ऐग्रीकल्चर इंस्पैक्टर हो, चाहे बी०डी०ओ० हो, चाहे कोई मास्टर हो, हर आदमी फैमिली प्लानिंग के चक्कर में है । वैसे ठीक है कि फैमिली प्लानिंग होनी चाहिए, लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि सरकार कानून क्यों नहीं बनाती यानी बजाए इसके कि मास्टर, ऐग्रीकल्चर इंस्पैक्टर जिसका काम यह है कि वह गांव में किसान के पास जाए, खेत पर फसल के बारे में जो बीमारियां हैं उनके बारे में बताए, वह फैमिली प्लानिंग के काम में लगा हुआ है । बी० डी० ओ० और तहसीलदार का काम नसबन्दी का नहीं है । यह ठीक है कि सरकारी कर्मचारियों का इसमें कोई दोष नहीं है । सरकार की जो पालिसी होती है, सरकारी कर्मचारियों का काम उसको इम्पलीमेंट करना होता है । मेरी सरकार से गुजारिश है कि अगर सरकार देश को बचाना चाहती है, खुशहाल बनाना चाहती है तो उसको यह कानून बनाना पड़ेगा चाहे आप आज बना लें या दस–बीस साल के बाद बना लें । अगर यह कानून पास नहीं किया जाएगा तो मैं साफ तौर पर बताना चाहता हूं कि जमीन पर तो रहने के लिए कोई जगह मिलेगी नहीं शायद आसमान में ही कोई जगह

ढूढनी पड़े । सरकार ने गांव–गांव में प्राईमरी हैल्थ सैन्टर्ज खोले हुए हैं, अच्छे अस्पताल भी हैं, फण्डज भी काफी प्रोवाइ किए हैं । जो लोग नसबन्दी करवाते हैं उनको पैसा भी दिया जाता है, दवाई भी दी जाती हैं लेकिन कोई भी सरकार ज्यादा देर तक इस खर्चे को बर्दाश्त नहीं कर सकती । अगर हम कानून बना दें तो जो यह खर्चा हो रहा है वह पैसा दूसरे डिवैलपमैंट के कामों पर खर्च किया जा सकता है । मैं ज्यादा न कहते हुए सरकार से गुजारिश करना चाहता हूं कि सरकार इस बारे में जल्दी से जल्दी सोच विचार कर कोई कानून पास करे । इस बारे में जितनी सरकार ढील करेगी उतना ही सरकार का और देश का नुक्सान होगा ।

तीसरी बात मैं ऐग्रीकल्चर के बारे में कहना चाहता हूं । मित्तल साहब, ने ऐग्रीकल्चर के लिए करोड़ों रुपया रखा है । यह ठीक है कि ऐग्रीकल्चर को और इरीगेशन को प्रायरिटी दो गई है लेकिन मेरी इस बारे में कुछ सजैशज हैं और तह यह कि एक तो किसान की फसल की इंशोरैंस होती चाहिए । किसान मेहनत करता है, अपने फूल जैसे बच्चों को, अपने प्यारे बच्चों को चाहे वह पांच साल के हैं या दस सात के हैं सब को लेकर सुबह से लेकर शाम तक खेत में काम करता है । हर आदमी को मेहनत करनी चाहिए, चाहे वह दफ्तर में है, चाहे खेत में है, चाहे वह किसी भी फील्ड में है । जिस तरह हमारे नौजवान हमारे देश की सीमाओं की रक्षा करने में सजग हैं उसी तरह से हरियाणा का किसान सुबह से शाम तक मेहनत करता है और आप जानते हैं कि

जब एक आदमी सुबह से शाम तक मेहनत करता है और उसको उसकी मेहनत का फल न मिले तो उसका दिल टूट जाता है और ऐसा आज किसान के साथ हो रहा है इसमें कोई शक की बात नहीं है । डिप्टी स्पीकर साहिबा, यह ठीक है कि आप किसान को बिजली देते हैं, यह भी हम मानते हैं कि सरकार उनको कर्जे भी देती है । यह तो सरकार का फर्ज है कि वह किसानों को हर तरह की सहूलियतें दे और हर तरह के अच्छे अच्छे काम करे जिन से किसानो की भलाई हो । लेकिन आज जो किसान मेहनत करते हैं, और गेहूं, बाजरा, मकई की पैदावार करते हैं उन की मेहनत के मुताबिक उन गरीब किसानो को उनकी पैदावार के सही भाव नहीं मिल रहे हैं । गन्ने के बारे में तो मेरा रैजोल्यूशन है । (इस समय सभापतियों की सूची में से एक सदस्य राव निहाल सिंह पदासीन हुए) चेयरमैन साहब, इस बारे में मेरे कुछ रुझाव हैं । पहली बात तो यह है कि हरेक किसान की फसल के लिये इंशोरैन्स होनी चाहिये क्योकि फसल बोने के बाद अगर कहीं कोई शरारती आदमी आग लगा दे, या और किसी कारण से फसल की बरबादी हो जाए तो यदि फसल की इंशोरैंस हुई होगी तो किसान को उसका मुआवजा भी मित्र सकेगा और किसान को तसल्ली भी होगी कि उसने जो मेहनत की है, वह जाया नहीं जाएगी । सरकार अगर ऐसा कर दे तो इससे किसानों का हौंसला बढ़ेगा और किसान दुगुनी मेहनत से काम करेगा । अतरू आपके द्वारा सरकार को मेरा यह सुझाव है कि किसान की क्राप इंशोर्ड होनी चाहिए ।

चेयरमैन साहब, दूसरी बात यह है कि किसान जब भी फसल बोये, उसके दो या तीन महीने पहले उसको यह बता देना चाहिये कि आपके गन्ने की, गेहूं की, बाजरे की और मकई वगैरह की जो भी उसकी क्राप हो, का यह भाव होगा ताकि वह गरीब किसान जिस क्राप में उसे इन्कम दिखाई दे, उसी फसल की बुवाई करे । होता क्या है कि ऐग्रीकल्चर प्राइस कमीशन वाले किसानों से हमदर्दी नहीं करते, बल्कि उनसे मजाक करते हैं । कमीशन वालों को आज के युग में जबकि हमारे देश का भार प्रधान मती के कंधों पर है, इन गरीब किसानों के साथ मखौल नहीं करना चाहिये, बल्कि उनकी हर प्रकार से मदद करनी चाहिये । मैं आपके द्वारा सरकार के नोटिस में यह बात लाना चाहता हूं कि किसान की फसल के भाव पहले निश्चित किए जाएं ताकि किसान जो फसल मुनासिब समझे, वही बोये और उसे यह पता लग सके कि जिस की वह बुवाई कर रहा है, उससे उसको अच्छी रिटर्न होगी ।

इससे अगला सुझाव है कि जिस तरह से बड़े बड़े व्यापारियों की बैन्कस के अन्दर लिमिट्स होती हैं उसी तरह से किसानों की भी बैन्कों के अन्दर लिमिटस होनी चाहिये ताकि जब वे चाहें बैन्कस से पैसे निकलवा सकें और जब चाहे जमा करवा सकें । होता क्या है कि अगर टयूबवैल के लिये कर्जा लेना है तो पहले पंडित चिरंजी लाल जी के पटवारी से पीछा नहीं छूटता, कहीं 1000 कहीं 500 रुपये मांग लेते हैं । मेरा कहने का मतलब यह है कि सरकार को इस तरफ ध्यान देना चाहिये जिससे किसान

के टाईम की बचत भी हो और पैदावार बढ़ाने में उसका हौसला भी बढ़े । एक फाउंडेशन सीड कारपोरेशन है, उनकी तो न ही पूछो तौ अच्छा है, बुरी हालत है । चाहे कोई कारपोरेशन हो, मैं कह रहा था सीड के बारे में कि सीड 150 रुपये की आफर हुई है, 4,32 रुपये किलो के हिसाब सें सीड मिला है । एक डी० ए० पी०, फिर यूरिया, सुपर फासफेट और दूसरे बाद 600 रुपये की पड़ जाएगी । तो 20 रुपये फी किल्ले के हिसाब से दस बाही 200 रुपये तो यह हो गया, 140 रुपये फी एकड़ का पानी का खर्चा हो गया, उसके बाद सपरे के लिये कम से कम 10 रुपये खर्च आता है । कहने का मतलब यह है कि आज किसान को भाव 150 रुपये प्रति क्वींटल मिलेंगे और उसका खर्चा हुआ है 200, 225 रुपये प्रति क्वींटल । तो मेरा कहने का मतलब यह है कि 150 रुपये पर सरकार लेगी, सरकार ज्यादा से ज्यादा 25 रुपये मुनाफा ले जिससे अफसरों की इज्जत भी रह जाएगी, 50 रुपये मुनाफा ले लो । सीड 200 रुपये में क्यों नहीं दे सकते, क्या वजह है?

चेयरमैन साहब, एक और सुझाव है कि ट्रैक्टरों की कीमतें कम होनी चाहिये कोई भी ट्रैक्टर ले लो, सभी की कीमतें बढ़ी हैं । फोर्ड को ले लो, पहले 32 हजार, थी, 32 से 34 हजार हुई, फिर 40 हजारहुई । धीरे धीरे बढ्ती गई फिर 55 हजार हुई और अब मैंने सुना हे कि पहली जनवरी से 61 हजार कर रहे हैं । एक तरफ किसानों की भलाई की बात को देखकर कहते हैं कि

भाव नीचे आ रहे हैं और दूसरी तरफ ऐग्रीकल्चर की इम्पलीमेन्ट्स के भाव पांच गुना बढ़ रहे हैं । चेयरमैन साहब, अगर किसान खुशहाल होगा, तोदेश खुशहाल होगा, किसान के चेहरे पर रौनक आएगी तभी देश का नाम ऊंचा होगा और देश के चेहरे पर रौनक होगी । अतरू इन सब बातों का ध्यान करते हुए ट्रैक्टर्ज के रेट्स वगैरह कम किये जाएं । खाद के भाव के साथ, डीजल के भाव और मोबिल आयल के भावों को कम किया जाए । चेयरमैन साहब, जिन इलाकों में फ्लडज आए हैं, सरकार को उस इलाके की तरफ ध्यान देना चाहिये । सफीदों में 25–30 गांवों की बहुत बुरी हालत हो गई है और वहां कोई फसल नहीं हो रही है । मेरी सरकार से गुजारिश है कि वहां से जो आबयाना लिया जाता है वह माफ किया जाए । और आगे के लिये सरकार ऐसे इलाकों के लिये, जहां पर हर साल फ्लड के कारण नुकसान हो जाता है, कोई प्रबन्ध करे ताकि लोगों का फ्लड से बचाव हो सके और लोग खुशहाल हो सकें । चेयरमैन साहब, एक बात मैं और ट्यूबवैल्ज के कनैकशंज के बारे में कहना चाहता हूं कि ट्यूबवैल्ज के लिए किसानों ने बैंकों से कर्जा लिया और सिक्योरिटी भी भर दी, टैस्ट रिपोर्ट भी हो गई लेकिन फिर भी डेढ़–डेढ़, दो–दो साल से केस. पैंडिंग पड़े हैं और उनको कनैक्शन नहीं मिले जबकि दूसरी तरफ लैड मार्गेज बैक वाले किश्तों की वसूली के लिये जीप लिये फिरते हैं । किश्त वह कहां से दें, कनैकशन तो उसे मिला नहीं । किश्त के अलावा उसके ऊपर ब्याज भी पड़ रहा है । तो चेयरमैन साहब, मैं आपके द्वारा सरकार से प्रार्थना करना चाहता हूं कि वह चाहे

कहीं से भी कंडक्टर और तार वगैरह का इन्तजाम करे जल्द से जल्द तीन या छरू महीने के अन्दर अन्दर सारे हरियाणा में किसानों को ट्यूबवैल्ज के कनैकशंज दे दे ।

चेयरमैन : आप वाइंड अप करें, अपिका टाईम हो चुका है ।

श्री धजा राम : चेयरमैन साहब, मैं तो पहले बिल्कूल ही नही बोला हूं । तो मै एक गुजारिश और करना चाहता हूं कि करनाल जिले से 55 गांव जींद जिले में आये हैं, कुछ गांव सफीदों और नरवाना तहसीलों में चले गये हैं लेकिन उनके इलैक्ट्रिसिटी डिविजनों और सब–डिविजन में बड़ा कंफ्यूजन है । किसी का करनाल है, किसी का पानीपत है तो किसी का असंध है । चेयरमैन साहब, जब आप दनोली, मिलकपुर और मूवाना वगैरह के विलेज टूर पर थे तो उस वक्त भी यह डिमांड आपके सामने रखी गई थी । यह मेरी खुश किस्मती है कि मैं बोल रहा हूं और आप चेयर पर हैं । तो आपने उस वक्त एश्योंरैस दी थी कि मैं जाते ही गवर्नमैंट को लिखूंगा लेकिन वह काम अभी तक नहीं हुआ । सरकार से मेरी गुजारिश है कि जो जींद और नरवाने के सब डिविजन हैं ये जल्द से जल्द तबदील किये जाएं ताकि बेचारे गरीब परेशान न हो । मैं कुछ शब्द सफीदों के हल्के के बारे में कहना चाहता हूं । सफीदों के प्राइमरी हैल्थ सैंटर की एक बिल्डिग होती थी उसकी हालत बहुत खस्ता है । किसी दिन बहिन शारदा जी और सरदार हरपाल सिंह जी टाइम निकाल कर उसे

देखने का प्रयत्न करें तो पता चलेगा ।

चेयरमैन : धजा राम जी, आप बहिन और भाई का रिश्ता न करिये, आप आनरेबल मैंबर या आनरेबल मिनिस्टर कहिये । कइयों के रिस्ते और तरह के हैं तो वह सब हाउस में अलाउड नहीं हैं । (हंसी)

श्री धज्जा राम : ठीक है जी, तो चेयरमैन साहब, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वे किसी दिन आकर अगर वहां उसकी हालत देख लें तो अच्छा है । अगली बात मैं वाटर वर्कस के बारे में कहना चाहता हूं । पिछले सैशन में मेरा एक क्वैश्चन आया था जिसके जवाब से पता चला था कि सफीदों तहसील के 35 गांव ऐसे हैं जहां पीने का पानी अच्छा नहीं है । आज आजादी मिले 28 साल हो गये हैं और 28 सालों में इन 35 गावों को पीने का पानी नहीं मिला है । किसी भी गांव में वाटर वर्कस का काम शुरू नहीं हुआ और जो स्कीमें बनाई हैं वे 35– 40 लाख की हैं जिनमें 8– 8 और 10– 10 गांव इकट्ठे कर दिये हैं तो मेरी सरकार से गुजारिश है कि छोटी छोटी स्कीमें बनाई जाएं और अच्छे ढंग से बनाई जाएं ताकि सभी गांवों के लोगों को पीने का पानी मिल सके और उन स्कीमों पर ऐक्सपैसं भी कम पड़े । चेयरमैन साहब, एक बात मैं सड्कों के बारे में भी कहना चाहता हूं । टोडी खेडी से भुसलाने तक वाया वसीनी आप भी मेरे साथ विलेज टूर पर गये थे । मुझे अच्छी तरह से याद है कि वसीनी में उस बुढिया से मैंने कहा था कि ताई आप भी घर आ जाना और नहीं तो साड़ी

ले आना । मैंने मखौल का मखौल और बात की बात कही थी । तो चेयरमैन साहब, मैं आपकी मार्फत सरकार के नोटिस में यह बात लाना चाहता हूं कि भुसलाना सफीदों हल्के का सब से आखिरी गांव है जो करनाल जिले की बाउंडरी के साथ लगता है, इसलिये इस गांव को डबल लिंक दिया जाना बहुत जरूरी है ।

चेयरमैन : That is all आपको बोलने के लिये आगे बहुत मौके मिलेंगे फिर बोल लेना । मित्तल साहब, आप कब बोलेंगे और कितना टाईम लेंगे?

वित्त मंत्री (श्री राम सरन चन्द मित्तल) : मैं 15– 20 मिनट से ज्यादा नहीं लूंगा ।

चेयरमैन : ठीक है, चौधरी धजा राम जी आपका टाईम हो चुका है इसलिये आप तशरीफ रखें ।

श्री धज्जा राम : ठीक है जी, धन्यवाद! आपकी यही मर्जी है तो मैं बैठ जाता हूं ।

चौधरी अब्दुर रजाक खां (फिरोजपुर झिरका) : मोहतरिम चेयरमैन साहब, कल से हरियाणा के बजट 1976– 77 पर बहस हो रही है । जरायती मकासद के लिये अपने वजीरे खजाना ने काफी रकम इसमें रखी है लेकिन मैं आपकी मार्फत वजीरे खजाना से और सरकार से यह कहूंगा कि मेरे इलाके के लिये बहुत पुराने वायदे हैं, उनके लिये इस बजट में कोई रकम नहीं रखी गई । मसलन मेरे इलाके में कोई नहर नहीं है और

वहां खारा पानी है । अरावली पर्वत की एक रेंज है उसकी बैलट में काफी पानी है । अपने पहले मुख्य मन्द्री जनाब बंसी लाल जी ने भी वायदा किया था कि इस इलाके की इस रेंज के साथ साथ सरकारी ट्यूबवैल लगा कर पानी दिया जाएगा और तमाम जमीन को सैराव किया जाएगा । लेकिन मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि इस बजट में उस स्कीम के लिये कोई पैसा नहीं रखा गया । मैं उम्मीद करता हूं कि फाइनैसं मिनिस्टर साहब दूसरे सप्लीमेंटरी बजट में इसको लाकर हमारे इलाके की गरीबी को दूर करेंगे और हमें शुक्रिया का मौका देंगे । इसके साथ साथ जहां आबपाशी की बात है । वहां फ्लडज को दूर करने के लिये भी काफी रकम रखी गई है । जनाब चेयरमैन साहब, मेरा इलाका फिरोजपुर झिरका और नूह है इन दोनों में राजस्थान के फ्लड का पानी आकर काफी तबाही करता है और ऐसे डिप्रेशंज हैं कि अगर उनमें पानी भर जाए तो निकलता ही नहीं । अरावली बंध से और कामडा बंध से थोड़ी सी रिलीफ मिली लेकिन ऐसी रिलीफ नहीं मिली कि उससे तमाम इलाके की जमीनें जो डिप्रैशन से परेशान हैं, जिनमें बीज नहीं डलता, उनमें बीजाई हो सके । कुछ जमीनें ऐसी हैं जिनमें आज तक पानी पड़ा है । एक बनारसिया गांव है वहां पानी खड़ा हुआ है, रीचट एक गांव है वहां भी पानी खड़ा हुआ है इनके बीच में और छोटे छोटे गांव पड़ते हैं जैसे उमरा है, वजीदपुर है और सुजाकपुर है इनमें भी पानी खड़ा हुआ है । इसके आगे चल कर पुनहाना हल्के में एक विकटी गांव है जिसकी आबादी भी पानी में दबी हुई है । सरकार ने और अपने आज के

मुख्य मन्त्री जी ने भी उस गांव का विजिट किया और राजस्थान सरकार से बात की लेकिन वह बात कामयाब नही हुई । जहां तक उसकी आबादी को गांव से बाहर मुन्तकिल करने की बात है इसमें तो थोड़ी सी मदद दी है लेकिन उसकी आबादी को ही नहीं बल्कि उस जरई जमीन को भी फ्लड के पानी से निकालने का बन्दोबस्त करना चाहिये और यह जल्द करना चाहिये क्योंकि मेरे इलाके में इस वजह से बड़ी परेशानी है । इसके साथ साथ विकटी के पास में जो और गांव हैं उनकी जमीनें भी काश्त के लिये आज तक काबिल नहीं हैं । एक गांव मुबारिकपुर है जिसे वहां लोकल जबान में राउल की कहते हैं, एक बिसर है और एक पुनाना है और एक पटाखपुर है । इन इलाकों में आज तक ऐसी जमीनें हैं जिनमें खरीफ और रबी की फसल की बीजाई नहीं हो सकी और उनकी यह हालत आज से नहीं बल्कि उनकी हालत 1963 से अब तक चल रही है । उन गांवों के लोगों ने अपनी जमीन का पेशा छोड़ कर और बहुत से लोग जो जमींदारा न करने को बर्दाश्त नहीं करते थे, उन्होंने अपनी आबादी छोड़ कर, अपने पेशे छोड़ कर बच्चों समेत फरीदाबाद, बल्लभगढ और इधर के जो बड़े बड़े शहर हैं गुडगांव और दिल्ली उनमें मजदूरी का पेशा अख्तियार कर लिया । उनको कई कई साल तो अपने गांवों को देखे हो गये हैं । तो मैं इस बारे मैं अर्ज करूंगा कि उस इलाके की गुरबत को देख कर, इनडैटिड– नैस को मिटाने की गर्ज सेइन फ्लडज के लिये पहली फुरस्त में हरियाणा सरकार तवजुह दे और फाइनैसं मिनिस्टर साहब अपने सप्लीमेंटरी बजट में इस बारे में प्रोवीजन

रखें और उस इलाके को अभी से इस परेशानी से निजात दिलाने के लिये काम शुरू करवा दें । पिछली बार यानी गये साल हमारे ड्रेन के महकमे के लोग और फ्लडज डिपार्टमैंट के लोग तथा कैनाल्ज वाले लोग जब जीप लेकर जाते थे तो जवाब यह देते थे कि इस बारे में हमारे पास फंडज नहीं हैं । हमें बड़ा अफसोस होता था कि यह शिकायत जो दस साल से लगातार चरनी आ रही है उसके लिये सरकार ने बजट में पैसा नहीं रखा, प्रोवीजन नहीं रखा । यह तो मोटी मोटी दिक्कतें थीं कुछ छोटी छोटी दिक्कतें और हैं । चेयरमैन साहब, हमारे यहां जिन लोगों ने कर्जा लिया हुआ था अपने देहाती साहुकारों से, उनके लिये परेशानी हो गई । सरकार की तरफ से कर्जा मुलतवी जरूर हुआ है लेकिन माफ नहीं हुआ । अब इससे उनमें एक दहशत फैली हुई है कि इस साल का भी सूद लगेगा । तो यह जो मुलतबी हुआ है यह उलटा बोझ हो गया । मैं यह अर्ज करूंगा कि उनके आल्ट्रेनेटिव के लिये बन्दोबस्त किया जाए ।

चेयरमैन : आपने चीफ मिनिस्टर साहब को नहीं सुना? उन्होंने कहा था कि इसे माफ करने का कानून हम बना रहे हैं ।

चौधरी अब्दुर रजाक खां : अगर मैं गल्ती नहीं कर रहा तो चेयरमैन साहब, देंने जो कहा है वह इस राशि के सूद के बारे में कहा है । मेरा इशारा इस बात की ओर था ।

चेयरमैन : जब असल ही माफ करने का कानून बना रहे

हैं तो फिर यह सूद वाली बात कहां रह गई?

श्री गुलाब सिंह जैन : आप लोगों को समझायें कि वे न दें ।

चौधरी अब्दुर रजाक खां : लोग दहशत के मारे दे रहे हैं । तो मैं अर्ज करता हूं कि यह जो बजट है यह बीस नुकाती प्रोग्राम के मुताबिक तैयार होना चाहिये । दावा तो इस बात का किया जा रहा है कि यह उसके मुताबिक ही तैयार हुआ है लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि बहुत सी बातें ऐसी हैं जिनको इस बीस नुकाती प्रोग्राम की रोशनी नहीं मिली है जैसे कि नशाबंदी की बात है । कोई सरकार नशाबंदी न करके टैक्स तो ले सकती है और अपनी आमदनी में इजाफा कर सकती है लेकिन जो लोग हैं उनका अख्लाक पस्त हो जाता है और आप जानते हैए कि पस्त अख्लाक के लोग देश की तरक्की करने में देश को ऊंचा उठाने में कोई मदद नहीं कर सकते । नशाबंदी न होने से जहां अख्लाक पस्त होता है वहां इससे ला ऐंड आर्डर का मसला भी पैदा होता है क्योंकि जरायम की बहुतात हो जाती है । हमारे देश की प्रधान मली कहती हैं कि देश में नशा बंदी होनी चाहिये और देश की जनता भी चाहती है कि नशाबंदी होनी चाहिये । तो जहां और कई कामों में हमारा हरियाणा पहल करता है वहां इस बात में भी पहल करके इस बात का एलान करे कि नये साल में स्टेट में कहीं भी शराब के ठेके नहीं देंगे ताकि इससे हमारी देश में मशहूरी भी हो कि हम ने देश को लीड दी है और लोगों का अख्लाक भी

ऊंचा हो । आज हजारों केस नाजायज शराब के कशीद करने के पकड़े जाते हैं, सैकड़ों कत्ल के केस शराब पी कर होते हैं, हजारों केसिज शराब के नशे में मार पीट के डकैती के और रेप के होते हैं और कई किस्म के दूसरे जरायम शराब की लानत की वजह से होते हैं । मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि ठीक है कि सरकार को शराब से आमदनी होती है लेकिन जितनी आमदनी होती है उतना ही खर्च भी इन जरायम की रोक थाम के लिये, ला ऐंड आर्डर मेनटेन करने के लिये और पुलिस भारी तादाद में रखने पर खर्च होता है । तो फिर ईस आमदनी का क्या फायदा? अगर ला ऐंड आर्डर ठीक होगा और दूसरे जरायम नहीं होंगे और लोगों का अख्लाक ऊंचा होगा, चाल चलन अच्छा होगा और लोगों का मजाज अच्छा होगा तो इतनी भारी पुलिस और दूसरा ला ऐंड आर्डर कायम रखने का अमला फैला रखने की जरूरत नहीं रहेगी जिससे खर्च में कमी होगी । इसलिये मैं सरकार से अर्ज करूंगा कि वह नशाबंदी करे और इस नये साल में शराब के ठेकों के लाइसैस किसी को न दे । चेयरमैन साहब, हमारे हरियाणा मैं कुछ अकलीयतें हैं और उनके बारे में इस बजट में गुन्जायश नहीं रखी गई है । हरियाणा में एक अकलीयत मुसलमान हैं । इस बीस नुकाती प्रोग्राम के तहत और प्रधान मंत्री साहिबा के मन्शा के मुताबिक उर्दू की तालीम काफी मायने रखती है । मैं गुजारिश करुंगा कि हमारी यदु उर्दू जबान बहुत ही मीठी और प्यारी कबान है । यह जबान इज्जत, अदब, मुहब्बत, मरव्वत और शऊर वाली जबान है जिसे कि हिन्दुस्तान का हर फर्दोंबशर समझता है लेकिन

इस तरक्की के लिये इस बजट में गुंजायश नहीं रखी गई है । मैं सरकार से अर्ज करता हूं कि इस जबान की तरक्की के लिये खास फंडज रखे जायें और हर स्कूल में उर्दू टीचर्ज मुहैया किये जायें उर्दू जबान वह जबान है जिस ने हमारी जंगे आजादी में नाकाबले फामोश खिदमात सर अंजाम दी हैं । जंगे आजादी के वक्त इस जबान के अशआर लोगों में जोशो खरोश दिलाते थे । ऐसे ऐसे शेअर हैं जिन से हर कोई झूम उठता था जै–से कि यह शेअर है

हिन्दियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की

तरता लंदन तक चलेगी तेरा हिन्दुस्तान की ।

फिर आप यह शेअर मुलाहिजा फरमायें

सारे जहां से अच्छा हिन्दुस्तान हमारा ।

हैं हम यत्न है हिन्दुस्तान हमारा ।

इस तरह के लामिसाल अशआर हैं जो हमें आजादी की तरफ ले जाते थे और जिन को बोल बोल कर आजादी के दीवाने जंगे आजाद के मैदान में उतरते थे । आज हमारे बच्चे जो उर्दू नहीं भी जानते हैं रेडियो पर उर्दू प्रोग्राम को बड़े शौक और जौक से सुनते हैं । तो मैं वजीर साहब से कहूंगा किं उदइऊ जबान की नश्वोनुमा के लिये बजट में या सप्लीमैंट्री बजट ला कर काफी फंडज रखें और हर स्कूल में उर्दू का टीचर रखने का प्रोविजन करें । इसके अलावा मैं अर्ज करता हु कि हम अकलीयतों के कुछ

त्योहार हैं और हमारे निहायत मुतबर्रक कौमी त्योहार हैं । हरियाणा में हमारी 6 लाख की आबादी है । हमारे ऐसे ऐसे मशहूर त्योहार हैं जो 14 सौ सालों के चले आ रहे हैं । ईदउल्जुहा है जिसकी न दफ्तरों में और न स्कूलों में छुट्टी होती है । इसी तरह से न मुहर्रम की न मीलाद उल्नबी और न ही शब बरात की कोई छुट्टी. मनाई जाती है । कम से कम इन त्योहारों की जो नैशनल लेवल पर मनाये जाते हैं जैसे कि यह चार त्योहार मैंने बताये हैं छुट्टी होनी चाहिये । तो मैं सरकार से अपील करूंगा कि इस तरफ तवज्जुह दे कर इन चार त्योहार को छुट्टियों कीं फहरिसत में शामित किया जाये । अब पीने के पानी की सप्लाई के बारे में सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं । हमारे पहले चीफ मिनिस्टर साहब ने इसी हाउस में वायदा किया था कि जिन गांव के आबनोशी के कुये हमारे उस बंध की कद में आ गये हैं उन गांव में पीने का पानी सब से पहले मुहैया करने का इन्तजाम किया जायेगा और प्रायर्टी बेसिज पर वाटर सप्लाई की स्कीम को चलाया जायेगा लेकिन आज तक वह वायदा पूरा नहीं हुआ है और हमारे इन गांव के लोग पीने के पानी से महरूम हैं । चार महीने बंध में जुलाई से लेकर सितम्बर तक पानी भरा रहता है और इन पांच सात गांव के लोग दूर दूर से, दूसरे गांव से पीने का पानी लातें हैं जिमसे उनको भारी तकलीफ का सामना करना पड़ रहा है । मैं सरकार से अर्ज करता हूं कि जैसे कि पहले वायदा किया जा चुका है इन गांव में इसी साल पीने का पानी मुहैया किया जाये ताकि हमारे पहले चीफ मिनिस्टर साहब का वायदा भी पूरा हो

जाये और लोगों को पीने का पानी भी मिल जाये । हमारे यहां डेरी डिपार्टमैंट ने दूध के बारे में चिल्लिंग सैटर खोले हुए हैं । इसके अलावा वहां पर डालमिया फर्म की भी दूध लेने की एजैसीज हैं और वह भी दूध लोगों से लेते हैं । चिल्लिग सैटंर्ज में जो डेरी वालों के हैं, सरकार के हैं उन में तो 150 रुपये फी क्विटल के भाव पर दूध लिया जाता है लेकिन उसके मुकाबले में डालमिया फर्म की एजैसी वाले 190 रुपये के भाव पर दूध लेते हैं । जब यह बात हो तो आप अंदाजा लगायें कि सरकारी स्कीमों से लोगों को कितना फायदा होता है । सरकार तो दूध के कम पैसे देती है लेकिन प्राइवेट फर्म वाले ज्यादा पैसे देते हैं । इससे लोगों में बहुत नाराजगी पाई जाती है । या तो सरकार की तरफ से ऐसे प्राइवेट लोगों को वहां दूध लेने से बंद करना चाहिये या फिर उनके मुकाबले का ही दूध का भाव रखा जाये । एक और बात है जिस का इस हाउस मैं बहुत चर्चा है और वह है फैमली प्लानिंग की बात । बहुत सारे मैंबर साहिबान जिनको मैं अकलमंद समझता हू उन्होंने कहाकि सरकार को कानूनी तौर फैमली प्लानिंग करनीचाहिये और सैंटर की सरकार से सिफारिश करनी चाहिये कि वह इस बारे में कानून बनाये । मैं गुजारिश करूंगा कि वह इस मामला पर दिल से गौर करे । अगर आप पिछले दस साल के आबादी के आदादोशुमार को देखें तो आपको पता लग जायेगा कि इतनी आबादी कितने दिनों से बढ़नी शुरू हुई है (घंटी) चेयरमैन साहब, मुझे गवर्नर साहब के ऐडैस पर भी बोलने के लिये टाईम नहीं मिला है इसलिये मेरी गुजारिश है कि मुझे ज्यादा टाईम दिया

जाये ताकि मैं अपने हलका के लोगों की तकलीफ सरकार के ध्यान में ला सकूं ।

चेयरमैन : आप दो मिनट में वाइंड अप कर दें ।

18.00 बजे

चौधरी अब्दुर रजाक खां: ये निजाम कुदरत ने बनाए हैं, और नुक्सान के नहीं हैं । बावजूद इस बात के हकूमत करोड़ों रुपया इस मकसद के लिए खर्च कर रही है । इतना रुपया खर्च करने के बावजूद भी 1966 से लेकर 1975 तक हमारी आबादी की तादाद 33 लाख बढ़ चुकी है आबादी को रोकने की कोशिशों के बावजूद भी हमारी आबादी हर साल 6–7 लाख बढ़ जाती हैं । मैं बरसरे हकूमत से गुजारिश करूंगा कि फैमिली प्लानिंग के वास्ते आवाम को मजबूर न किया जाए और इस सिलसिले में कानून बनाने के लिए कोई सिफारिश न करें और मरकजी सरकार कुदरत के असूलों में दखलंदाजी का मजूम न बने । यहाइसान की खुराक का मसला पेश छउ, यह कोई खास मसला नहीं है । मखलूक सुबह उठती है और सारा दिन चर कर शाम को हो जाती है, वह भी तो किसी न किसी जरिए से अपना गुजारा करती है । कुदरत उसकी मदद करती है । तो हमें कुदरत के भरोसे पर यकीन करके आगे चलते रहना चाहिए । सब गुजारा करते हैं, किसी ने भूख से मौत नही पाई, अगर कोई कहता है तो गलत कहता है, मैं इस बात पर यकीन नहीं कर सकता । जब चींटी भूख से नहीं मरती,

बड़े से बड़ा हाथी भूख से नहीं मरता तो इन्सान कैसे मर सकता है? सरकार ने सरकारी मुलाजमों पर फैमिली प्लानिंग पर अमल करने के लिए जो पाबन्दी लगाई है उसको खत्म कर दिया जाए और उनकी इस अनर्जी को डिवैल्पमेंट के कामों में कारगर इस्तेमाल किया जाए । इस फैमिली प्लानिंग के नाम से पटवारियों से पचास पचास रुपया लेते हैं और इस रकम का कोई हिसाब नहीं होता । फैमिली प्लानिंग बहुत से आफिसरों की जेबें भरने का जरिया बना हुआ है । (घंटी)

चेयरमैनः आपके दो मिनट पूरे हो गए हैं ।

चौधरी अब्दुर रजाक खां : अभी खत्म कर रहा हुं, जनाब । हमारे इलाके में आगरा कैनाल चलती है । उसकी हालत यह है कि उसमें पानी कभी नहीं आता क्योंकि उस में सिल्ट है, वह सिल्ट से भरी हुई है, इसके बारे में मैंने पहले भी कहा था और पहले मुख्य मन्ड़ी ने यह बात यू ० पी० सरकार से चलाई थी लेकिन उस बात का कोई असर नहीं हुआ । मैं चाहूंगा कि मौजूदा मुख्य मन्त्री और यह सरकार इस नहर का मुआवजा यूं ० पी० सरकार को देकर इसे अपने कब्जे में ले ताकि हम उसका पानी' इस्तेमाल कर कर्के । (घंटी) मैं वजीरे आजम खजाना से दरख्वास्त करूंगा कि वे इसका मुआवजा देकर नहर को अपने कब्जे में कर लें ।

वित्त मंत्री (श्री राम सरन चन्द मित्तल): सभापति

महोदय, इस बजट पर दो रोज से बहस हो रही है और इके मेजर प्वांयट्स के ऊपर मुख्य मन्त्री जी ने विस्तारपूर्वक जवाब दे दिया है । मैं कुछ थोड़ी सी बातें अर्ज करने के लिए खड़ा हुआ हूं । जहां तक बजट का ताल्लुक है, मुझे इस बात की बड़ी खुशी है कि माननीय सदस्यों ने इसका स्वागत किया है । यह स्वागत हमारे दल के साथियों ने ही नहीं किया, बल्कि सामने बैठने वालों ने भी खुले शब्दों में स्वागत किया । दरअसल बजट बनाने में अबकी बार एक खास बात यह रही कि इस में बहुत साधारण भाषा का प्रयोग किया गया, कोई बम्बास्टिक लैग्वेज इस्तेमाल नहीं की गई । भाषा का प्रयोग रीयलिस्टिक तरीके से किया जिसको हर एक आदमी समझ सकता है कि इस में क्या क्या मांग की । 1975–76 की जो कारगुजारी है वह भी इस में है और 1976–77 की जो प्रपोजल्ज हैं, उन के अनुमान भी इसमें रखे गए हैं । इसलिए इस में कोई ऐसी बात नहीं है जो समझ न आए । इसमें मैंने यह बात देखी है कि किसी भी सदस्य ने, खासकर विरोधी दल के सदस्यों ने, बजट प्रपोजल्ज की कोई खास नुक्ताचीनी नहीं की है । 20–प्वांयट प्रोग्राम पर तो कहा लेकिन जहां तक बजट प्रपोजल्ज का सवाल है, उसके बारे में किसी ने नुक्ताचीनी नहीं की और न ही कोई ऐसी बात कही जिससे यह मालूम पड़े कि बजट में उलट–पुलट किया है । बजट में बतलाया गया है कि इतना घाटा है । इतना अब है और इतना पहले था, सरकार मुलाजिमों को दो किस्तें दे रही है, इससे इतना घाटा बढ़ जाएगा, यह सब कुछ बताया हैऔर यह बजट रयलिस्टिज तरीके से तैयार किया

गया हए । हमारे कुछ साथियों ने जो सामने बैठने वाले हैं, उन्होंने देहाती जनता के बारे में, खास कर किसानों की हालत पर बड़ी हमदर्दी प्रकट की हए और कहा कि कोई खास तरक्की नहीं हुई, यानी उनकी हालत नहीं सुधरी । मैं उनका ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हू कि गरीबी हटाना एक रोज का काम नहीं है न ही एक साल का काम है । अगर आप इतिहास के पन्ने उलटे तो पाएंगे कि जब यहां पर मुगल बादशाहों, सुल्लानों की हकूमत थी तो उस वक्त के एक फ्रैच ट्रैवलर ने लिखा है कि Tillers fo the soul the selves hungry but toiling to feed others weavers themselves naked but toiling to cloth others. यह गरीबी उस जमाने से चली आ रही है । उसके बाद अंग्रेजों की हकूमत आई । ठीक है, उन्होंने ठीक तरीके से काम चलाया लेकिन हमारे देहात रोज–ब–रोज वीक होते गए । (इस समय श्री अध्यक्ष पदासीन हुए) महात्मा गांधी की जब ट्रायल हुई तो उन्होंने इम बात पर खास स्ट्रैस किये था कि अंग्रेज हकूमत के अन्दर हमारा देश बहुत ज्यादा गरीब हुआ है और खास तौर से देहाती असैट्स, देहाती वल्थ मुल्क से बाहर जा रही है । पैरिस, लंडन जो बड़े बड़े शहर हैं, वे सब हिन्दुस्तान के बलबूते पर थे । उसके बाद अब क्या हालत है, आप खुद देखते हैं । यह बात तो नहीं है कि हम लोगों की हालत अमरीका और इंगलैड के बराबर हो गई है लेकिन रोज–बरोज सरकार सिंसीयरिली अच्छी हालत बनाने की कौशिश कर रही है । रहन–महन के अन्दर, पढ़ाई के अन्दर. मकानों के बारे में, हर बात के अन्दर आमूर दोखेगे, कर तरक्की ही तरक्की

हो रही है । किसानों के बारे में करोकोडाइल टीयर्ज बहाना ठीक नहीं यह तो रसमी रिवाज हो गया है । इसके सिवाये वे कुछ नहीं कहते वि सान' की हालत खराब है । यह सही नहीं है । सरकार ने किसानों के लिए काफी प्रोवीजन किया है । मुझे खुशी है, दौलता साहब ने एक बात कही कि जो बजट बना है यह रूरल बायस है । मैंने अपनी बजट स्पीच के अन्दर भी लिखा है कि बजट रूरल बायस है । विलेजिज की हालत सुधारने के लिए, किसानों की हालत सुधारने के लिए बिजली के ऊपर, सिंचाई के ऊपर, कृषि के ऊपर, हरएक चीज पर रुपया खर्च किया है, सब बातें इलस्ट्रेट की गई हैं । तो यह कहना कि किसानों की हालत खराब है, गलत है । इसलिए यह क्रोकोडाइल टीयर्ज हैं, इन का नोटिस न लिया जाए ।

स्पीकर साहब, हाउसिंग और डेरी डिवैल्पमैंट का महकमा मेरे पास है । कुछ सदस्यों ने गवर्नर ऐड्रैस पर बोलते हुए एतराज किया था कि कुछ मकान ऐसे बने हैं सोनीपत में जिनके अन्दर पानी आ गया । उसके ऊपर पूरी तहकीकात की गई । वहां जमीन का लैवल जो है वह सड़क के लैवल से पांच छः फुट नीचे था । उसको जमीन के ऊपर लाने के लिए काफी मिट्टी डाली गई ताकि लैवल ऊंचा हो जाए । ऐसे केसिज में जब बारिश हो जाए तो डिप्रेशन हो जाना मामूली सी बात है । ऐसा सड्कों पर भी हो जाता है । वह अब दुरुस्त कर दिया गया है और लोगों को जिनको वे मकान अलौट किए गए हैं उनको इस बारे में कोई

शिकायत नहीं है । अब वे सैटिसफाइड हैं । अम्बाला जिला के माननीय सदस्य श्री फूलचन्द जी ने कहा था कि अम्बाला कालोनी के अन्दर मकानात जो नए बनाए गए उनमें लोगों की रिहायश नहीं है बल्कि सरकार के दफतर हैं । इस बारे में मैं उन्हें कहना चाहता हूं कि हाउसिंग बोर्ड ने उन्हें गवर्नमैंट को नहीं दिया है । हाउसिंग बोर्ड ने तो मकानात सिटिजन्ज को अलौट किये हैं और सिटिजन्ज को कब्जा दिया है । अब सिटिजन्ज उन्हें चाहे किसी को किराए पर दें या उन में अपने आप रहें यह उनकी मर्जी है । मैं उन्हें यह भी बताना चाहता हूं एक ऐसी बात भी नहीं होती कि मकानों में दफतर नहीं होते । जहां दफतरों के लिए अलग से जगह नहीं होती वहां मकानों के अन्दर ही दफतर खुलते हैं । चंडीगढ़ में ही आप देखिए लोगों की कोठियों में दफतर खुले पड़े हैं क्योंकि यहां सरकारी मकानात की कमी हए । जहां तक गवर्नमैंट का ताल्लुक है इसमें कोई आपत्तिजनक बात नहीं है ।

कई माननीय सदस्यों ने अपने अपने हल्कों के बारे में कुछ सूझाव पेश किए है । सम्बन्धित विभाग इन सब बातों को देखेंगे और जो हो सकेगा उसको पूरा करने की कोशिश की जाएगी ।

हाउस टैक्स और प्रौपर्टी टैक्स की मर्जर के बारे में' दो तीन माननीय सदस्यों ने कहौ । इस बारे में सरकार पूरी तरह से गौर कर रही है और मेरा ख्याल है जल्दी ही यह हो जाएगा ।

मेवात के माननीय सदस्य श्री अब्दुर रजाक ने उर्दू के बारे में कहा । माननीय शिक्षा मैली जी से बात करने पर पता लगा है कि उर्दू की पढ़ाई के लिए जितनी सहूलियात सरकार की तरफ से हो सकती हैं वे दी जाती हैं । जहां जहां जरूरत है वहां वहां उर्दू के टीचर्ज की पोस्टिग की जाती है ताकि जो बच्चे उर्दू पढ़ना चाहते हों वे उर्दू पढ़ सकें । फिर भी अगर कहीं कोई कमी हो तो माननीय सदस्य शिक्षा मंत्री जी के नोटिस में वह बात ला सकते हैं ।

लाला रुलिया राम जी ने कहा कि उनके यहां की बसें पुरानी हो गई हैं । मुझे ट्रासपोर्ट मिनिस्टर साहब ने बताया है कि दो सौ नई बसें आ रही हैं । उनके आने पर पुरानी बसों की सारी शिकायतें दूर हो जाएंगी ।

श्री ओम प्रकाश गर्ग जी ने कहा कि मिल्क प्लान्ट्स वालों ने गाय का दूध कैना बंद कर दिया है । दरअसल यह बात नहीं है । हमारी डेरीज के अन्दर दूध की फैट कंटैन्टस के ऊपर कीमत दी जाती है । गाय के दूध में इतनी फैट नहीं होती जितनी भैस के दूध में । अगर लोग उसे वहां ले जाएंगे तो नैचुरली कीमत कम वसूल होगी । इसलिए दूध को वहां देना या न देना लोगों के ऊपर निर्भर करता है, हमारी तरफ से कोई इन्कार नहीं है ।

हमारे जगाधरी के माननीय डा० ओम प्रकाश जी ने

कहा कि जगाधरी का हस्पताल जो है वह बनना चाहिए । यह बात ठीक है । मैं मानता हूं कि जगाधरी का हस्पताल जगाधरी के लायक नहीं है लेकिन इस साल का बजट तो अब बन चुका है । फिर भी इस पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करेंगे । अगर इस साल पैसा बच गया तो इस साल बनवा देंगे वरना अगले साल तो इस पर जरूर गौर की जाएगी क्योंकि वाक्या ही वहां इस बात की तकलीफ है ।

स्पीकर साहब, कुछ माननीय सदस्य जाने में ज्यादा उत्सुक हैं, इसलिए मैं ज्यादा समय न लेते हुए दुबारा सदन के प्रति आभार प्रकट करता हूं क्योंकि इसने बजट को अच्छी स्पिरिट में लिया है और उसकी सराहना की है । (तालियां)

Mr. Speaker : The House stands adjourned till 2.00 p.m. tomorrow.

18.14 बजे

(The Sabha then *adjourned till 2.00 p.m. on Wednesday. the 21st January, 1976)